बालाघाट
मंगलवार 08 सितम्बर 2026
भाद्रपद कृष्ण 10 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 345
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

PMG
हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स - 76,132.81
निफ्टी - 23,779.15
सोना - 1,63,004
चांदी - 250000
डॉलर - 94.49

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

सागर में जहरीली शराब से अब तक 15 मौतें, अब 'क्लीनचिट' पर उठ रहे सवाल

-जिन बॉम्बे और सागर गोल्ड ब्रांडों को जांच में पीने योग्य बताया गया, उन्हीं की शराब पीने के बाद मौतों का आरोप

-7 दुकानें की गईं सील और 10 आरोपी लिए गए हिरासत में

सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है। करीब 84 मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी सामने आई है। बंडा और शाहगढ़ तहसील के कई गांवों में हुई इस घटना ने प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सबसे बड़ा सवाल उन शराब ब्रांडों को लेकर है, जिनका सेवन करने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी और मौतें हुईं। रिपोर्टों के मुताबिक, बॉम्बे व्हिस्की और सागर गोल्ड की संदिग्ध शराब को आबकारी विभाग की जांच में एक दिन पहले ही पीने योग्य बताया गया था। हालांकि, इस जांच में फॉरेंसिक परीक्षण नहीं कराया गया था। अब यही पहलू जांच के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है, कि शराब तस्कर कथित तौर पर नकली बॉम्बे ब्रांड करीब 20 रुपये और सागर गोल्ड करीब 30 रुपये सस्ती बेच रहे थे। कीमत अचानक कम होने पर कुछ लोगों ने शराब की गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठाए। आरोप है कि तस्करों ने इसे उसी ब्रांड की 'नई फॉर्मूला' वाली शराब बताकर लोगों को भरोसा दिलाया। प्रारंभिक जांच में शराब में मेथाइल अल्कोहल (मेथेनॉल) की मिलावट की आशंका जताई गई है। नकली शराब की बोतलों पर फर्जी रैपर, सील और क्यूआर कोड इस्तेमाल किए जाने के संकेत भी जांच एजेंसियों को मिले हैं।

सुबह अचानक बिगड़ी लोगों की तबीयत

शनिवार रात कई गांवों में लोगों ने शराब का सेवन किया था। रविवार सुबह बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। मरीजों में उल्टी, पेट दर्द, कमजोरी, सिरदर्द, धुंधला दिखाई देना और आंखों की रोशनी प्रभावित होने जैसे लक्षण सामने आए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में टीमें भेजीं और घर-घर जाकर स्क्रीनिंग शुरू की। प्रशासन ने अपील की है कि पिछले 24 से 48 घंटे में शराब पीने वाले लोगों में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो वे बिना देरी किए अस्पताल पहुंचें।

7 शराब दुकानें सील, 30 लोगों पर एफआईआर

जहरीली शराब मामले में बंडा और विनायका थानों में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। करीब 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तितरवारा क्षेत्र का कथित मास्टरमाइंड अभी फरार बताया जा रहा है। परिजनों और ग्रामीणों के आरोपों के बाद प्रशासन ने बरेठी, बंडा, शाहगढ़, मगरधा, विनायका, दलपतपुर और बरायठा की सात शराब दुकानें सील कर दी हैं। इन दुकानों से नमूने लेकर जांच की जा रही है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गिरी गाज

घटना के बाद सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई भी की है। सहायक आबकारी आयुक्त कीर्ति दुबे, जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते और आबकारी उप निरीक्षक रोशनी उरेते समेत चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सरकार ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

एसीएस ने किया अस्पतालों का निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) दीपाली रस्तोगी सागर पहुंचीं। उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) और जिला अस्पताल का निरीक्षण कर डॉक्टरों को मरीजों की 24 घंटे सघन निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल पुलिस अवैध शराब के निर्माण, नकली पैकेजिंग और सप्लाई नेटवर्क की पूरी कड़ी खंगाल रही है।

खास खबर

स्वतंत्र भारद्वाज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल, मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्रा-कार्यकर्ता के पिता से मारपीट से जुड़ा है। एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह लल्लर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश किए गए भारद्वाज को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। भारद्वाज को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ मारपीट के आरोपों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) और पॉक्सो अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं।

श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 13 की मौत

बागपत। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 7 साल के बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पिकअप में सवार 32 श्रद्धालु राजस्थान के बागड़ धाम (गोगामेड़ी) से बदायूं लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार देर रात करीब 1 बजे पिकअप को एक तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। फिर करीब 10 फीट तक घिसटते हुए सड़क के बीचों-बीच पलट गई। 50 मीटर दूर तक लाशें बिखर गईं। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। घायल श्रद्धालु दर्द से कराहने लगे। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। लोगों ने घायलों को सड़क के किनारे किया। फिर पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया।

पंजाब सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर जताया विरोध

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है, कि नियुक्ति से पहले राज्य सरकार से राय नहीं ली गई, जबकि यह राज्य के प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसी कारण पंजाब सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर केंद्र सरकार के कानून मंत्री के पास विरोध दर्ज कराया है। सरकार के मुताबिक, संवैधानिक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय जरूरी है। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार से

कुछ ना कहना

सत्य निकेतन हादसा

इमारत का मालिक हरिराम बंसल फरार

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने के हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। हादसे के मामले में नामजद इमारत मालिक हरिराम बंसल फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं, जो दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक, हादसे के तुरंत बाद जब टीम हरिराम बंसल के घर पहुंची तो वह वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों की तलाश शुरू कर दी। गुरुग्राम समेत दिल्ली-एनसीआर के कई स्थानों पर दबिश दी गई है। पुलिस उसके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के ठिकानों पर भी नजर रख रही है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा हुआ है।

रेनोवेशन के दौरान पिलर और दीवारों से छेड़छाड़ का आरोप

पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे के समय इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए पिलर और दीवारों में बदलाव किया जा रहा था। इससे इमारत का ढांचा कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद अचानक पूरी इमारत भरभराकर ढह गई और उसके मलबे में कई लोग दब गए। हालांकि हादसे की वास्तविक वजह और किसी तरह की लापरवाही की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

मालिक समेत जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज

सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस के साउथ कैंपस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम बंसल और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब हादसे से जुड़े दस्तावेजों, निर्माण और रेनोवेशन के काम तथा सुरक्षा मानकों की भी जांच कर रही है।

हादसे में 6 लोगों की मौत, 11 घायल

इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल बताए गए हैं। घायलों को इलाज के लिए ऐम्स में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान अभी जारी है। रेस्क्यू टीमें मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। घटनास्थल के ड्रोन से लिए गए वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें मलबे का बड़ा ढेर दिखाई दे रहा है। बचाव दल जेसीबी समेत भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में जुटे हैं। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी हरिराम बंसल की तलाश तेज कर दी गई है और उसे जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला- बिना उचित कारण पति से अलग रहने पर पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं

नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भरण-पोषण को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति से अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता अपने आप नहीं मिल जाता। अदालत ने एक महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को यह साबित करना होगा कि उसके अलग रहने का उचित और वाजिब कारण था।

मामला एक ऐसे दंपती से जुड़ा है, जिनकी शादी वर्ष 1995 में हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान पत्नी अपने बीमार माता-पिता और बहन की देखभाल के लिए मायके चली गई थी। बाद में पति ने उसे वैवाहिक घर वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन वह वापस नहीं आई। पति के अनुसार, वह पत्नी को लेने उसके मायके भी गया था। इसके बाद पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने पति पर प्रताड़ना और क्रूरता के आरोप लगाते हुए अपनी दो बेटियों के साथ भरण-पोषण की मांग की थी।

महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर-4 की तैयारी की सुगबुगाहट

ठाकरे गुट के 14 विधायक एकनाथ के संपर्क में

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी सियासी तोड़-फोड़ की पटकथा लिखी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक मुरजी पटेल ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में राज्य में ऑपरेशन टाइगर-4 होने वाला है। पटेल का कहना है कि शिवसेना ठाकरे गुट के करीब 14 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोकसभा में कुल 9 सांसदों में से 6 सांसद पार्टी से अलग होकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे। लोकसभा में अब शिंदे के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। हालांकि, 14 विधायकों वाली बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

मुरजी पटेल के दावे के मुताबिक, ठाकरे गुट के सांसदों के बाद अब विधायक और फिर नगरसेवक भी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा में 14 का आंकड़ा बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा में ठाकरे गुट के पास 20 विधायक हैं। कानून के मुताबिक, अगर इनमें से दो-तिहाई विधायक एक साथ दलबदल करते हैं, तो दलबदल विरोधी कानून के तहत अलग कानूनी और राजनीतिक स्थिति बन सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने किसी अनजान जगह पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। इसके अलावा, महाविकास अघाड़ी की हालिया बैठक में 60 में से 37 विधायकों की अनुपस्थिति ने भी राजनीतिक अटकलों को बढ़ा दिया।

सीएम विजय ने कहा, पुलिस रक्षक बने.... न कि कोई स्वतंत्र सत्ता का केंद्र

चेन्नई । तमिलनाडु विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दल डीएमके के विधायकों ने हाल ही में हुई हत्याओं का हवाला देकर जोरदार नारेबाजी की और मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। सदन में बढ़ते विरोध के बीच, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपनी सरकार का बचाव कर पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया।

मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग को जनता का रक्षक बनना चाहिए, न कि कोई स्वतंत्र सत्ता का केंद्र। उन्होंने जोर दिया कि कानून सभी के लिए समान है और अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। सीएम विजय ने कहा, मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं, जहाँ तक पुलिस विभाग का सवाल है, उसे अच्छे लोगों का दोस्त और बुरे लोगों का दुश्मन होना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है। जो कोई भी अपराध करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। यही हमारी सरकार की नीति है। पिछले कुछ महीनों में हुई आपराधिक घटनाओं पर सीएम विजय ने कहा कि इन्हें अचानक हुई घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसमें से कई के पीछे पुरानी रंजिश और बदले की भावना जैसे कारण होते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे इन घटनाओं का इस्तेमाल सत्ताधारी सरकार को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं।

ग्रामीण इलाकों में भी 25 दिन में सिलेंडर बुकिंग होगी

अभी 45 दिन में हो रही थी; अब शहर-गांव में एक जैसे नियम

नई दिल्ली। अब गांवों में भी लोग 25 दिन में गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करने का 45 दिन का नियम खत्म कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर रिफिल बुकिंग का अंतराल 25 दिन है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को बताया कि सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस नए नियम को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सुरेश गोपी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दौरान एलपीजी सप्लाई पर दबाव था। इसके चलते 9 मार्च को शहरी इलाकों में रिफिल बुकिंग का अंतर 25 दिन और 12 मार्च को ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था। मंत्री ने कहा कि एलपीजी सप्लाई की मौजूदा स्थिति में सुधार हुआ है और पेंडिंग बुकिंग में कमी आई है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने यह पाबंदी हटा दी है।

ग्वालियर में 20 बांग्लादेशियों के फर्जी भारतीय पासपोर्ट बने

-एसटीएफ की 10 टीमें असम-बंगाल तक नेटवर्क खंगालने में जुटीं; मुख्य गवाह गिरफ्तार

ग्वालियर। देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। ग्वालियर जिले के डबरा में 20 बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनने का मामला सामने आया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने डबरा तहसील के एक ही पते का इस्तेमाल कर इन पासपोर्ट को बनवाया। हैरत की बात यह है कि सभी बांग्लादेशी नागरिकों को डबरा के बौद्ध विहार में रहने वाला बौद्ध धर्म का अनुयायी दर्शाया गया है। सभी पासपोर्ट में एक ही गवाह के हस्ताक्षर हैं। एसटीएफ ने इसी गवाह रियाल चौधरी को गिरफ्तार किया है।

जांच में सामने आया कि गिरोह ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र और 10वीं की अंकसूची समेत अन्य दस्तावेज तैयार किए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट के लिए आवेदन कराया गया। सभी 20 पासपोर्ट में गवाह के तौर पर रियाल चौधरी का नाम दर्ज है।

एक ही पते से बनवाए 20 भारतीय पासपोर्ट

पासपोर्ट जारी होने से पहले स्थानीय पुलिस द्वारा आवेदक के पते, पहचान और चरित्र का भौतिक सत्यापन किया जाता है। ऐसे में डबरा स्थित बौद्ध विहार के एक ही पते से 20 बांग्लादेशी नागरिकों के भारतीय पासपोर्ट बन जाना पुलिस वेरिफिकेशन प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। एसटीएफ अब यह जांच कर रही है कि सत्यापन में जानबूझकर लापरवाही बरती गई या पुलिसकर्मियों की मिलीभगत थी। मामले में संलिप्त कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

5 साल पहले बने थे पासपोर्ट, विदेश यात्राएं भी कीं

एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, ये 20 पासपोर्ट करीब पांच साल पहले बनवाए गए थे।

इसरो का निजीकरण नहीं, सरकारी संस्था ही रहेगी

-चेयरमैन वी. नारायणन बोले- कर्मचारियों की चिंताएं जायज, समाधान करेंगे

बेंगलुरु,(ईएमएस)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चेयरमैन वी. नारायणन ने स्पष्ट किया है कि इसरो का निजीकरण नहीं हुआ है और यह सरकारी संस्था ही है। उन्होंने संगठन के कर्मचारी संगठनों की ओर से उठाई गई चिंताओं को जायज बताते हुए कहा कि कर्मचारियों की आशंकाओं को दूर करना उनकी जिम्मेदारी है।

नारायणन ने यह बात बेंगलुरु स्पेस एक्सपो (बीएसएक्स) के 9वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उनका बयान इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों की ओर से 4 सितंबर को भेजे गए पत्र के बाद आया है। कर्मचारी संगठनों ने इसरो के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कामों को निजी संस्थाओं को सौंपने से जुड़े प्रस्तावों पर जवाब मांगा था।

निजी कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ेगा

इसरो चेयरमैन ने कहा कि देश के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए हर साल करीब 50 लॉन्च व्हीकल की जरूरत होगी। भारत में स्पेस इकोनॉमी और अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, इसरो निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसरो सरकारी निवेश के साथ काम कर रहा है। हालांकि, अंतरिक्ष क्षेत्र के बढ़ते दायरे को देखते हुए देश में एक मजबूत स्पेस इकोसिस्टम और स्पेस इकोनॉमी तैयार करना जरूरी है।

कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने का भरोसा

नारायणन ने कर्मचारी संगठनों की आपत्तियों पर कहा कि उनके साथियों की चिंताएं जायज हैं और उन्हें स्पष्ट करना संगठन की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिया कि कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम करीब 64-65 साल पुराना है और इस समय देश के 56 स्पेस एसेट्स अंतरिक्ष में हैं, जो आम लोगों के लिए उपयोगी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि, देश की जरूरतें इससे कहीं अधिक हैं।

छह साल पहले हुए थे अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार

इसरो चेयरमैन के मुताबिक, करीब छह साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार लागू किए गए थे। इनका उद्देश्य इसरो की क्षमताओं का उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र और स्टार्टअप कंपनियों को सहयोग देना तथा देश के स्पेस इकोसिस्टम का विस्तार करना था। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य इसरो का निजीकरण करना नहीं, बल्कि देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर विकसित करना है। इसके लिए सरकारी संस्था के रूप में इसरो अपनी भूमिका निभाता रहेगा।

डॉक्टरों पर हमला करने वाले नेताओं को तुरंत हिरासत में लो- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों पर लगातार बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ा निर्देश देकर कहा कि डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को तुरंत हिरासत में लें और उन्हें खुले में घूमने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यह सख्त टिप्पणी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई।

शीर्ष न्यायालय कल्याण के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों पर हुए हमले के मामले में म्हात्रे को जमानत शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हालांकि, उनके वकील मुकुल रोहतगी ने बाद में अपनी याचिका वापस ले ली। महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने म्हात्रे की जमानत रद्द करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को तय की गई है, जिसके लिए, अदालत ने नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ठीक एक दिन पहले, पालघर जिले में भी एक अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना सामने आई थी। आरोप है कि दही हांडी उत्सव के दौरान घायल एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के कुछ पदाधिकारियों ने अस्पताल में हंगामा कर मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में व्यक्ति को अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट को थप्पड़ मारते हुए भी देखा गया, जब रिसेप्शनिस्ट ने बीच-बचाव की कोशिश की थी। इस मामले में पालघर पुलिस ने कम से कम 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें शिंदे गुट के कुछ सदस्य भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि 6 जुलाई को ठाणे के शास्त्रीनगर अस्पताल, कल्याण में इस तरह की घटना हुई थी।

कुर्सी नई, चुनौतियां पुरानी, नवागत सीएमएचओ ने संभाली जिले की कमान

पदभार लेते ही डॉ. शत्रुधन दाहिया ने माना- व्यवस्था में रह गई कमी, कमियों की समीक्षा कर उसे दूर करने की कही बात, प्रभावित गांवों पर विशेष निगरानी, स्टाफ और संसाधन बढ़ाने शासन को पत्र

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और हाल के दिनों में आदिवासी अंचल में सामने आए बच्चों की मौतों के बीच सोमवार को जिले को नया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिल गया। मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जिला चिकित्सालय जबलपुर में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ रहे डॉ. शत्रुधन दाहिया ने सोमवार को सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया।पदभार संभालते ही नवागत सीएमएचओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की है। खासतौर पर आदिवासी बाहुल्य और प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ, दवाइयों और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था तथा गंभीर मरीजों के समय पर उपचार को लेकर अब उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पदभार के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक

डॉ. दाहिया ने पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों से परिचय प्राप्त करते हुए विभागीय कामकाज की जानकारी ली और सभी को अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील होकर काम करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग का काम सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए मैदानी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर करना प्राथमिकता

जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की कमी लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ बेड और अन्य संसाधनों की आवश्यकता भी सामने आती रही है।इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नवागत सीएमएचओ ने बताया कि स्टाफ और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है। अब इन मांगों को आगे बढ़ाकर जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं की जरूरत के मुताबिक व्यवस्थाएं मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रभावित गांवों पर रहेगा विशेष फोकस

हाल के दिनों में बिरसा क्षेत्र सहित आदिवासी अंचल में बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने और मौतों के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठे हैं। ऐसे में नवागत सीएमएचओ के लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बड़ी प्राथमिकता होगी।इन क्षेत्रों में बीमारी की रोकथाम, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय अमले की मौजूदगी और गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।

शिशु रोग विशेषज्ञ का अनुभव भी आएगा काम

डॉ. शत्रुधन दाहिया जिला चिकित्सालय जबलपुर में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ रहे हैं। ऐसे समय में जब बालाघाट के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर परिस्थितियां सामने आई हैं, उनका शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में अनुभव विभाग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।अब देखना यह होगा कि नवागत सीएमएचओ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी चुनौतियों को किस तरह समझते हैं और कितनी तेजी से उनके समाधान की दिशा में कदम उठाते हैं।

पूर्व सीएमएचओ के बाद नई जिम्मेदारी

स्वास्थ्य विभाग में हालिया घटनाक्रम के बीच डॉ. दाहिया को जिले की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में उनके सामने एक ओर विभागीय व्यवस्था को संभालने की चुनौती है तो दूसरी ओर प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसा बहाल करने की भी जिम्मेदारी है।पदभार ग्रहण के साथ ही उन्होंने जिस तरह स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर करने तथा प्रभावित गांवों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, उससे आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली में बदलाव की उम्मीद जगी है।

कहीं न कहीं कमी रह गई, उसे पूरा करेंगे-दाहिया

जिले की मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर नवागत सीएमएचओ डॉ दाहिया ने स्वीकार किया कि व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी रही है तो उसे दूर करने की दिशा में काम किया जाएगा। उनका कहना है कि विभागीय स्तर पर जो कमियां सामने आएंगी, उन्हें चिन्हित कर दूर करने का प्रयास किया जाएगा।उन्होंने संकेत दिए कि केवल कार्यालयीन स्तर पर बैठकर व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य केंद्रों और प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा।

जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से 7 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री डी.पी. बर्मन, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुरजीत भारती ठाकुर, बालाघाट एसडीएम गोपाल सोनी, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित

रहे। बैठक में आगामी गणेश उत्सव, दुर्गोत्सव, दशहरा (विजयादशमी), महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, भगवान बिरसा मुंडा जयंती, गुरुनानक जयंती एवं क्रिसमस डे के दौरान कानून व्यवस्था एवं आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अपर कलेक्टर श्री बर्मन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक त्योहार के दौरान पिछले वर्षों की तरह बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं समितियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुरजीत भारती ठाकुर ने गणेश एवं दुर्गा उत्सव समितियों से अपील की कि प्रतिमाओं की स्थापना के लिए उचित स्थान का चयन करें तथा सड़कों पर अनावश्यक गड्ढे न खोदें। साफ-सफाई बनाए रखने के लिए पर्याप्त डस्टबिन की व्यवस्था करने तथा अनावश्यक रूप से तोरण-कतरण आदि न करने के निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी ने सभी से आपसी समन्वय के साथ शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बैठक में आगामी सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के वातावरण में मनाने पर विशेष जोर दिया गया।

अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आज

नक्सल मुक्त बालाघाट में असाक्षरता की चुनौती बरकरार
नक्सल मुक्त बालाघाट में अब भी 47 हजार लोग अनपढ़!

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शिक्षा केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं,बल्कि व्यक्ति को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और अवसरों से जोड़ने का सबसे मजबूत माध्यम है। इसी संदेश के साथ आज 7 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। बात अगर जिले की करें

तो बालाघाट जिले में भी साक्षरता को लेकर अभियान जारी है, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जिले में अभी भी 47 हजार 292 लोग बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं।जानकारी के अनुसार 15 से 75 वर्ष आयु वर्ग के असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 1 लाख 25 हजार 871 लोगों को साक्षरता परीक्षा में सफल कराया जा चुका है। अब शिक्षा विभाग का लक्ष्य मार्च 2027 तक शेष लोगों को भी बुनियादी शिक्षा से जोड़ना है।

आंकड़े बताते हैं चुनौती कितनी बड़ी

वर्ष 2011 की जनगणना में जिले में 1,57,080 लोग असाक्षर चिन्हित किए गए थे। बाद के सर्वे में यह संख्या बढ़कर 1,72,163 हो गई। हालांकि अभियान के बाद अब तक करीब 73 प्रतिशत लोगों को साक्षरता परीक्षा में सफल कराया जा चुका है।वहीं नए सर्वे के अनुसार 47,292 लोग अभी भी अभियान में शामिल किए जाने बाकी हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर जिले के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है।

विद्यार्थी बनेंगे बड़ों के 'अक्षर साथी'

साक्षरता अभियान को गति देने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 'अक्षर साथी' बनाया गया है। विद्यार्थी अपने आसपास रहने वाले असाक्षरों को पढ़ाने में सहयोग करेंगे। इसके लिए उन्हें 20 अंक का प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया है। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस, आजीविका मिशन की दीदियों तथा डीएड-बीएड प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों को भी अभियान से जोड़ा गया है।

परीक्षा पास करने पर मिलेगा प्रमाण पत्र

अभियान के तहत पढ़ाए जा रहे लोगों की सितंबर 2026 और मार्च 2027 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले लोगों को साक्षरता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र पर पंचायत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी होंगे।

लक्ष्य सिर्फ आंकड़ा घटाना नहीं, जीवन बदलना

बताया गया कि साक्षरता अभियान का वास्तविक उद्देश्य केवल सरकारी आंकड़ों में असाक्षरों की संख्या कम करना नहीं है। बुनियादी शिक्षा मिलने के बाद व्यक्ति बैंकिंग, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी को बेहतर ढंग से समझ सकता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर बालाघाट के सामने लक्ष्य स्पष्ट है—47 हजार 292 लोगों तक अक्षर ज्ञान पहुंचाना और मार्च 2027 तक असाक्षरता के इस आंकड़े को शून्य के करीब लाना है।

जल्द ही लक्ष्य को हासिल कर लेंगे- बर्मन

जिला शिक्षा केंद्र डीपीसी श्री बर्मन ने बताया कि शासन से जो लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है उसे लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए टीम तैयार कर दी गई है।सर्वे के आधार पर लोग चिन्हित कर लिए गए हैं जल्द ही उन्हें साक्षर करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि समय सीमा के भीतर ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।

बेहरई-लेण्डेझरी मार्ग की बदहाली से ग्रामीण परेशान, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क

बारिश ने बढ़ाई मार्ग की दुर्दशा, स्कूली बच्चों और राहगीरों के लिए बना दुर्घटना का खतरा, सात दिन में मरम्मत शुरू नहीं हुई तो चक्काजाम की चेतावनी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। बारिश के कारण कई प्रमुख मार्गों की स्थिति खराब हो गई है और जगह-जगह सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं। इन जर्जर मार्गों के कारण ग्रामीणों को रोजाना आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं मार्गों की खराब स्थिति को लेकर अब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित कराते हुए मरम्मत की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में शहर मुख्यालय से लगे ग्राम बेहरई से लेण्डेझरी मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर लोक निर्माण विभाग से तत्काल मरम्मत की मांग की गई है। ग्राम बेहरई निवासी एवं पूर्व उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा नेतलाल ठाकरे ने लोक निर्माण विभाग बालाघाट को ज्ञापन सौंपकर बेहरई से लेण्डेझरी मार्ग की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से विभाग को मार्ग की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि यह मार्ग लंबे समय से खराब स्थिति में है और बारिश के बाद इसकी हालत और अधिक बिगड़ गई है। सड़क पर जगह-जगह बड़े और गहरे गड्ढे हो जाने के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बेहरई से लेण्डेझरी को जोड़ने वाला यह मार्ग स्थानीय लोगों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण रास्ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मार्ग से आवागमन करते हैं। इसके अलावा स्कूली छात्र-छात्राएं भी इसी मार्ग का उपयोग कर स्कूल आने-जाने के लिए करते हैं। सड़क पर बने गहरे गड्ढों और बारिश के कारण इनमें पानी भर जाने से कई स्थानों पर गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए भी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ज्ञापन में बताया गया कि सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों द्वारा पहले भी विभागीय कर्मचारियों को मौखिक रूप से कई बार जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद अभी तक मार्ग की मरम्मत के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश

का दौर जारी रहने के कारण सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यदि समय रहते गड्ढों का भराव और आवश्यक मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में मार्ग से आवागमन और अधिक मुश्किल हो सकता है। नेतलाल ठाकरे ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर बेहरई से लेण्डेझरी मार्ग का निरीक्षण करें और सड़क की वास्तविक स्थिति का जायजा लें। इसके बाद तत्काल गड्ढों का भराव कराने के साथ जहां आवश्यक हो वहां सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके। ज्ञापन में विभाग को सात दिवस की समयसीमा भी दी गई है। मांग की गई है कि सात दिनों के भीतर मार्ग पर मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण उन्हें लंबे समय से परेशानी हो रही है और अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मार्ग की स्थिति को देखते हुए तत्काल मौके पर कार्य शुरू किया जाना आवश्यक है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिवस के भीतर सड़क की मरम्मत का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर इसी मार्ग पर चक्काजाम कर आंदोलन किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि उनका उद्देश्य आवागमन बाधित करना नहीं, बल्कि लगातार खराब होती सड़क की समस्या का स्थायी समाधान कराना है, ताकि क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।

निर्माणाधीन भवन वाले कॉलेज में 22 छात्रों का आवंटन

भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और विद्यार्थियों के आवंटन को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है। सीधी जिले की कुसमी तहसील के भादौरा स्थित आयुष्मान कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज में 22 विद्यार्थियों के आवंटन को लेकर एनएसयूआई ने मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का आरोप है कि जिस कॉलेज के भवन और अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी संस्थान में जीएनएम के 15 और बीएससी नर्सिंग के 7, कुल 22 विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आवंटित किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कॉलेज को विद्यार्थियों के आवंटन से पहले किए गए भौतिक सत्यापन को लेकर खड़ा हो रहा है।

परमार ने सवाल उठाया कि यदि कॉलेज का भवन निर्माणाधीन था और उसकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल मौजूद थे, तो उसे नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता किस आधार पर मिली? इसके बाद विद्यार्थियों को वहां आवंटित करने से पहले निरीक्षण दल ने मौके पर क्या-क्या देखा, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि निरीक्षण के समय भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण, फैकल्टी और क्लीनिकल ट्रेनिंग की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं या नहीं। यदि सभी सुविधाएं मौजूद थीं तो उनका निरीक्षण रिकॉर्ड कहां है और यदि सुविधाएं अधूरी थीं तो विद्यार्थियों को उस कॉलेज में आवंटित करने का आधार क्या रहा?

एनएसयूआई का कहना है कि मामला सिर्फ एक कॉलेज की मान्यता तक सीमित नहीं है। विद्यार्थियों को किसी ऐसे संस्थान में प्रवेश मिलना, जिसकी सुविधाओं को लेकर सवाल हों, उनके शिक्षा और भविष्य पर सीधा असर डाल सकता है। परमार ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था को लेकर हजारों विद्यार्थी परीक्षा, रिजल्ट और मान्यता संबंधी विवादों से प्रभावित हैं। ऐसे में नए विद्यार्थियों को विवादित या संदिग्ध स्थिति वाले संस्थानों में आवंटित किया जाना गंभीर चिंता का विषय है।

एनएसयूआई ने नर्सिंग कॉलेज संचालकों के साथ-साथ मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। संगठन का सवाल है कि यदि कॉलेज की भौतिक स्थिति और सुविधाओं में कोई कमी थी, तो निरीक्षण और मान्यता की प्रक्रिया में उसे क्यों नहीं पकड़ा गया। परमार ने कहा कि कॉलेज की मान्यता से लेकर 22 विद्यार्थियों के आवंटन तक हर चरण की जांच होनी चाहिए। एनएसयूआई ने इस पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जांच में दस्तावेजी प्रक्रिया के साथ मौके पर कॉलेज की वास्तविक स्थिति, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनिकल प्रशिक्षण की व्यवस्था भी जांची जाए, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब मिल सके।

नाम सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शालिनी भगत पिता श्री देवकृष्ण भगत वार्ड न. 05, ग्राम अंसेरा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र. की निवासी हुं।

यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी में मेरी सरनेम(उपनाम) भगत लिखा हुआ है लेकिन मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में सरनेम(उपनाम) भगत दर्ज नही है, जबकि शालिनी और शालिनी भगत उक्त दोनो नाम मेरे स्वयं के है।

अत: मुझे शालिनी एवं शालिनी भगत उक्त दोनों नाम से जाना पहचाना जावें।

वास्ते सूचनार्थ
शालिनी भगत
पिता श्री देवकृष्ण भगत
वार्ड न. 05, ग्राम अंसेरा तहसील वारासिवनी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

कार्यालय तहसीलदार तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट (म.प्र.)

रा.प्र.क्र. 0032/इ-154/2026-27
मौजा निलजी, रा.नि.मं. खमरिया

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका लीला कोल्हेकर पति स्व. कमल कोल्हेकर, जाति महार, निवासी ग्राम निलजी, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा निलजी, रा.नि.मं. खमरिया, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा अपने ससुर गंभीरदास पिता देवाजी का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 (2), म.प्र. मृत्यु पंजीयन 1999 नियम 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त मृत्यु की घटना दिनांक 12.04.1990 मृत्यु स्थल ग्राम निलजी के अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह दिनांक 18.09.2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 07.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

स्थान - लालबर्रा
दिनांक - 08.09.2026

भूपेन्द्र अहिरवार
तहसीलदार
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र.

आवश्यकता है
लड़कों की आवश्यकता है
10वीं पास नो डी फार्मा नो बी फार्मा
मो. 9340308019

जमीन बेचना है
52 डिसमील
बस स्टैण्ड के पास भिलाई रोड गायत्री मंदिर के सामने लांजी
मो. 7611166768

बारबेड वायर (कांटेदार तार)
एवं चेन लिंक जाली
उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

नवागत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.शत्रुधन दाहिया ने पदभार ग्रहण किया

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पर के जिले के नवागत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.शत्रुधन दाहिया ने आज 07 सितम्बर 2026 सोमवार प्रात:11:30 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुँचकर सी. एम. एच. ओ.

बालाघाट का पदभार ग्रहण कर लिया हैं। आप जिला चिकित्सालय जबलपुर में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ थे,पदभार ग्रहण करने के उपरांत डॉ. दाहिया ने कार्यालयिन अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर परिचय प्राप्त किया और अपने-अपने कार्य के प्रति संवेदनशील रहकर कार्य करने के निर्देश दिये।

प्रभारी मंत्री बोले.. बुखार कभी खत्म नहीं होता..! बैगा बच्चों की मौत की संख्या बताये 28

बालाघाट पहुंचे परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ली समीक्षा बैठक, संवेदनशील मामले पर बयान बना चर्चा का विषय

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में बैगा आदिवासी बच्चों की लगातार हो रही मौतों के बीच सोमवार 7 सितंबर को मध्यप्रदेश शासन के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह बालाघाट प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभागीय अधिकारियों और विधायकों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने परसवाड़ा विकासखंड के कुछ जन शिक्षा केंद्रों और स्कूलों में पहुंचकर विद्यांजलि कार्यक्रमों में भी सहभागिता की। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि एक दिवसीय प्रवास के दौरान समीक्षा बैठक में जिले की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने विशेष रूप से पोषण आहार, खाद्यान्न वितरण और बैहर-बिरसा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रणनीति तैयार किए जाने की जानकारी दी। उनका कहना था कि दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों तक सरकारी सुविधाएं समय पर पहुंचाना प्राथमिकता है। प्रभारी मंत्री ने अपने बयान यह भी बताया कि बरसात के समय में बिरसा और बैहर क्षेत्र के सुदूर अंचल में खाद्यान्न पहुचाने की चुनौतियाँ थी, अब बरसात खत्म हो गई है अब दुरस्थ अंचलों में प्राथमिकता के साथ खाद्यान्न पहुचाने का कार्य किया जायेगा।

बैहर-बिरसा क्षेत्र में बच्चों की मौत के मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रभारी मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब तक 28 बच्चों की मौत हुई है। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बच्चों की मौत के आंकड़ों को लेकर पिछले दिनों से अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठनों और विपक्ष की ओर से यह संख्या 31 तक बताए जाने का दावा किया जाता रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बैहर-बिरसा क्षेत्र की स्थिति में अब पहले की तुलना में सुधार आया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों और निगरानी व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि प्रशासन बच्चों की मौत के मामले को लेकर संवेदनशील है और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि लगातार आ रहे मामले पर सवाल में प्रभारी मंत्री का एक बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने और लगातार हालात नही थमने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बुखार कभी खत्म नहीं होता, बुखार सभी को आता है। उनके इस बयान को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। एक ओर बैगा आदिवासी अंचल में बच्चों की मौत का सिलसिला चिंता का विषय बना हुआ है और दूसरी ओर ऐसे संवेदनशील मामले में प्रभारी मंत्री द्वारा बुखार को लेकर दिया गया यह बयान लोगों के बीच चर्चा का कारण बन गया है। हालांकि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार और प्रशासन बच्चों की मौत के मामले को लेकर गंभीर और संवेदनशील है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ पोषण और खाद्यान्न व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना जरूरी है। इसके लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के दौरे के दौरान जहां एक ओर प्रशासन ने क्षेत्र में स्थिति सुधरने का दावा किया, वहीं बैगा बच्चों की मौत का आंकड़ा 28 बताए जाने से मामले की गंभीरता एक बार फिर सामने आ गई है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जमीनी असर कब तक दिखाई देता है और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को समय पर बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जाती हैं।

ड्रोन व ट्रैप कैमरे से रखी जाएगी बाघों के मूमेंट की खबर

अब वन विभाग और कान्हा की टीम ने संभाला मोर्चा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। परसवाड़ा तहसील क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाघों की लगातार हो रही मूवमेंट ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। शेरपार और सिलगी क्षेत्र में बाघ द्वारा चार मवेशियों का शिकार किए जाने के बाद अब लिंगा-चीनी मार्ग पर भी बाघ दिखाई देने से दहशत का माहौल है। मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग और कान्हा नेशनल पार्क की टीम ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग-अलग स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जबकि वन विभाग, वन विकास निगम, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गश्त भी की जा रही है।

दो दिन में चार मवेशियों का शिकार

जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर को ग्राम शेरपार में बाघ ने दो मवेशियों का शिकार किया। इसके अगले दिन 4 सितंबर को सिलगी के कन्हारटोला क्षेत्र में भी बाघ ने दो मवेशियों को अपना शिकार बना लिया। लगातार हो रही इस घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। इसके बाद 5 सितंबर की सुबह परसवाड़ा मुख्यालय से करीब दो किलोमीटर दूर चीनी-लिंगा रोड के पास ग्रामीणों ने एक बाघ को जाते हुए देखा। ग्रामीणों ने मोबाइल से बाघ की तस्वीर भी खींची। लगातार बाघ के मूवमेंट से स्थानीय लोग घबराए हुए हैं जो दहशत में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं।जिसपर अपनी नाराजगी जताते हुए स्थानीय लोगों द्वारा जल्द से जल्द बाघो के मूवमेंट से राहत दिलाए जाने की मांग की गई है।

सूचना मिलते ही पहुंची कान्हा की टीम

बाघ दिखाई देने की सूचना ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग बालाघाट तथा कान्हा नेशनल पार्क की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद दोपहर टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी। इसके बाद 6 सितंबर को लिंगा, पोंडी, धुर्वा और सिलगी सहित आसपास के क्षेत्रों में टीम ने भ्रमण कर बाघ की गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई।

ट्रैप कैमरों से रखी जा रही नजर

वन विभाग द्वारा बाघों की वास्तविक संख्या और उनकी आवाजाही का पता लगाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं।वही जगह जगह से ड्रोन भी, उडाए जा रहे है। कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों के आधार पर बाघों की पहचान और उनकी गतिविधियों का आकलन किया जा रहा है। मौसम साफ रहने पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी करने की बात विभागीय स्तर से कही जा रही है।

एक नहीं, दो से तीन बाघ होने की संभावना

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर सामने आ रही बाघों की गतिविधियों को देखते हुए क्षेत्र में दो से तीन वयस्क बाघों की मौजूदगी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले यह माना जा रहा था कि संभवत: एक ही बाघ भोजन की तलाश में गांवों के आसपास घूम रहा है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार सामने आ रही गतिविधियों के बाद वन विभाग ने निगरानी और बढ़ा दी है।

ग्रामीणों को दी जा रही सतर्क रहने की समझाइश

वन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क कर रही है। ग्रामीणों से कहा गया है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अकेले खेत अथवा जंगल की ओर न जाएं। जरूरी होने पर समूह में जाने और रास्ते में आवाज करते हुए आवागमन करने की सलाह दी गई है। रात के समय संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्त की व्यवस्था भी की जा रही है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी चिंता का विषय

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जिस मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में बाघ की गतिविधियां सामने आ रही हैं, वहां से ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूली बच्चे भी आवागमन करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। इसी को देखते हुए संयुक्त टीम द्वारा गश्त बढ़ाई गई है।

> **एक नजर में**
>
> 3 सितंबर को शेरपार में दो मवेशियों का शिकार।
>
> 4 सितंबर को सिलगी के कन्हारटोला में दो मवेशी मारे गए।
>
> 5 सितंबर, चीनी-लिंगा रोड पर ग्रामीणों ने बाघ को देखा।
>
> 6 सितंबर- कान्हा और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कई गांवों में की गश्त।
>
> ट्रैप कैमरों से बाघों की गतिविधियों पर निगरानी।
>
> दो से तीन वयस्क बाघों की मौजूदगी की संभावना।
>
> मौसम साफ रहा तो ड्रोन से भी होगी निगरानी।
>
> ग्रामीणों से सुबह-शाम अकेले जंगल और खेत की ओर नहीं जाने की अपील।

कान्हा-पेंच कॉरिडोर से सटी है इन गांवों की सीमा

बताया गया कि परसवाड़ा तहसील का बड़ा हिस्सा कान्हा नेशनल पार्क के बफर क्षेत्र और वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके चलते इस इलाके में वन्यजीवों की आवाजाही पहले भी सामने आती रही है। पूर्व में कान्हा से लगे परांपुर गांव में बाघ के घर में घुसने की घटना में एक महिला की मौत हो चुकी है। वहीं खेत गए एक किसान पर भी बाघ हमला कर चुका है। ऐसे में वर्तमान में सामने आ रही लगातार बाघ मूवमेंट को वन विभाग गंभीरता से लेते हुए निगरानी, ट्रैप कैमरा और गश्त के माध्यम से स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

अलग-अलग क्षेत्रों में दिख रही गतिविधि- अशोक मंडलेकर

उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के अध्यक्ष अशोक मंडलेकर ने बताया कि उनके गांव से लगे क्षेत्र में भी बाघ की मूवमेंट देखी जा रही है। धुर्वा, सिलगी, खरपड़िया सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बाघ की गतिविधियां सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले एक ही बाघ होने की संभावना लग रही थी, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों में अलग-अलग स्थानों पर गतिविधियां सामने आने के बाद इसकी जानकारी डीएफओ और सीसीएफ को दी गई हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अब संयुक्त रूप से गश्त की जा रही है।

घबराएं नहीं, सतर्क रहें- डीएफओ

डीएफओ रेशम सिंह धुर्वे ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से अलग-अलग क्षेत्रों में बाघ का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है। कान्हा की टीम के साथ गांवों में भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और गश्त बढ़ा दी गई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अकेले बाहर न निकलें। आवश्यक होने पर समूह में जाएं और आवाज करते हुए आवागमन करें। उन्होंने शेरपार सहित अन्य क्षेत्रों में दो से तीन बाघ होने की संभावना जताई है।

हक के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे मछुआ समाज के लोग

प्रशासन की अनुमति नहीं मिली तो जनपद के सामने डाला डेरा, नौ सूत्रीय मांगों को लेकर दिनभर प्रदर्शन, दो दिन में मांगें पूरी नहीं हुई तो अनशन की चेतावनी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। वंशानुगत ढीमर मछुआ समाज ने अपने हक और अधिकारों से जुड़ी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों का कहना है कि पिछले करीब दो वर्षों से वे आवेदन, निवेदन, जनसुनवाई और विभिन्न स्तरों पर शिकायतों के माध्यम से अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ है। इसी नाराजगी के चलते समाज ने परिवार सहित भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। समाज का आरोप है कि प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर लगातार शिकायतों के बावजूद उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। समाज के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार पत्र और ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कई मामलों में जांच भी हुई, लेकिन जांच के बाद अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आने से समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

ज्ञापन में सहकारिता विभाग के वर्तमान प्रभारी उपायुक्त का प्रभार समाप्त कर निष्पक्ष अधिकारी को जिम्मेदारी देने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई है। इसके अलावा जिला स्तरीय निष्कासन समिति के निर्णय के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई और समितियों के कार्यक्षेत्र में मौजूद विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। समाज ने लालबर्रा ब्लॉक की पांच मत्स्य सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में धारा-12 के तहत संशोधन कर भौगोलिक स्थिति के आधार पर नए और सुसंगत कार्यक्षेत्र निर्धारित करने की मांग की है। इसके साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों की जांच रिपोर्ट राज्य स्तरीय छानबीन समिति भोपाल को भेजकर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई किए जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। समाज ने सामान्य जाति के लोगों द्वारा कहार, ढीमर, सिंगराहा और मांझी जाति के नाम पर कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही वंशानुगत मछुआ जाति की पहचान के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने और मत्स्य नीति 2008 में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर ही मत्स्य सहकारी समितियों में सदस्यता देने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा लालबर्रा ब्लॉक की पांचों समितियों के विसंगतिपूर्ण कार्यक्षेत्रों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने तक पट्टा पुनरावंटन पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्राथमिक राजीव गांधी मछुआ सहकारी समिति बोरी से बिना सूचना अथवा नोटिस के हटाए गए वास्तविक वंशानुगत मछुआरों के नाम उनकी सहमति से पुन: शामिल किए जाने की मांग भी समाज ने रखी है। समाज के लोग सोमवार सुबह लालबर्रा से जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए थे। शेखर जायसवाल ने बताया कि प्रदर्शन की जानकारी प्रशासन को पहले ही दी जा चुकी थी। प्रभारी मंत्री के दौरे के चलते रास्ते में पुलिस की अलग-अलग एजेंसियों द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन समाजजन अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचने पर अड़े रहे और आखिरकार करीब 11 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद समाजजन को वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप और मिले आश्वासन के बाद प्रदर्शन स्थल को जनपद पंचायत बालाघाट के सामने किया गया। यहां समाज के लोगों ने टेंट लगाकर दिनभर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। धरने के दौरान सोहन बाडके, शेखर जायसवाल, मछुआ समाज के सचिव बेनीराम मेश्राम, सुरेंद्र चौधरी, श्रवण मेश्राम सहित अन्य वक्ताओं ने अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि समाज लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।वहीं वारासिवनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल भी धरना स्थल पर पहुंचे और मछुआ समाज की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाज की जायज मांगों के साथ वे खड़े हैं और संबंधित विषयों को लेकर उनकी बात शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।शेखर जायसवाल ने कहा कि कई बार विभागीय स्तर पर जांच कराई गई, लेकिन उसका सही नतीजा सामने नहीं आया। इसी कारण करीब एक सप्ताह पहले ही कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि समाज अब केवल आश्वासन के भरोसे पीछे हटने वाला नहीं है और लंबित मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई चाहता है। धरना दे रहे समाजजनों ने प्रशासन को दो दिन का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि इस अवधि में मांगों को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे धरना स्थल पर ही अनशन शुरू करेंगे। समाज ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन वंशानुगत मछुआ परिवारों के अधिकारों और उनकी आजीविका से जुड़े मुद्दों को लेकर है और मांगों के निराकरण तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है।

केके सिंगारे को किया जाए निलंबत,सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन

चेक पावर छीनने, कार्यालय से अटैच करने और जिले से बाहर स्थानांतरण की भी मांग, प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री केके सिंगारे के खिलाफ चल रहे विवाद के बीच सोमवार को सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने सिंगारे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने मप्र शासन के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री तथा बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्यपालन यंत्री केके सिंगारे को निलंबित करने, उनके चेक पावर वापस लेने, कार्यालय से अटैच करने तथा बालाघाट से हटाकर भिंड-मुरैना जैसे किसी अन्य जिले में पदस्थ करने की मांग की।एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान के नेतृत्व में पहुंचे पदाधिकारियों और ठेकेदारों ने प्रभारी मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और सिंगारे के खिलाफ लगाए गए आरोपों से अवगत कराया। इस दौरान प्रभारी मंत्री से प्रतिनिधिमंडल की चर्चा भी हुई। बताया गया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर कुमार सत्यम को संपूर्ण प्रकरण की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई कर शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई, जांच में सामने आई थी आय से अधिक संपत्ति

गौरतलब है कि कार्यपालन यंत्री केके सिंगारे पहले से ही जांच और कार्रवाई के घेरे में हैं। आर्थिक अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की कार्रवाई के दौरान उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की जांच की गई थी। जांच में अब तक करीब 11 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चलने की बात सामने आई थी, जो उनकी ज्ञात आय की तुलना में कई गुना अधिक बताई गई। मामले में अन्य संपत्तियों, बैंक खातों और लॉकरों की जांच भी जारी रहने की जानकारी सामने आई थी।इसी पृष्ठभूमि में अब सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने विभागीय स्तर पर भी सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि अधिकारी पर गंभीर आरोपों की जांच चल रही है तो उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकारों से दूर रखा जाना चाहिए, ताकि जांच प्रभावित न हो और ठेकेदारों के हितों की भी रक्षा हो सके।

ठेकेदारों में नाराजगी, कार्रवाई की मांग

एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि केके सिंगारे के चेक पावर तत्काल छीने जाएं, उन्हें कार्यालय से अटैच किया जाए और निष्पक्ष जांच के लिए बालाघाट से बाहर पदस्थ किया जाए। साथ ही मामले में दोष सिद्ध होने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की मांग भी की गई है।ज्ञापन सौंपने वालों में सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन मध्यप्रदेश के कोषाध्यक्ष संतोष कुमार असाटी, सदस्य एवं पीड़ित छोटूलाल ठाकरे, इंजीनियर आतिफ खान, कांट्रेक्टर अंसार खान, ठेकेदार सीताराम लील्हारे सहित अन्य पदाधिकारी और ठेकेदार मौजूद रहे।

आस-पास की खबरें

बेलगांव में भक्तिभाव के साथ मनाया गया श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत बेलगांव में हिन्दु धर्मालंबियों के द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर शुक्रवार को शुभ मुहुर्त पर अपने-अपने घरों में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापना कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस

अवसर पर श्रध्दालुओं के द्वारा नंदलाला श्री कृष्ण की विधि-विधान से पूजा अर्चन कर ग्राम की सुख-समृध्दि के लिए प्रार्थना की गई। जिसके बाद शनिवार की शाम में सभी श्रध्दालुजन अपने-अपने घरों से प्रतिमा लेकर ग्राम के चौक में एकत्रित हुए जिसके बाद बैंडबाजे की धुन पर शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा ग्राम का भ्रमण करते हुए ग्राम के समीप से गुजरी नहर पहुंची। जहां भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना एवं आरती कर विधिपूर्वक प्रतिमा का विसर्जन किया गया और सभी ने एक-दुसरे को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सरपंच अरविंद पंचेश्वर, सावनलाल गाडेश्वर, मोहनदास माने, बिस्तेराम बाहेश्वर, यदूराम पंचेश्वर, पन्नालाल पंचेश्वर, सावललाल सिंघई, खोमन लांझेवार, पप्पू सिंघई, तिलक सिंघई, राजा सिंघई, रामेश्वर बाहेश्वर, गणेश पंचेश्वर, लकेश बाहेश्वर, कुंजीलाल, अशोक सिंघई, बीरेलाल, नंदलाल सिंघई, रामलाल, महेश, मेहतर नेवारे, दिनेश, गिरधारी घोटीवार, दीनदयाल भारद्वाज, जीवन बारेकर, पेशारी महोबे, देवदास बोरकर, गोकुल बाहेश्वर, बेनीराम, माने, खेमन माने, मोतीलाल माने, दिनेश बाहेश्वर, मुकेश बाहेश्वर, विजय राणा, रामेश्वर मरठे, राजेन्द्र कावरे, अनिल सिंघई, अशोक पंचेश्वर, धरमराज बाहेश्वर, वीरू मरठे, गोपाल माने, पिंटू महोबे, कृष्णा सिंघई, राजेश माले, विजय पंचेश्वर, परमानंद सोनी, सोमन बारेकर, शिवचरण माले, सुरेश माने सहित बड़ी संख्या में श्रध्दालुजन उपस्थित रहे।

तीन दिन से लापता व्यक्ति का कुएं में मिला शव

ससुराल आया था मृतक, आज किया जायेगा पोस्टमार्टम, मामले की जांच में जुटी पुलिस

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

ससुराल आये एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक पिछले तीन दिनों से लापता था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस थाने में भी दर्ज करवाई थी। सोमवार को ग्राम पंचायत टेकाड़ी ला. निवासी किसान के खेत स्थित कुएं से पुलिस ने तीन दिन से लापता व्यक्ति पोटूटोला बोरी निवासी 45 वर्षीय अमरसिंह बैगा का शव बरामद किया है। वहीं शाम हो जाने के कारण शव को लालबर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के शव वि छेदन गृह में रखवा दिया गया है, मंगलवार को सुबह पोस्टमार्टम किया जायेगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घास काटने गये किसान को कुएं में उतराता हुआ दिखाई दिया शव

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अमरसिंह पिता मिलापसिंह बैगा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बोरी के पोटूटोला का रहने वाला था। जो बीते कुछ दिनों पूर्व रक्षाबंधन में ससुराल ग्राम टेकाड़ी ला.

आया हुआ था। पिछले तीन दिनों से वह अचानक लापता हो गया, जिसकी काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। सोमवार शाम करीब 4 बजे खेत में घास काटने गये एक किसान ने जब पास स्थित कुएं की ओर से गुजर रहा था तो उसे एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद उसके द्वारा शोर मचाते हुए ग्रामीणों को जानकारी दी कि कुएं में एक व्यक्ति डूबा हुआ है। वहीं देखते-देखते घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस घटना स्थल पहुंचकर होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाले, जिसकी शिनाख्त तीन दिनों से लापता व्यक्ति अमरसिंह के नाम से की गई। जिसके बाद उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा कार्यवाही पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर आये। लेकिन देरशाम हो जाने के कारण शव को शव विच्छेदन गृह में रखवा दिया गया है, दुसरे दिन मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जायेगा। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक रक्षाबंधन पर्व पर अपने ससुराल टेकाड़ी ला. आया था और तीन दिन पूर्व बिना बताये कही लापता हो गया था, तीन दिन बाद टेकाड़ी ला. के किसी किसान के खेत स्थित कुएं से उसका शव संदिग्ध अवस्था में मिला है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वह खेत की ओर घुमने गया होगा और कुएं के समीप से गुजरते समय पैर अनियंत्रित होने से कुएं में गिर गया होगा जिससे उसकी मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पायेगा।

मामले की जांच की जा रही है - राजमल

दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी राजमल दायमा ने बताया कि तीन दिन से लापता व्यक्ति का टेकाड़ी ला. निवासी एक किसान के खेत स्थित कुएं से सोमवार की शाम में शव दिखाई देने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पहुंचकर शव बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की है। श्री दायमा ने बताया कि मृतक 45 वर्षीय अमरसिंह बैगा पोटूटोला बोरी निवासी है, देरशाम हो जाने के कारण मृत व्यक्ति की लाश को शव विच्छेदन गृह में रखवा

तालाब में डूबने से युवक की मौत, ग्राम में पसरा मातम

पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा, जांच में जुटी पुलिस

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कामथी में सोमवार दोपहर एक दु:खद हादसा सामने आया है। गांव के ही तालाब में डूबने से 18 वर्षीय युवक अंकित पिता नेतलाल सहारे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने घटना स्थल से शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

माँ-बाप का इकलौता बेटा था अंकित

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अंकित मूल रूप से बघोली का निवासी था, लेकिन बचपन से ही वह अपनी माँ के साथ कामथी में अपने मामा के घर पर रह रहा था, जिसने कक्षा 9 वी तक पढ़ाई की है और उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। उनकी माँ ने दोनों बच्चों की परावरिश ग्राम कामथी में अपने मायके में रहकर ही की है। सोमवार को दोपहर में अंकित कामथी स्थित तालाब की ओर घुमने गया था लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद वह घर वापस नही आया तो परिजन उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान किसी ग्रामीण को तालाब में डुबा हुआ कोई दिखाई दिया। जिसकी जानकारी लगते ही घटना स्थल में लोगों की भीड़ लग गई। जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। वहीं लालबर्रा पुलिस को कामथी के तालाब में किसी व्यक्ति के डुब जाने की जानकारी लगने के बाद थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिसकर्मी घटना स्थल पहुंचे और गोताखोरों व ग्रामीणों की मदद से तालाब में डुबे युवक को बाहर निकाला गया, जिसकी शिनाख्त मूल निवासी बघोली, हाल मुकाम कामथी निवासी 18 वर्षीय अंकित सहारे के नाम से की गई। जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर आये। जहां चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। मृतक युवक माँ-बाप का इकलौता बेटा था। बचपन में ही उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चले गई थी किसी कारणवश और उनके पिता बघोली में ही रहते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को दोपहर में अंकित सहारे गांव के तालाब की ओर गया होगा, तालाब के किनारे अचानक पैर फिसल जाने से वह अनियंत्रित होकर गहरे पानी में चला गया होगा और अधिक समय तक पानी में डूबे रहने के कारण उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन शरीर में कपड़े नही होने से यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नहाने के दौरान उक्त हादसा घटित हुआ होगा। अंकित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी असमय मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा है और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

सोनेवानी लालबर्रा वाईल्ड लाईक वाहन संचालक संघ के अध्यक्ष बने राहुल शर्मा

1 अक्टूबर से खुलेगा सोनेवानी का गेट, पर्यटक वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र का करेगें भ्रमण

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। दक्षिण सामान्य वन विभाग लालबर्रा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले सोनेवानी जंगल को वन भ्रमण व अनुभूति केंद्र के लिए प्रमुखता से जाना जाता है। जहां जिले सहित अन्य जिलों व प्रदेशों के पर्यटक व नागरिक घूमने आते है। साथ ही जंगल क्षेत्र का भ्रमण कर बाघ सहित अन्य वन्यप्राणियों का दीदार करते है परन्तु शासन के निर्देश पर दक्षिण सामान्य वन विभाग लालबर्रा के वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए सोनेवानी वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र को जून माह में बंद कर दिया गया था। जिसे अब 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया जायेगा और क्षेत्रीय पर्यटक सफारी कर सोनेवानी वन्यप्राणी क्षेत्र का भ्रमण करने के साथ ही बाघ सहित अन्य वन्यप्राणियों का दीदार करने के साथ ही टेकाड़ी ला. सरांटी जलाशय एवं पहाड़ी क्षेत्र के मनमोहक दृश्यों का जमकर आनंद लेगें। वहीं सोनेवानी वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के गेट खुलने के पहले 7 सितंबर को बालाघाट रोड़ मानपुर स्थित लॉन में वाईल्ड लाईक वाहन संचालक संघ सोनेवानी लालबर्रा की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। यह बैठक वन्यजीव प्रेमी, जिप्सी संचालक एवं संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। आयोजित बैठक में संघ का गठन करने, 1 अक्टूबर से सोनेवानी अनुभव क्षेत्र का भ्रमण हेतु गेट खुलने के पहले की तैयारी, जंगल क्षेत्र स्थित सड़क का मरम्मत कार्य, वन विभाग के नियमों का सभी जिप्सी संचालकों को पालन करने सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं सर्वसम्मति से वाईल्ड लाईक वाहन संचालक संघ सोनेवानी लालबर्रा का गठन कर राहुल शर्मा को अध्यक्ष, भूपेन्द्र बिसेन (नवेगांव गेट), नोबिल बिसेन (अंतरा गेट), रिजाद अली (रमरमा गेट) को उपाध्यक्ष, राजिक मंसुरी को सचिव, आरिफ खान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को संघ के हित एवं वन विभाग के द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करते हुए कार्य करने की बात कही गई। वहीं उपस्थित वन्यप्रेमी एवं जिप्सी संचालकों ने भी अपनी-अपनी बात रखते हुए कहा कि वन विभाग के द्वारा 1 अक्टूबर से सोनेवानी अनुभव क्षेत्र को प्रारंभ किया जा रहा है, लेकिन बारिश होने के कारण जंगल क्षेत्र की सड़क खराब हो चुकी होगी, ऐसी स्थिति में पर्यटकों को वन्यप्राणियों का दीदार करवाने हेतु भ्रमण करने में परेशानी होगी, इसलिए वन विभाग को उक्त क्षेत्र की सड़कों एवं गड्ढों का मरम्मत कार्य एवं सभी जिप्सी संचालकों व गाइडस को नियमों का पालन करवाने की मांग की है। इस अवसर पर वनप्रेमी ज्ञानचंद शर्मा, पांढरवानी सरपंच अनीस खान सहित संघ के सदस्य एवं जिप्सी संचालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

नियमों के पालन के साथ पर्यटकों को दी जायेगी बेहतर सुविधा - संघ

चर्चा में वाईल्ड लाईक वाहन संचालक संघ लालबर्रा के नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल शर्मा, सचिव राजिक मंसुरी, भूपेन्द्र बिसेन ने संयुक्त रूप से बताया कि शासन के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से सोनेवानी वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र पर्यटकों के लिए खोल दिया जायेगा। इसलिए संघ का गठन करने एवं विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में संघ का गठन के साथ ही पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और सभी को वन विभाग के नियमों का पालन करते हुए जिप्सी वाहन चलाने एवं पर्यटकों को जंगल क्षेत्र का भ्रमण करवाने की बात कही गई है। साथ ही यह भी बताया कि बारिश के कारण जंगल के अंदर के सड़कों की हालत खराब हो गई है, जिससे भ्रमण के दौरान वाहनों के संचालन में परेशानी आ सकती है। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग से मांग की जाती है कि प्रवेश गेट खुलने से पहले मार्ग एवं गड्डों का मरम्मत कार्य तत्काल पूर्ण करवाये। आगे बताया कि संघ का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना और वन विभाग के सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। आगामी 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे पर्यटन सत्र के लिए सभी जिप्सी संचालक और गाइड पूरी तरह से तैयार हैं। संघ द्वारा सभी सदस्यों को विभागीय दिशा-निर्देशों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बेहतर सुविधा हेतु कार्य करने के निर्देश दिये गये है।

पांढरवानी सरपंच ने 4 हितग्राहियों को अंत्येष्टि सहायता राशि का किया वितरण

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय को ग्राम पंचायत पांढरवानी निवासी हरकंता यादव, रिजवान रंगरेज, धनराज सहारे, शशिभूषण रंगारे का गत दिवस मृत्यु हो गई थी। सोमवार को मृतिका के परिजन को ग्राम पंचायत पांढरवानी सरपंच अनीस खान के द्वारा 5-5 हजार रूपये की अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान की गई है और उन्हे शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ दिलवाया जायेगा। चर्चा में पांढरवानी सरपंच अनीस खान ने बताया कि ग्राम के 4 व्यक्तियों का गत दिवस मृत्यु होने के उपरांत शासन से मिलने वाली मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल योजना के अंतर्गत) अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत मृत व्यक्तियों के परिजन राधेश्याम यादव, साईमा रंगरेज, प्रभा सहारे एवं अनिता रंगारे को 5-5 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई है। साथ ही शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ दिलवाया जायेगा। इस अवसर पर सरपंच अनीस खान, प्रभारी सचिव कृष्णा पंचेश्वर सहित हितग्राही एवं पंचायतकर्मी उपस्थित रहे।

जहरीली शराब के डिस्टलरी मालिकों को बचा रहे आबकारी अधिकारी

भोपाल। एजेंसी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में लगातार हिंदुओं की मौत हो रही है और सरकार के जिम्मेदार अधिकारी जहरीली शराब के मामले में डिस्टलरी मालिकों को बचाने में लगे हैं। सिंघार ने कहा- पाकिस्तान के बाद अगर हिंदू कहीं खतरे में हैं तो वह मध्य प्रदेश है। सागर से लौटने के बाद भोपाल स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंघार ने कहा कि सरकार और आबकारी विभाग शराब के नेटवर्क के उत्तर प्रदेश से जुड़े होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका दावा है कि शराब का नेटवर्क उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के भावनगर में नौ लोगों की मौत के मामले में गुजरात पुलिस को उज्जैन का नेटवर्क मिला था। उज्जैन में शराब पकड़ी गई और वहां किस तरह शराब का नेटवर्क चल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। सिंघार ने सवाल किया कि उज्जैन में अनीश यादव किससे जुड़े हुए हैं और क्या उन्हें मुख्यमंत्री का समर्थन हासिल है? उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस मामले में बयान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उज्जैन और धार में जहरीली शराब बन रही है और सागर में पहुंच रही है। सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।

आबकारी आयुक्त सागर क्यों पहुंचे, किसे बचाने?

सिंघार ने आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के सागर पहुंचने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घबराहट में आबकारी आयुक्त सागर पहुंचे, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे आबकारी विभाग के नेक्सस को बचाने पहुंचे थे या डिस्टलरी मालिकों को। उन्होंने कहा कि अभी तक जिला आबकारी अधिकारी और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है और डिस्टलरी मालिकों पर भी केस दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने आबकारी विभाग के आदेशों में कथित बदलाव को लेकर भी सवाल उठाया। सिंघार ने कहा कि यदि किसी ब्रांड की शराब को पहले पीने योग्य नहीं बताया गया और एक घंटे के भीतर ही आदेश बदलकर उसे पीने योग्य बता दिया गया तो यह गंभीर मामला है। उनके अनुसार यह बदलाव अधिकारियों और डिस्टलरी मालिकों के बीच मिलीभगत की ओर इशारा करता है। सिंघार ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को बदनाम करने में लगी है, जबकि शराब का नेटवर्क मध्य प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों और डिस्टलरी मालिकों के बीच मिलीभगत के कारण नकली ब्रांड की शराब बाजार में पहुंच रही है और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पैसे कमाने की होड़ है और सरकार को जनता की चिंता नहीं है।

खापा से कैंप मार्ग जर्जर, राहगीर परेशान

उड़ती गिट्टियां और गड्ढे बढ़ा रहे दुर्घटना का खतरा

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम खापा से कैंप को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों अत्यंत बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। मार्ग पर डामर की परत जगह जगह से तरह उखड़ चुकी है जिसके कारण पूरी सड़क पर छोटे.बड़े जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों से बाहर निकली गिट्टियां राहगीरों स्कूली विद्यार्थियों और वाहन चालकों के लिए लगातार हादसे का सबब बन रही हैं। सड़क की इस दुर्दशा के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे शीघ्र मरम्मत की मांग कर रहे हैं।

क्षमता से अधिक भार और देखरेख का अभाव

प्राप्त जानकारी के अनुसार खापा में जिले और संभाग का एक प्रमुख खुला अनाज भंडारण केंद्र स्थित है। पूर्व में ग्रामीणों के भारी जनांदोलन के बाद प्रशासन ने इस मार्ग पर डामरीकरण कराया था। हालांकि रोजाना अनाज ढोने वाले दर्जनों भारी भरकम ट्रकों की आवाजाही के कारण यह सड़क समय से पहले ही जर्जर हो गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मार्ग के निर्माण कम क्षमता के वाहनों के अनुसार किया गया था। जबकि इस पर क्षमता से दोगुना भारी वाहन दौड़ रहे हैं। निर्माण के बाद से अब तक विभाग के द्वारा एक बार भी मरम्मत कार्य नही कराए जाने से सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सड़क के प्रारंभ में स्कूल के सामने भयंकर गड्ढे हो गए हैं तो वहीं कैंप के सामने करीब २०० मीटर की दूरी में गड्ढों का अंबार लगा हुआ है, इन सभी जगह डामर की चद्दर उखाड़ने से यहां गड्ढे बन गए हैं यह स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में जलभराव होने से राहगीरों पर गंदा पानी और कीचड़ उछलता है जिससे पैदल चलने वालों व दोपहिया चालकों के कपड़े खराब हो रहे हैं। दोपहिया वाहनों के फिसलने और अनियंत्रित होकर गिरने का डर हर समय बना रहता है। यह मार्ग केवल खापा ही नहीं बल्कि आसपास की कई ग्राम पंचायतों को आपस में जोड़ता है। प्रतिदिन सैकड़ों विद्यार्थी और ग्रामीण इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के द्वारा कई बार संबंधित विभाग से मरम्मत की गुहार लगाई जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मानसून से पूर्व मरम्मत करा दी जाती तो सड़क की इतनी दुर्दशा नही होती। ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग का अविलंब डामरीकरण या मरम्मत कराया जायें।

स्कूल आने जाने में सभी छात्र छात्राओं को बहुत समस्या होती है-अंजलि गजाम

छात्रा अंजलि गजाम ने बताया कि मैं गोंडीटोला में निवास करती हूं जहां से शिक्षा अध्ययन करने के लिए एकीकृत माध्यमिक शाला खापा आना होता है। इस दौरान करीब १ किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है यह जो मार्ग से हम आते जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। हमें साइकिल से आने.जाने में बहुत दिक्कत होती है बारिश के समय कपड़े खराब हो जाते हैं वहीं भारी ट्रक रोजाना चलते रहते हैं तो डर भी लगा रहता है। दुर्घटना तो यहां होती है अभी कुछ समय पहले इस मार्ग पर गड्ढों के कारण दो जगह दुर्घटना हुई थी जिसमें उन लोगों को घायल होना पड़ा था। यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती है ,हम यही चाहते हैं कि मार्ग को अच्छे से बनाना चाहिए ताकि आवागमन कर रहे लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।

मार्ग की जर्जर स्थिति से ग्रामीणजन बहुत परेशान है-जितेंद्र गौतम

ग्रामीण जितेंद्र गौतम ने बताया कि यह मार्ग का निर्माण बहुत संघर्षों के बाद बना हुआ था परंतु वर्तमान में यह जगह.जगह से खुद गया है गड्ढे हो गए हैं। प्रारंभ में ही बहुत ज्यादा गड्ढे एक स्थान पर बने हुए हैं जहां लोगों को आराम से आना जाना होता है नए व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वहीं पूरे मार्ग इस प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं और कैंप के सामने तो बहुत ज्यादा समस्या है। यह मार्ग सीधे कटंगी के लिए निकलता है और बहुत सारे लोग यहां से आना जाना करते हैं दुर्घटनाएं भी घटित होती है। इस मार्ग की मरम्मत बहुत समय से नहीं की गई है यदि समय रहते मरम्मत की जाती तो यह गड्ढे इतने बड़े नहीं होते। हमारी मांग है कि जल्द इसकी मरम्मत कर दी जाए ताकि संभावित दुर्घटना का भय समाप्त हो। यहां प्रतिदिन भारी वाहन चलते हैं जिससे और ज्यादा मार्ग भविष्य में खराब होगा उसके पहले सुधार होना चाहिए।

बोदलकसा पुलिया पर अंधा मोड़ बना परेशानी का सबब

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदलकसा के प्रारंभ में स्थित पुलिया और सड़क का घुमावदार निर्माण राहगीरों की जान के लिए आफत बन गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार में बनी इस सड़क के ठीक मध्य में एक पुलिया स्थित है। जहां हर पल भीषण सड़क दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है। ग्रामीणों और रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों ने शासन प्रशासन से यहां तत्काल सुरक्षा इंतजाम किए जाने की मांग की है।

अंधा मोड़ और सांकेतिक बोर्ड का अभाव

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिया के दोनों ओर अत्यंत खतरनाक अंधे मोड़ हैं। यहां मोड़ पर अचानक सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो जाती हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब राहगीर अचानक मुड़ते हैं और सामने से आने वाली गाड़ियां ब्रेक तक नहीं लगा पातीं। इतने संवेदनशील मोड़ के बावजूद संबंधित विभाग के द्वारा यहां अब तक ना तो कोई टर्निंग गार्ड लगाया गया है और ना ही किसी प्रकार का सांकेतिक बोर्ड स्थापित किया गया है। मार्ग संकरा है इसके ठीक बगल में गहरा नाला बहता है। ढलान और तीखे मोड़ के कारण कई बार अनियंत्रित होकर वाहन सीधे नाले में जा गिरते हैं। दिन के उजाले में स्थानीय लोग जैसे तैसे सावधानी पूर्वक निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में विशेषकर नए राहगीरों और वाहन चालकों को सड़क का मोड़ और ढलान समझ पाना बेहद कठिन हो जाता है जिससे कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। यह मार्ग आगे चलकर सीधे कटंगी क्षेत्र को जोड़ता है और दर्जनों ग्रामीण पंचायतों के लिए संपर्क मार्ग का कार्य करता है। वारासिवनी मुख्यालय आने जाने के लिए रोजाना सैकड़ों ग्रामीण साइकिल, मोटरसाइकिल और चार पहिया वाहनों से इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। भारी कमर्शियल वाहनों की भी निरंतर आवाजाही बनी रहती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस रास्ते से होकर बड़ी संख्या में स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी रोजाना गुजरते हैं, जिससे हर समय बड़े हादसे का डर सताता रहता है। ग्रामीण राहगीर ने शासन प्रशासन से मांग की है कि पुलिया के दोनों ओर तत्काल प्रभाव से टर्निंग गार्ड और रेडियम युक्त साइन बोर्ड लगा कर पुलिया और संकरे मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। ताकि रात के समय वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सके।

मार्ग के दोनों तरफ अंधा मोड़ होने से रास्ता और वाहन नहीं दिखाई देते - तुलसीराम जैतवार

ग्रामीण तुलसीराम जैतवार ने बताया कि बोदलकसा खापा की यह सीमा है यहां पर एक नाला है। आने जाने में समस्या इसलिए है कि दोनों तरफ अंधा मोड़ है आगे का रास्ता और वाहन दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। कई बार वाहन नाले में उतर जाते हैं नए लोगों के साथ यह समस्या होती है। क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है अपने हिसाब से लोग आना जाना करते हैं जिन्हें पता है वह ठीक है और जिन्हे नहीं पता उनसे दुर्घटना होती है। यहां टर्निंग गार्ड लगने चाहिए ताकि लोगों को टर्निंग पता रहे दोनों तरफ गोलाई है आगे का स्पष्ट दिखता नहीं है। यह मार्ग कटंगी के लिए निकलता है इस पर से यात्री वाहन छोड़कर सभी भारी वाहन ऑटो ट्रक टैंपो आना जाना करते हैं।

गांधी चौक पर गोविंदाओं ने २५ फिट ऊंची मटकी फोड़ कर लगाये जयघोष

श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं की तर्ज पर दही हांडी कार्यक्रम बना नगर की पहचान-प्रदीप जायसवाल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर के गांधी चौक पर श्रीकृष्णा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस साल भी विशिष्ट पहचान देखने को मिली। दही हांडी प्रतियोगिता में पानी की तेज बौछार,गुलाल की होली,तेज डीजे शोर के बीच गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने श्रीकृष्ण भक्त भी अधिक संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की टीमो ने भी शामिल होकर बेहद उंची बंधी दही मटकी को फोडने का अनवरत प्रयास किया और अंत में कंटगझरी की युवा टीम को इस कार्य में सफलता मिल ही गयी। सांस्कृतिक कार्यक्रम मटकी फोड़ प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने श्रीकृष्ण लीलाओं की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुये कार्यक्रम को नगर की पहचान बनने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि यह उत्सव भगवान श्रीकृष्ण की बचपन की उस लीला को दर्शाता है, जिसमें वे ब्रंदावन में ग्वालबालो के साथ मिलकर गोपियों के घरो से मक्खन व दूध चुराया करते थे। आज युवाओं की उर्जा व सहभागिता को देखकर हमारी सोच भी पूरी हो रही है। हम सभी को साथ लेकर नगर व क्षेत्र में समान रूप से विकास की नयी गाथा लिखना चाहते है। नपा अध्यक्ष श्रीमती सरिता दांदरे ने जन्माष्टमी के महत्व को रेखांकित कर आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज कार्यक्रम में बेहद सुंदर स्वरूप में सजे हुये अनेक बालको को श्रीकृष्ण के रूप में देखकर बेहद प्रसन्नता भी हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने पूरे कार्यक्रम को कौमी एकता की पहचान निरूपित किया। उन्होंने कहा कि उनका बचपन भी इसी गांधी चौक में व्यतीत हुआ है। इस स्थल पर सभी कार्यक्रम में सभी की सहभागिता से बेहद सफल होते आये है। इसी तरह पूर्व पार्षद सुनील पिपरेवार ने ग्राम ग्राम से आये गोविंदाओं का मार्गदर्शन करते हुये कार्यक्रम को नगर के त्योहारों को भव्य और एक नयी दिशा देने की बात कही। आयोजक टीम की तरफ से संदीप मिश्रा ने कहा कि अनवरत ६ साल के इस कायक्रम के सफर को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रथम वर्ष के छोटे आयोजन का जिक्र करते हुये कहा की आज ६ वें वर्ष में यह कार्यक्रम सभी के सहयोग के कारण विराट रूप ले लिया है। इस दौरान उत्कर्ष कासल, अमित एरपुडे,शैलेंद्र तिवारी,अरमान खान,समीर बिसेन,रितेश पटले ने भी गोविंदाओं की टोली को मानव पिरामिड बनाकर दही मटकी फोड़ने की शैली की सराहना की। आयोजक टीम की तरफ से मोनु लिमजे ने बताया कि प्रथम पुरस्कार कंटगझरी टीम को ७ हजार एक सौ रुपये,द्वितीय पुरस्कार कायदी टीम को तीन हजार एक सौ रूपये प्रदान किया गया है। साथ ही भौरगढ, वारासिवनी व अन्य टीमो को भी पुरस्कृत कर आयोजन को सफल बनाने के लिये साधुवाद प्रेषित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने मे संदीप मिश्रा, मोनू लिमजे,संजय रजक, शरद दुबे,जगदीश नेमा, संजय बांगडे,साजिद अली,मिथलेश बुरडे, शाहबाज मंसूरी,राहील खान, अभिषेक चौहान, अमन चौहान, मोंटी चौहान, निलेश डोंगरे,शंशाक डोंगरे,मयूर चौरसिया,साहिल खान,सिंद्धात मिश्रा, मोनू देवगिरकर, साबिर खान,रवि गोखले, परमेंद्र हेडाउ आदि का योगदान रहा।

केशव विद्यालय में विद्यार्थियों ने मनाया शिक्षक दिवस

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। केशव इंग्लिश हायर सेकेण्डरी स्कुल में भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता की भावना व्यक्त करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा सभी शिक्षकों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। विद्यार्थियों ने अपने भाषणों एवं कविताओं के माध्यम से शिक्षकों के प्रति अपने भाव व्यक्त किए तथा उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मनोरंजन एवं उत्साह के लिए विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया। शिक्षकों ने भी इन खेलों में उत्साह पूर्वक भाग लिया, जिससे विद्यालय परिसर में खुशी और उमंग का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम में शिक्षकों के समर्पण, मेहनत एवं विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। अंत में राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का गरिमापूर्ण समापन हुआ।

हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए ज्ञान की रोशनी

दुनियाभर में लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्वभर में 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' मनाया जाता है। दुनिया से अशिक्षा को समाप्त करने के संकल्प के साथ इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पहली बार यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा 17 नवम्बर 1965 को 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद प्रथम बार 8 सितंबर 1966 से शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्वभर के लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष इसी दिन यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। वास्तव में यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का ही प्रमुख घटक है। निरक्षरता को खत्म करने के लिए ईरान के तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान वर्ष 1965 में 8 से 19 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए पहली बार बैठक की गई थी और यूनेस्को ने नवम्बर 1965 में अपने 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। उसके बाद से सदस्य देशों द्वारा प्रतिवर्ष 8 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' मनाया जा रहा है। साक्षरता दिवस के अवसर पर निरक्षरता समाप्त करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देने तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। यह दिवस लगातार शिक्षा को प्राप्त करने की ओर लोगों को बढ़ावा देने के लिए तथा परिवार, समाज और देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए मनाया जाता है। दुनियाभर में आज भी अनेक लोग निरक्षर हैं और यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विश्व में सभी लोगों को शिक्षित करना ही है। साक्षरता दिवस के माध्यम से यही प्रयास किए जाते हैं कि इसके जरिये तमाम बच्चों, व्यस्कों, महिलाओं तथा वृद्धों को भी साक्षर बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में फिलहाल करीब चार अरब लोग साक्षर हैं लेकिन विडम्बना यह है कि आज भी विश्वभर में करीब एक अरब लोग ऐसे हैं, जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते। तमाम प्रयासों के बावजूद दुनियाभर में 77 करोड़ से भी अधिक युवा भी साक्षरता की कमी से प्रभावित हैं अर्थात प्रत्येक पांच में से एक युवा अब तक साक्षर नहीं है, जिनमें से दो तिहाई महिलाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि 6-7 करोड़ बच्चे आज भी ऐसे हैं, जो कभी विद्यालयों तक नहीं पहुंचते जबकि बहुत से बच्चों में नियमितता का अभाव है या फिर वे किसी न किसी कारणवश विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। कोरोना काल में यह समस्या और ज्यादा गहरी हुई। करीब 58 फीसदी के साथ सबसे कम व्यस्क साक्षरता दर के मामले में दक्षिण और पश्चिम एशिया सर्वाधिक पिछड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक विशेष थीम चुनी जाती है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है 'लोगों, धरती और समृद्धि के लिए साक्षरता'। वर्ष 2025 और 2024 में साक्षरता दिवस क्रमशः 'डिजिटल युग में साक्षरता को ब ?ावा देना' और 'बहुभाषी शिक्षा को ब ?ावा देना- आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता' थीम के साथ मनाया गया था। इस विशेष दिवस के लिए 2006 से लेकर अब तक निर्धारित थीम पर नजर डालें तो 2006 में सामाजिक प्रगति प्राप्ति पर ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय 'साक्षरता सतत विकास' रखा गया था।

सागर से उठता सवाल -जहरीली शराब की कीमत कौन चुका रहा है?

मौतें जनता की,राजस्व सरकार का और फायदा माफिया का ? -शराब माफिया बड़ा या सरकारी सिस्टम ?- समग्र व्यापक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर भारत में जहरीली शराब से मौत की खबर कोई नई खबर नहीं है।वर्षों से अलग-अलग राज्यों से ऐसी त्रासदियां सामने आती रही हैं और हर बार मौतों के बाद जांच,छापे, गिरफ्तारी,निलंबन, मुआवजा और कठोर कार्रवाई के आश्वासन सुनाई देते हैं।लेकिन कुछ समय बाद वही कहानी किसी दूसरे जिले, दूसरे राज्य और दूसरे गांव में फिर सामने आ जाती है। 6 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र से सामने आई कथित जहरीली/अवैध शराब की त्रासदी ने इसी पुराने प्रश्न को फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है, आखिर जहरीली शराब का नेटवर्क बार-बार क्यों लौट आता है और उसे स्थायी रूप से तोड़ने में व्यवस्था क्यों सफल नहीं हो पा रही? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मीडिया के हवाले से बताना चाहूंगा कि सागर में 6 सितंबर को सुबह से मृतकों की संख्या लगातार बदलती रही।शुरुआती रिपोर्टों में 8-9 मौतें सामने आईं,बाद में 11 और कुछ रिपोर्टों में 12 से 14 से अधिक मौतों की सूचना दी गई।30 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें भी सामने आईं। प्रभावित क्षेत्र में बंडा तहसील के कई गांवों के नाम सामने आए हैं और प्रशासन ने मेडिकल तथा जांच टीमें तैनात की हैं।शुरुआती चिकित्सकीय आकलन में मेथनॉल विषाक्तता की आशंका व्यक्त की गई,लेकिन अंतिम कारण पोस्टमार्टम और रासायनिक जांच के बाद ही निश्चित होगा। साथियों,इस घटना ने एक और गंभीर पहलू सामने रखा है।प्रारंभिक जांच संबंधी रिपोर्टों में उत्तर प्रदेश के ललितपुर से कथित नकली शराब नेटवर्क का कनेक्शन सामने आने की बात कही गई है।जांच रिपोर्टों के अनुसार नकली शराब को वास्तविक ब्रांड जैसा दिखाने के लिए नकली लेबल, ढक्कन और क्यूरआर कोड का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है तथा इसे वाहनों और मोटरसाइकिलों के माध्यम से मध्य प्रदेश के गांवों तक पहुंचाने की बात सामने आई है।कुछ रिपोर्टों में पांच शराब दुकानों को सील किए जाने की जानकारी भी है। हालांकि इस पूरे नेटवर्क की वास्तविक संरचना और किस स्तर तक इसकी पहुंच थी,यह जांच पूरी होने के बाद ही सटीकता से स्पष्ट होगा। साथियों,यहीं से पहला और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है शराब माफिया आखिर इतना संगठित कैसे हो जाता है कि नकली उत्पाद तैयार कर सके,उसे असली ब्रांड जैसा पैक कर सके,नकली क्यूरआर कोड लगा सके,सीमावर्ती जिलों में पहुंचा सके और अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके? यदि किसी नेटवर्क में उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण और स्थानीय बिक्री की अलग- अलग कड़ियां मौजूद हैं,तो यह केवल एक व्यक्ति की आपराधिक गतिविधि नहीं रह जाती;यह संगठित अवैध अर्थव्यवस्था का रूप ले लेती है।सागर की प्रारंभिक जांच में ललितपुर कनेक्शन की बात सामने आना इसी पहलू को गंभीर बनाता है। साथियों,बात अगर हम इस अवैध शराब से जुड़े पहले स्तर- शराब माफिया,नकली शराब की पूरी श्रृंखला को समझने की करें तो,अवैध शराब का कारोबार सामान्यतः केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं होता जो अंतिम बोतल बेचता है।सवाल यह है कि नकली शराब बनती कहां है,उसके लिए कच्चा माल और रसायन कहां से आते हैं,उसे तैयार कौन करता है,बोतलों में कौन भरता है नकली ब्रांडिंग कौन करता है,परिवहन कौन करता हैऔर स्थानीय स्तर पर उसे बेचने वाला कौन है? सागर मामले में यदि ललितपुर से उत्पादन और सागर तक आपूर्ति की जांच सही साबित होती है, तो जांच एजेंसियों को केवल स्थानीय विक्रेता तक रुकने के बजाय पूरे सप्लाई नेटवर्क को खंगालना होगा।मई 2026 के पुणे मामले ने भी इसी नेटवर्क की गंभीरता दिखाई थी। वहां जांच में मेथनॉल की आपूर्ति और उसे अवैध शराब में मिलाए जाने की कड़ी सामने आई तथा ए ?डीए ने हजारों किलोग्राम मेथनॉल जब्त किया था।यानें जहरीली शराब की समस्या केवल कुछ लोग चोरी से शराब बना रहे हैं तक सीमित नहीं है; इसके पीछे रसायनों की उपलब्धता,अवैध उत्पादन वितरण और स्थानीय बिक्री जैसी अनेक कड़ियां हो सकती हैं। साथियों,बात अगर हम इस अवैध शराब से जुड़े दूसरे स्तर, प्रशासन और आबकारी व्यवस्था,निगरानी कहां टूटती है? इसको समझने की करें तो,दूसरा सवाल सीधे प्रशासन और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी से जुड़ता है।लाइसेंस प्राप्त शराब दुकानों की निगरानी, अवैध बिक्री की पहचान, संदिग्ध शराब की जांच,स्टॉक और दस्तावेजों का सत्यापन तथा अवैध नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई व्यवस्था की जिम्मेदारियों का हिस्सा हैं।यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अवैध शराब बिकती रहती है,तो यह पूछना स्वाभाविक है कि स्थानीय सूचना तंत्र, पुलिस, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन के बीच समन्वय कितना प्रभावी था।लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी जरूरी है,हर जहरीली शराब की घटना के बाद पूरे प्रशासन को बिना जांच दोषी घोषित करना उचित नहीं है।दोष व्यक्तिगत अधिकारियों का है ?,विभागीय लापरवाही है? स्थानीय मिलीभगत है? या नेटवर्क ने निगरानी को चकमा दिया? यह स्वतंत्र जांच से तय होना चाहिए।फिर भी यदि जांच में यह सामने आता है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई,संदिग्ध दुकानों की निगरानी नहीं की गई या अधिकारियों ने जानबूझकर आंखें बंद कीं, तो जवाबदेही केवल माफिया तक सीमित नहीं रह सकती।पुणे त्रासदी के बाद पुलिस और आबकारी विभाग के 22 कर्मचारियों के निलंबन ? ने यही सिद्धांत सामने रखा कि यदि सरकारी निगरानी में गंभीर चूक प्रमाणित होती है तो प्रशासनिक जवाबदेही भी सटीकता से तय की जा सकती है। साथियों बात अगर हम इस अवैध शराब से जुड़े तीसरे स्तर-राजनीतिक और आर्थिक विरोधाभास,राजस्व बनाम जीवन इसको समझने की करें तो,भारत में शराब एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र है और अनेक राज्य इससे महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त करते हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। एक ओर सरकार शराब की बिक्री को नियंत्रित और लाइसेंस करती है तथा उससे राजस्व प्राप्त करती है; दूसरी ओर उसी व्यवस्था के समानांतर अवैध शराब का बाजार खड़ा हो जाता है, जो कभी-कभी सीधे मानव जीवन के लिए खतरा बन जाता है।इसका अर्थ यह नहीं कि वैध शराब की बिक्री अपने आप जहरीली शराब की जिम्मेदार है। समस्या उस समय पैदा होती है जब वैध और अवैध बाजार के बीच निगरानी की दीवार कमजोर पड़ती है। नकली बोतल, नकली लेबल, नकली क्यूरआर कोड और असली ब्रांड की नकल उपभोक्ता को यह समझने का अवसर ही नहीं देती कि वह क्या पी रहा है। सागर मामले में सामने आई कथित फर्जी पैकेजिंग इसी चिंता को और गंभीर बनाती है।इसलिए प्रश्न शराब के राजस्व को बंद करने या जारी रखने से पहले यह होना चाहिए कि क्या सरकार की नियामक क्षमता इतनी मजबूत है कि राजस्व व्यवस्था के साथ नागरिकों की सुरक्षा भी सटिका से सुनिश्चित की जा सके? साथियों बात अगर हम इस अवैध शराब से जुड़े,चौथे स्तर- मानव जीवन बनाम सरकारी राजस्व को समझने की करें तो,सबसे बड़ा प्रश्न आखिरकार आर्थिक नहीं, मानवीय है। एक व्यक्ति की मृत्यु का मूल्य किसी सरकारी राजस्व तालिका में दर्ज नहीं किया जा सकता। जहरीली शराब से मरने वाले व्यक्ति के पीछे एक परिवार होता है बच्चे होते हैं, माता-पिता होते हैं, पत्नी या पति होते हैं, भविष्य की योजनाएं होती हैं और परिवार की आर्थिक सुरक्षा होती है।यदि कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीकर मरता है तो नुकसान केवल एक जीवन का नहीं होता। परिवार की आय समाप्त हो सकती है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, चिकित्सा खर्च बढ़ सकता है, परिवार कर्ज में जा सकता है और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पैदा हो सकती है। इसलिए जहरीली शराब की वास्तविक सामाजिक लागत उस तत्काल सरकारी राजस्व से कहीं अधिक हो सकती है जो शराब के वैध कारोबार से प्राप्त होता है।भारत की जनता अब बार-बार सामने आने वाली ऐसी खबरों से केवल दुखी नहीं है; वह जवाब चाहती है। सवाल अब यह नहीं होना चाहिए कि अगली घटना के बाद कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल यह होना चाहिए कि अगली घटना होने ही न देने की सटिका से व्यवस्था कब बनेगी? साथियों बात अगर हम इस अवैध शराब से जुड़े, गंभीर प्रश्न क्या केंद्र और राज्यों को नई राष्ट्रीय रणनीतिचाहिए? इसको समझने की करें तो,अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस समस्या को केवल कानून -व्यवस्था की स्थानीय घटना मानने के बजाय राष्ट्रीय सार्वजनिक- सुरक्षा चुनौती के रूप में देखें। केंद्र के स्तर पर अवैध शराब के अंतरराज्यीय नेटवर्क, संदिग्ध औद्योगिक रसायनों की आपूर्ति,डिजिटल ट्रैकिंग, फर्जी लेबल और नकली क्यूरआर कोड जैसी तकनीकों के दुरुपयोग पर राज्यों के बीच बेहतर सूचना- साझाकरण का मजबूत ढांचा बनाया जा सकता है।राज्यों को अपने स्तर पर आबकारी, पुलिस,स्वास्थ्य विभाग, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और जिला प्रशासन के बीच एकीकृत तंत्र बनाना चाहिए।संदिग्ध शराब की तत्काल जांच, संवेदनशील क्षेत्रों की जोखिम-मैपिंग, लाइसेंसधारी दुकानों की डिजिटल निगरानी अवैध बिक्री की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही को संस्थागत बनाया जाना चाहिए। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहरीली शराब के मामले में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। गांवों में तत्काल चिकित्सा पहुंच, विषाक्तता की पहचान, रेफरल व्यवस्था और चिकित्सकों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल कई जानें बचा सकते हैं। साथियों सवाल आखिर किससे है? इसको समझने की करें तो,सागर की त्रासदी को केवल शराब पीने वालों की गलती कहकर समाप्त कर देना समस्या की जड़ से आंखें चुराना होगा।व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपनी जगह है,लेकिन जब नकली शराब उत्पादन,संगठित परिवहन, नकली पैकेजिंग,अवैध बिक्री और संभावित अंतरराज्यीय नेटवर्क जैसी कड़ियां सामने आती हैं, तब शासन की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शराब माफिया दोषी है तो उसका नेटवर्क टूटना चाहिए।संभवतः अधिकारी दोषी हैं तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

सोन जल समझौते से सहकारी संघवाद की नई राह

- डॉ. सत्यवान सौरभ

अंतरराज्यीय नदियाँ केवल बहते पानी की नदियाँ ही नहीं हैं, बल्कि ये जीवन रेखाएँ हैं जो कृषि उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, उद्योगों, पारिस्थितिकी तंत्र और लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देती हैं। हालाँकि, नदियों का प्रवाह राज्य की सीमाओं को भी पार कर सकता है, इसलिए इनका प्रबंधन राज्यों के बीच टकराव का कारण बन सकता है। हाल ही में बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी को लेकर हुआ समझौता, जिसका उद्देश्य लगभग 25 वर्षों से चले आ रहे जल विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करना है, सतत जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ‖ एक ऐसा जल मुद्दा जिसे केवल सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है, न कि टकराव से।

अंतरराज्यीय जल संघर्षों के निरंतर बने रहने का मुख्य कारण जल विकास के लिए परस्पर विरोधी हित हैं। एक राज्य सिंचाई के लिए अधिक जल का उपयोग कर सकता है, जबकि दूसरा पेयजल, उद्योग या शहरी विकास के लिए। ये सभी आवश्यकताएँ जायज़ हैं, लेकिन जल सीमित है। यदि कई राज्य एक ही नदी पर निर्भर हैं, तो संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं और इन आवश्यकताओं को संतुलित करना संघीय प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों और ऋतुओं में जल असंतुलन से जटिलताएं और बढ़ जाती हैं। मानसून के मौसम में अच्छी वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में उस दौरान भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी हो सकती है। इस प्रकार, एक नदी एक वर्ष भरपूर जल से भरी हो सकती है और दूसरे वर्ष विरल हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति और भी अनिश्चित होती जा रही है। वर्षा के बदलते पैटर्न से नदियों के प्रवाह में परिवर्तन हो रहा है, जबकि लंबे समय तक सूखा पड़ने और चरम मौसम की घटनाएं भी जल उपलब्धता को प्रभावित कर रही हैं और जल उपलब्धता के बारे में अनुमानों को कम विश्वसनीय बना रही हैं।

प्रशासनिक पुनर्गठन से ऐतिहासिक समझौतों पर असहमति भी उत्पन्न हो सकती है। बिहार-झारखंड संबंधों के मामले में भी यही स्थिति है। एक ही प्रशासनिक ढांचे के भीतर हुए समझौतों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है यदि राज्यों का पुनर्गठन हो और उनकी कृषि, जनसंख्या और आर्थिक आवश्यकताएं विकसित हों। दशकों पहले प्रचलित निष्पक्षता की अवधारणा वर्तमान संदर्भ में लागू होना आवश्यक नहीं है।

संघर्ष का एक अन्य बड़ा कारण ऊपरी इलाकों में चल रही परियोजनाओं का विकास और उनका उपयोग है। बांधों, बैराजों और सिंचाई योजनाओं के कारण निचले इलाकों में पानी की मात्रा और निकासी का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। सूचना साझाकरण और राज्यों के बीच परियोजना समन्वय के अभाव में, तकनीकी कार्य में निपुणता भी अविश्वास का कारण बन सकती है।

पारदर्शी और वास्तविक समय के जलवैज्ञानिक आंकड़ों की अनुपलब्धता विवादों को और बढ़ा देती है। राज्यों के बीच आवंटित जल की मात्रा और उपलब्ध जल की मात्रा को लेकर अलग-अलग लक्ष्य हो सकते हैं। यदि वर्षा की मात्रा, नदी के प्रवाह, जलाशयों के स्तर और जल उपयोग के बारे में कोई साझा, वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो बातचीत आसानी से परस्पर विरोधी मांगों पर बहस में बदल सकती है।

अगर लोग राजनीतिक रूप से संगठित हो जाते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। पानी का मुद्दा भावनात्मक है और इसका किसानों, परिवारों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर तकनीकी समस्या क्षेत्रीय मुद्दा या राजनीतिक विवाद बन जाती है, तो समझौता करना मुश्किल हो जाता है। संस्थागत संवाद का यही उद्देश्य है, ताकि यह एक लंबा संघीय संघर्ष न बन जाए।

सोन नदी के लिए बिहार-झारखंड का दर्जा समझौता वार्ता के महत्व का एक उदाहरण है। दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से समाधान खोजने के लिए एक-दूसरे से संपर्क साधकर अहिंसक तरीके से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार को 575 करोड़ एकड़-फीट (ऋ्फ) और झारखंड को 2 करोड़ एकड़-फीट (ऋ्फ) जल आवंटन प्राप्त हुआ है। लेकिन इस समझौते का प्रभाव केवल इन आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी हैं। इसका वास्तविक महत्व यह संदेश देना है कि राज्य अपने हितों की रक्षा करने के साथ-साथ अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को भी समझने में सक्षम हैं। बातचीत से साझा अवसंरचना के बेहतर उपयोग के अवसर भी मिल सकते हैं। खंडित जल प्रबंधन की बजाय समन्वित जल प्रबंधन से इंद्रपुरी बैराज और उससे जुड़े नहर नेटवर्क से अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साझा अवसंरचना को सहयोग का आधार बनना चाहिए, न कि विभाजन का नया कारण।

अब भारत के लिए राज्य-आधारित दृष्टिकोण से हटकर नदी-बेसिन-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का समय आ गया है। नदी बेसिन एक एकल पारिस्थितिक-आर्थिक इकाई है। इसलिए जल नियोजन के लिए नदी के ऊपरी और निचले समुदायों, भूजल, पर्यावरणीय प्रवाह, कृषि, पेयजल और औद्योगिक उपयोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, जलविज्ञानीय डेटा साझा करने की खुली और अद्यतन प्रक्रियाओं को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। रुचि रखने वाले सभी राज्यों को एक ही विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी नदियों की निगरानी की सटीकता में सुधार करने और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा पर विवाद को कम करने में सहायक हो सकती है।

दूसरे, मध्यस्थता के तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों द्वारा उपलब्ध कराए गए संरचित मंचों का उपयोग मुकदमेबाजी या न्यायिक कार्यवाही से पहले उभरते जल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जा सकता है, जिससे भविष्य के विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। यद्यपि न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर भी बातचीत के माध्यम से किए गए समझौते बदलती परिस्थितियों के अनुरूप होने और दीर्घकालिक संबंधों को बनाए रखने में अधिक सहायक हो सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरराज्यीय नदियों को किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं बल्कि राज्यों द्वारा साझा की जाने वाली एक पारिस्थितिक और आर्थिक प्रणाली के रूप में माना जाना चाहिए। जो राज्य एक ही जल बेसिन साझा करने वाले अन्य राज्यों के हितों की अनदेखी करता है, वह दीर्घकालिक रूप से जल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। सहयोग करना कोई समझौता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।

बिहार-झारखंड सोन समझौता भारत के संघीय भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जब जल विवाद लंबी बातचीत का विषय बन जाते हैं, तो निरंतर संवाद, विश्वसनीय जानकारी और प्रभावी सहकारी संस्थानों के माध्यम से साझेदारी के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। नदियाँ राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानतीं। हमें जल प्रबंधन में इन सीमाओं से ऊपर उठना होगा। भारत में जल सुरक्षा नदियों पर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नहीं, बल्कि जल के प्रति साझा जिम्मेदारी से प्राप्त की जा सकती है।

रक्षा समझौते की आड़ में पाकिस्तान का बढ़ता सैन्य जमावड़ा

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लंबे समय से दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सैन्य तैयारियों का विस्तार लगातार जारी है। सऊदी अरब और तुर्किये के साथ हाल में हुए रक्षा सहयोग ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए यह साझेदारी केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित दिखाई नहीं देती, बल्कि आधुनिक ड्रोन, मिसाइल तकनीक और लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यही वजह है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ इस नए सैन्य समीकरण को गंभीरता से देख रहे हैं। अगस्त में पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य हवाई अड्डों पर तुर्किये के सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही ने भी इन आशंकाओं को बढ़ाया है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ ही दिनों के भीतर तुर्किये के सी-130 और ए-400एम जैसे परिवहन विमानों ने पाकिस्तान के अलग-अलग एयरबेस का इस्तेमाल किया। इस गतिविधि को दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि हथियारों की वास्तविक मात्रा और पूरी खेप के बारे में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक और उपकरणों का सहयोग कोई नई बात नहीं है। तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार बन चुका है। ड्रोन तकनीक से लेकर नौसैनिक परियोजनाओं और लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण तक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। पाकिस्तान को तुर्किये की बायरक्तार टीबी2 और अकिंसी जैसी ड्रोन प्रणालियों में रुचि है। इन प्लेटफॉर्मों की खासियत यह है कि इनका इस्तेमाल निगरानी के साथ-साथ सटीक हमलों के लिए भी किया जा सकता है। अकिंसी जैसे भारी ड्रोन अपेक्षाकृत अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम हैं और लंबी अवधि तक अभियान में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही तुर्किये की केमांकेश जैसी मानव रहित क्रूज मिसाइल तकनीक भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसी प्रणालियां आधुनिक युद्ध में पारंपरिक हथियारों से अलग भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इन्हें लक्ष्य की पहचान और सटीक हमले के लिए आधुनिक सेंसर तथा मार्गदर्शन तकनीक से जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस तरह की तकनीक हासिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में ड्रोन और मानवरहित प्रणालियां युद्ध की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। तुर्किये का सहयोग केवल नए हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने और उनके एवियोनिक्स तथा हथियार प्रणालियों को आधुनिक बनाने में भी तुर्किये की भूमिका रही है। पुराने लड़ाकू विमानों की सेवा अवधि और परिचालन क्षमता बनाए रखना किसी भी वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से पाकिस्तान अपने मौजूदा सैन्य संसाधनों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता है। इस समझौते को तीनों देशों के बीच रणनीतिक और सैन्य सहयोग को संस्थागत रूप देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यदि किसी एक साझेदार की सुरक्षा पर गंभीर संकट आता है तो अन्य देशों के समर्थन का प्रावधान इस समझौते को सामान्य रक्षा सहयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इसी कारण इसकी तुलना कई स्तरों पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से की जा रही है, हालांकि इसे सीधे नाटो का विकल्प मानना जल्दबाजी होगी। इस गठजोड़ में तीनों देशों की अलग-अलग ताकतें हैं। सऊदी अरब के पास आर्थिक संसाधन और ऊर्जा क्षेत्र में प्रभाव है। तुर्किये के पास मजबूत सैन्य ढांचा, रक्षा उद्योग और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का अनुभव है। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना, परमाणु क्षमता और मिसाइल प्रणालियों का व्यापक आधार है। यदि इन तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा होता है तो पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक इसका रणनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान की घरेलू आर्थिक स्थिति इस सैन्य विस्तार को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। देश कर्ज, महंगाई और राजकोषीय दबाव से जूझ रहा है। इसके बावजूद रक्षा बजट में वृद्धि हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का सैन्य खर्च 2025 में करीब 11.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि थी। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच भी इस्लामाबाद अपनी सुरक्षा और सैन्य क्षमता को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान के लिए सैन्य आधुनिकीकरण का एक बड़ा कारण भारत के साथ उसका लगातार बना हुआ रणनीतिक तनाव भी है। हालिया सैन्य घटनाक्रमों के बाद पाकिस्तान अपनी वायु रक्षा, ड्रोन क्षमता और सटीक हमले की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आधुनिक युद्ध में बड़ी संख्या में पारंपरिक सैनिकों के बजाय निगरानी ड्रोन, स्वचालित प्रणालियां, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं। इसलिए पाकिस्तान का ध्यान इन क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ाने पर होना स्वाभाविक है। लेकिन पाकिस्तान की चुनौती केवल बाहरी मोर्चे तक सीमित नहीं है। बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहा विद्रोह इस समय उसके लिए गंभीर आंतरिक सुरक्षा संकट बना हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे हथियारबंद समूहों की गतिविधियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार दबाव बनाया है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। यहां सुरक्षा की चुनौती का सीधा संबंध पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संसाधनों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं से भी जुड़ जाता है। बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना पर लगातार दबाव है। पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए समस्या यह है कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस संकट का स्थायी समाधान आसान नहीं है। क्षेत्रीय असंतोष, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों के बंटवारे और विकास से जुड़े सवाल भी लंबे समय से उठते रहे हैं। यदि इन मुद्दों का राजनीतिक समाधान नहीं खोजा गया तो सैन्य अभियानों के बावजूद अस्थिरता बनी रह सकती है। यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य क्षमता और उसकी आंतरिक कमजोरियां एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। एक तरफ देश अत्याधुनिक ड्रोन और मिसाइल तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसे अपने ही एक बड़े प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सैन्य संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। आर्थिक दबाव के बीच रक्षा खर्च बढ़ाना भी सरकार के लिए आसान फैसला नहीं है। तुर्किये के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी का एक दूसरा पहलू चीन से उसके पारंपरिक रक्षा संबंध भी हैं। पाकिस्तान अब एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय चीन, तुर्किये और अन्य साझेदारों से अलग-अलग सैन्य तकनीक हासिल करने की रणनीति अपना रहा है। इससे उसे विकल्प मिलते हैं और अपनी सैन्य जरूरतों के मुताबिक विभिन्न प्रणालियों को जोड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। दक्षिण एशिया के लिए इस बदलते समीकरण का अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारी अब केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रह गई है। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लक्ष्य पहचान, लंबी दूरी की मिसाइलें और आधुनिक एवियोनिक्स जैसे क्षेत्र आने वाले समय में उसकी रणनीति के केंद्र में रह सकते हैं। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम निगरानी और तकनीकी तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि किसी भी रक्षा समझौते को केवल हथियारों की खरीद के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे आर्थिक हित, क्षेत्रीय राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और बदलते वैश्विक गठजोड़ भी काम करते हैं।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये का उभरता त्रिकोण इसी व्यापक बदलाव का संकेत है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सहयोग केवल रक्षा खरीद और सैन्य अभ्यास तक सीमित रहता है या तीनों देशों के बीच साझा सैन्य रणनीति का रूप लेता है। पाकिस्तान के लिए असली चुनौती आधुनिक हथियार हासिल करना भर नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने की आर्थिक क्षमता, प्रशिक्षण, रखरखाव और दीर्घकालिक सैन्य रणनीति तैयार करना भी है। हथियारों का जखीरा किसी देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। आर्थिक स्थिरता, मजबूत संस्थाएं, राजनीतिक सहमति और आंतरिक शांति भी उतनी ही जरूरी हैं। यदि पाकिस्तान इन मोर्चों पर कमजोर रहता है तो बढ़ता सैन्य खर्च उसकी ताकत बढ़ाने के बजाय आर्थिक बोझ को और भारी कर सकता है। मक्का रक्षा समझौते और तुर्किये से बढ़ते सैन्य सहयोग ने पाकिस्तान की रणनीतिक दिशा को जरूर बदलने का संकेत दिया है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान कितने ड्रोन या कितनी मिसाइलें हासिल करता है। बड़ा सवाल यह है कि वह इन सैन्य क्षमताओं को किस रणनीति के तहत इस्तेमाल करता है और क्या उसकी अर्थव्यवस्था इस बढ़ती रक्षा महत्वाकांक्षा का बोझ उठा पाएगी। दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए भी यही आने वाले समय की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होगी।

-कांतिलाल मांडोतसोन जल

आवक घटने और त्योहारी मांग बढ़ने से सोयाबीन तिलहन के भाव में हुआ सुधार

-बिनौला तेल टूटा, सरसों और मूंगफली तेल-तिलहन के भाव बने रहे स्थिर

नई दिल्ली। बाजार में सोयाबीन की आवक घटने और त्योहारी मांग बढ़ने से बीते सप्ताह सोयाबीन तिलहन के भाव में हल्का सुधार दर्ज किया गया। औद्योगिक मांग बढ़ने और अन्य खाद्य तेलों की तुलना में सस्ता होने के कारण कच्चे पाम तेल और पामोलीन की कीमतों में भी तेजी रही। दूसरी ओर आयातकों द्वारा लागत से नीचे बिकवाली किए जाने से सोयाबीन तेल के भाव दबाव में रहे जबकि ऊंची कीमतों पर मांग कमजोर पड़ने से बिनौला तेल भी टूट गया। सुस्त कारोबार के बीच सरसों और मूंगफली तेल-तिलहन के भाव स्थिर बने रहे।

सूत्रों के मुताबिक सप्ताहांत में मंडियों में सोयाबीन की आवक घटकर 40-45 हजार बोरी रह गई, जबकि दैनिक मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है। आवक कम होने और त्योहारी मांग के कारण सोयाबीन तिलहन में मामूली मजबूती आई। सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव 25-25 रुपए बढ़कर क्रमशः 6,700-6,750 रुपए और 6,550-6,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।

वहीं, आयातकों की लागत से नीचे बिक्री का असर सोयाबीन तेल पर पड़ा। सूत्रों के मुताबिक सोयाबीन डीगम के आयात की लागत करीब 125 रुपए प्रति किलो बैठती है, जबकि आयातक इसे करीब 118.50 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में सोयाबीन तेल 150 रुपए घटकर 15,600 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। सोयाबीन इंदौर तेल भी 150 रुपए टूटकर 15,400 और सोयाबीन डीगम 200 रुपए गिरकर 11,850 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

औद्योगिक मांग बढ़ने और दूसरे खाद्य तेलों की तुलना में पाम तेल सस्ता होने से सीपीओ और पामोलीन के भाव मजबूत हुए। सीपीओ 150 रुपए बढ़कर 14,100 रुपए प्रति क्विंटल, पामोलीन दिल्ली 150 रुपए बढ़कर 16,000 रुपए और पामोलीन एक्स-कांडला 100 रुपए बढ़कर 14,700 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ऊंचे भाव पर लिवाली कमजोर रहने से बिनौला तेल 400 रुपए गिरकर 16,500 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। दूसरी ओर सरसों दाना 8,300-8,350 रुपए और सरसों तेल दादरी 16,800 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल क्रमशः 2,735-2,835 रुपए और 2,735-2,885 रुपए प्रति 15 किलो टिन पर बंद हुए। मूंगफली तिलहन 7,350-7,925 रुपए, मूंगफली तेल गुजरात 17,000 रुपये प्रति क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,680-2,980 रुपए प्रति टिन पर स्थिर रहे।

पिछले एक महीने में सोना, चांदी और बिटकॉइन ने निवेशकों को दिया अच्छा रिटर्न

-बिटकॉइन 26 फीसदी चढ़कर 80,000 डॉलर के स्तर के पार पहुंच गया

नई दिल्ली। पिछले एक महीने में सोना, चांदी और बिटकॉइन ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। सोने की कीमत करीब 7.6 फीसदी और चांदी की कीमत करीब 6 फीसदी बढ़ी है। वहीं बिटकॉइन करीब 26 फीसदी चढ़कर दोबारा 80,000 डॉलर के स्तर के पार पहुंच गया है। हालांकि, अब इन परिसंपत्तियों की तेजी के सामने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी बड़ी चुनौती बन सकती है।

सीएमई फेडवॉच के मुताबिक बाजार में इस साल के आखिर तक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की करीब 58 फीसदी संभावना जताई जा रही है। एक महीने पहले यह अनुमान करीब 45 फीसदी था। ब्याज दर बढ़ने पर अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड और डॉलर मजबूत हो सकते हैं। ऐसे में बिना ब्याज देने वाले सोने और चांदी की तुलना में बॉन्ड निवेशकों को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। बिटकॉइन जैसी जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर भी ऊंची ब्याज दरों का दबाव पड़ सकता है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सोने की स्थिति कुछ अलग हो सकती है। दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बनी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी विश्लेषक मानव मोदी के मुताबिक सोने और चांदी को अभी भी मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है, लेकिन फेड का सख्त रुख निकट अवधि में कीमतों के लिए चुनौती बन सकता है। केंद्रीय बैंक भी सोने की मांग को सहारा दे रहे हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई तक केंद्रीय बैंकों ने करीब 130 टन सोना खरीदा है। चीन समेत कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार अपने स्वर्ण भंडार में इजाफा कर रहे हैं।

असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट के सिद्धार्थ भामरे के मुताबिक डॉलर सूचकांक फिलहाल स्थिर है, लेकिन निवेशकों का डॉलर पर भरोसा पूरी तरह मजबूत नहीं है। ऐसे में सोने और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की ओर आकर्षण बना रह सकता है। सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व शेठ का मानना है कि अमेरिका के भारी कर्ज के कारण फेड के लिए ब्याज दर बढ़ाना आसान फैसला नहीं होगा। उनके मुताबिक डॉलर की क्रय शक्ति कमजोर होने पर सोने की मांग और बढ़ सकती है। बिटकॉइन को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी-कर्मचारियों का बढ़ेगा 3 फीसदी डीए

नई दिल्ली। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी ने अपने अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के महंगाई भत्ते में करीब 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस फैसले से बोकारो स्टील प्लांट समेत देश में फैली सेल की अन्य सभी यूनिट्स में कार्यरत करीब 54 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। डीए में इस बढ़ोतरी के बाद सेल-कर्मियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 55.7 फीसदी से बढ़कर 58.6 फीसदी हो जाएगा।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 382, निफ्टी 118 अंक गिरा

मुम्बई । भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से भी बाजार पर दबाव आया है।

इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 382.62 अंक नीचे आकर 76,132.81 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 118.55 अंक टूटकर 23,779.15 के स्तर पर बंद हुआ।

आज के सत्र में कुल 4729 शेयरों में कारोबार हुआ। इसमें गिरावट वाले शेयरों की संख्या बढ़त वाले शेयरों से ज्यादा थी। 2470 शेयरों में लाल निशान पर कारोबार समाप्त हुआ, जबकि 2018 शेयरों में तेजी रही। वहीं 241 शेयरों में कोई बदलाव नहीं आया। निफ्टी पर सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंशियल और एचडीएफसी लाइफ के शेयर रहे जबकि अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल, एलएंडटी, कोल इंडिया और मैक्स हेल्थकेयर के शेयरों में तेजी रही।

फार्मा सेक्टर ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जो बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक और रियल्टी जैसे सभी प्रमुख सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में भी 0.5 फीसदी की गिरावट आई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में बदलाव नहीं हुआ। ये बाजार में बिकवाली के दबाव को दिखाता है।

बाजार में इस गिरावट के पीछे । वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ी वजह बनकर उभरी, जो 0.78 प्रतिशत बढ़कर 97 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ाती हैं, जिसका असर शेयर बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे, जबकि एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला - दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई बढ़त में रहे, लेकिन शंघाई और हांगकांग के सूचकांक लाल निशान पर थे।

विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार दूसरे सत्र में बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। शुक्रवार को विदेशी निवेशकोंने भारतीय इक्विटी बाजार से 3,111.94 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। वहीं इससे पहले आज सुबह भी घरेलू बाजार गिरावट के साथ खुला था। सुबह सेंसेक्स 133.65 अंक की गिरावट के साथ 76,381.78 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी50 भी 47.30 अंक नीचे आकर 23,850.40 के स्तर पर पहुंच गया।

रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतें स्थिर, पर व्यावसायिक सिलेंडर महंगा हुआ

नई दिल्ली। रसोई गैस के उपभोक्ताओं के लिए सोमवार को एक मिश्रित खबर सामने आई है। जहां एक ओर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे लाखों परिवारों को तत्काल राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह स्थिति विभिन्न आर्थिक वर्गों पर अलग-अलग तरह से असर डालेगी, खासकर उन कारोबारियों के लिए जिनकी ईंधन लागत सीधे तौर पर उनके उत्पादों और सेवाओं की कीमत को प्रभावित करती है।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर आज भी 942 रुपये में उपलब्ध है, इसकी कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

हालांकि, यह राहत सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित है। होटल, रेस्तरां, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हुई है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 2747.50 रुपये का मिलेगा, जबकि पिछले महीने इसकी कीमत 2738 रुपये थी। इस प्रकार, प्रति सिलेंडर 9.50 रुपये की मामूली लेकिन महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह वृद्धि सीधे तौर पर इन व्यवसायों की परिचालन लागत को बढ़ाएगी। ईंधन की लागत में वृद्धि होने से इन कारोबारी इकाइयों का कुल खर्च बढ़ सकता है, जिसका संभावित असर ग्राहकों के लिए खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव सेवा क्षेत्र पर पड़ेगा, जहां भोजन और पेय पदार्थ तैयार करने में गैस एक प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग होती है। इससे व्यवसायों को अपनी लाभप्रदता बनाए रखने के लिए या तो खर्च का बोझ खुद उठाना होगा, या फिर इसे ग्राहकों पर डालना पड़ सकता है।

मेष राशि- आज का दिन नई उम्मीद और राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आखिरकार पूरा होने से मन हल्का और खुश महसूस करेगा। जीवनसाथी के साथ चल रही दूरियां बातचीत और समझदारी से कम होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास लौटेगी। आप दोनों भविष्य को लेकर साथ बैठकर नई योजनाएं बना सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा है। किसी बड़े पद, जिम्मेदारी या सम्मान की प्राप्ति से आत्मविश्वास काफी बढ़ सकता है।

वृषभ राशि-आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात आपके करियर या कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। हालांकि, दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। संतान की नौकरी में तरक्की से परिवार में गर्व और खुशी का माहौल बनेगा। पुराने प्यार से अचानक मुलाकात भावनाओं को जगा सकती है, लेकिन बीती बातों में ज्यादा उलझना ठीक नहीं रहेगा।

मिथुन राशि-आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर फैसला लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। विरोधियों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाएं। संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। नौकरी में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए जूनियर का सहयोग भी काफी उपयोगी रहेगा।

कर्क राशि-आज वैवाहिक जीवन में प्यार, समझ और आपसी सहयोग का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलेगा। माताजी से किया हुआ कोई वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतोष होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार बन सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। कारोबार में आपके नए विचार नई ऊंचाइयों का रास्ता खोल सकते हैं।

सिंह राशि-आज खुशियां और उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में अपनापन और मजबूती बढ़ाएगा। लंबे समय से अटकी हुई बिजनेस डील आखिरकार फाइनल होने की उम्मीद है।

कन्या राशि-आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका अच्छा साथ दे सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं और आय में बढ़ोतरी से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के लिए कोई खास चीज खरीदना रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाएगा। हालांकि निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें और पूरी जानकारी के बाद ही कदम उठाएं।

तुला राशि-आज दिन काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रह सकता है। कोशिश करें कि जरूरी काम खुद संभालें और हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। किसी पार्टी या समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, जहां आपकी बातचीत और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेंगे। यात्रा या घूमने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है।

वृश्चिक राशि-आज सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए खान-पान और आराम पर विशेष ध्यान दें। अचानक किसी यात्रा की योजना बन सकती है। कारोबार की कोई पुरानी समस्या भाई-बहनों के सहयोग से सुलझने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के भीतर कुछ नया सीखने और अलग करने की इच्छा जागेगी, जो आगे उनके लिए फायदेमंद हो सकती है।

धनु राशि-आज मन की कोई इच्छा पूरी न होने से थोड़ी बेचैनी या निराशा महसूस हो सकती है। काम में भी मन कम लगे तो खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना बेहतर होगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए बहस के बजाय धैर्य से बात करें।

मकर राशि-आज अचानक धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराना अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी खबर का इंतजार खत्म हो सकता है। घर में नए मेहमान के आने से खुशियों की रौनक बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ चल रही खटास को दूर करने के लिए आप दिल से प्रयास करेंगे। हालांकि, किसी सहयोगी की कही बात आपको थोड़ी परेशान या भावुक कर सकती है।

कुंभ राशि-आज का दिन सामान्य से बेहतर और कुछ नई संभावनाओं वाला रह सकता है। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं। संतान ने किसी परीक्षा में हिस्सा लिया था तो उसका परिणाम आपके लिए खुशी लेकर आ सकता है। नई नौकरी के लिए किया गया प्रयास भी सफल होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुल सकते हैं और भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और जरूरत न हो तो किसी भी परिस्थिति में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा।

मीन राशि-आज कारोबार में उतार-चढ़ाव के कारण मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें और किसी भी दस्तावेज या समझौते को बिना पढ़े स्वीकार न करें। दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें। पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को शांति मिलेगी।

शब्दजाल - 8374

रि	अ	मे	क	अ	मि	ता	भ	व	च्च	न
ति	भि	क	म	क्ष	डे	ने	ज	ति	मा	ला
क	षे	र	ला	य	ग	अं	द	ह	प	आ
रो	क	ल	का	कु	न	स	ध	ह	लि	मि
श	ब	स	ल	मा	न	खा	न	का	न	र
न	च्च	का	र	र	ल	का	त	ह	र	खा
र	न	ल	मा	व	शा	ह	रु	ख	खा	न
र	ज	भा	र	न	प	स	रा	ल	वि	ला
क	न	नी	अ	सै	फ	अ	ली	खा	न	दे
र	का	ति	कां	न	शा	हि	द	क	पू	र
बां	र	ल	प	त	स	स	ता	प	र	र

शब्द जाल में ऐसे 10 अभिनेता ढूंढिए जो सर्वाधिक पारिश्रमिक लेते हैं. नाम ऊपर से नीचे एवं तिरछे हैं.

अमिताभ बच्चन, रितीक रोशन, शाहरुख खान, रजनीकांत, आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर

शब्दजाल -8373 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7318

बायें से दायें:-

१. जॉय मुखर्जी, नंदा की 'मुझे इश्क है तुम्हीं से' गीत वाली फिल्म-३
३. 'मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो' गीत वाली राजकपूर, नूतन की फिल्म-३
६. आमिर, फैजल, ट्विंकल की 'तुझे रब ने बनाया है' गीत वाली फिल्म-२
७. अमिताभ, जीनत अमान की फिल्म-२
८. 'तसवीर बनाता हूँ' गीतवाली फिल्म-४
९. 'जब लिया हाथ' गीत वाली राजेंद्र कुमार, गीता बाली की फिल्म-३
११. राजकुमार, प्रिया की 'ये पर्वतों के दायरे ये शाम' गीत वाली फिल्म-३
१२. 'दिल में जिगर में' गीत वाली संजय, जैकी, शिल्पा, रवीना की फिल्म-२
१३. विकास भल्ला, सुमीत, की 'कोई दिल ना किसी' गीत वाली फिल्म-२
१४. 'काहे कोयल शोर मचाये' गीत वाली राजकपूर, नर्गिस की फिल्म-२
१५. विश्वजीत, माला सिन्हा की फिल्म-३
१७. राजकुमार, मीना की 'चलते चलते यूंही कोई मिल' गीत वाली फिल्म-३
१९. जैकी श्रॉफ, रति की फिल्म-२
२१. ऋषिकपूर, अल्बाज, जूही की 'ये प्यार पार क्या' गीत वाली फिल्म-३
२२. 'ना सताना से ऊपर ना' गीत वाली नवीन निश्चल, रेखा की फिल्म-२
२३. 'दुपट्टे का पल्लू' गीतवाली फिल्म-४
२६. फिल्म 'दोस्ताना' में अमिताभ की नायिका ?-३
२७. अभिषेक, अंतरा माली की 'इश्क दा तड़का' गीत वाली फिल्म-२
२८. 'मेरे दिल में रहो या जिगर' गीत वाली अस्मित, मीरा की फिल्म-३
२९. गुरुदत्त, वहीदा रहमान की 'जाने क्या तूने कही' गीत वाली फिल्म-२
३०. 'देर है अंधेर नहीं' गीत वाली शत्रुघ्न, राजकपूर, योगिता की फिल्म-२,२
३१. फिल्म 'सलाखें' में नायक ?-२

ऊपर से नीचे:-

१. 'मन क्यों बहका रे' गीत वाली शशि शेखर सुमन, रेखा, नीना की फिल्म-३
२. मिथुन, जुगल, सोनाली की 'तेरे चाहत में दिल' गीत वाली फिल्म-१,२
४. 'सीली हवा छू गई सीला' गीत वाली नसीर, शबाना आज़मी की फिल्म-३
५. अमिताभ, अमजद खान, नीतू की 'छूकर मेरे मन' गीत वाली फिल्म-३
६. 'बोल बेबी बोल रॉक' गीत वाली अनिल कपूर, मीनाक्षी की फिल्म-२,२
१०. धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की 'राजा ना जा ना जा' गीत वाली फिल्म-३
११. 'मैं इश्क उसका' गीत वाली अर्जुन रामपाल, जायेद, अमीषा की फिल्म-२
१४. धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की 'मैं लैला का मजनूं' गीत वाली फिल्म-३
१५. 'कोरा कागज था मन' गीत वाली राजेश खन्ना, शर्मिला की फिल्म-४
१६. संजय कपूर, माधुरी की 'फूल मांगू ना बहार मांगू' गीत वाली फिल्म-२
१७. 'दिले बेताब को सीने से' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वहीदा की फिल्म-३
१८. अमिताभ, अक्षय, जॉन, सिमी की 'फलक देखूं' गीत वाली फिल्म-३,३
२०. फिल्म 'देवी' में नायिका कौन थी-३
२४. 'अँखियां मिलाके जिया' गीत वाली फिल्म-३
२५. नसीर, अस्मित, उर्मिला की फिल्म-४
२६. 'शहर शहर डगर डगर' गीत वाली जैकी, संजय, सोनम की फिल्म-२,१

फिल्म वर्ग पहेली- 7317

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

8 सितम्बर को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

मंगलवार 2026 वर्ष का 251 वा दिन दिशाशूल उत्तर ऋतु वर्षा। विक्रम संवत् 2083 शक संवत् 1948 मास भाद्रपद (दक्षिण भारत में श्रावण) पक्ष कृष्ण तिथि द्वादशी 14.44 बजे को समाप्त। नक्षत्र पुष्य 16.40 बजे को समाप्त। योग परिघ 00.41 बजे रात्र को समाप्त। करण तैतिल 14.44 बजे ...

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः मन की साधना

चतुर्मास का समय निकट आया तो भिक्षु सुशांत ने बुद्ध से आग्रह किया, 'प्रभु, मैं नगरवधू सोमलता के सान्निध्य में अपना चतुर्मास व्यतीत करना चाहता हूं। कृपया इसकी आज्ञा प्रदान करें।' यह सुनकर बुद्ध मुस्कराए। वह समझ गए कि यह वहां जाकर मन को साधकर सच्चा साधक होना चाहता है। लेकिन अन्य भिक्षुओं ने इस पर आपत्ति जताई। उन्हें संदेह था कि सुशांत कहीं अपने पथ से विचलित न हो जाए। पर बुद्ध ने भिक्षुओं के विरोध के बावजूद उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, 'जाओ और आगे बढ़कर आना।' सुशांत सोमलता के पास पहुंचा। वहां सब उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन सुशांत अपने संकल्प पर अडिग था। इधर सोमलता के घुंघरुओं की आवाज गूंजती और उधर सुशांत अपनी साधना में लीन रहता। सोमलता सुशांत को रिझाने का प्रयास करती, मगर वह निर्लिप्त रहता। एक मास गुजर गया मगर सोमलता सुशांत को डिगा न सकी। हां, उससे थोड़ी सहानुभूति अवश्य होने लगी। उसने दूसरों को भी साधना के क्षणों में शांत रहने को कह दिया। चौथा मास आते-आते सुशांत ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया था। वह सोमलता या अन्य सुंदरियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था। संगीत उसे बुद्ध-वाणी की तरह लगता था और नृत्यालय देवालय की तरह। चार मास पूर्ण हुए और सुशांत अपने मठ की ओर वापस चला तो सबने आश्चर्य से देखा- भिक्षुणी बनी सोमलता उसके पीछे-पीछे अपना सर्वस्व त्याग कर जा रही थी। सोमलता अपने रूप-रंग से सुशांत को रिझा न सकी, मगर सुशांत के तप का प्रभाव सोमलता पर दिख रहा था। सुशांत वास्तव में आगे बढ़ गया था।

सूडोकु नवताल- 7627

मध्यम

9		6		3		4		8
	2				9		7	
4			1	6				2
		8			2		3	
1		4				2		5
	3		5			8		
7				9	5			3
	8		6				4	
6		2		7		5		1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7626 का हल

3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7

शब्द पहेली - 8842

बाएँ से दाएँ

1. ध्वज, पताका-2
4. वहम, संदेह-2
6. दलहन-2
7. खाली, रिक्त-2
9. रसूल, अल्लाह-3
12. अभिनेत्री मुनमुन सेन की पुत्री का सिर्फ नाम-3
14. सिवाय, बगैर-3
16. इराक की राजधानी-4
17. समधी की पत्नी-4
18. पीसना, महीन करना-3
20. उष्ण, गर्म-3
22. उत्तम, विष्णु अवतार-3
24. परत, तह-2
26. खेती-2
27. अधर, होठ-2
28. ताऊ की पत्नी, बड़ी मां-2

ऊपर से नीचे

1. जल प्रपात-3
2. आईल-2
3. हूर, अप्सरा-2
5. सूक्ति, वाणी, शबद-3
6. पिता के पिता-2
8. स्टार, सितारा-2
10. रोचक, सुंदर, मनोहारी-5
11. शीतलता, मुठभेड़-2
13. सतरंगा, शंकर धनुष-5
14. सिर्फ एक, एकमात्र-3
15. हवस, कामेच्छा-3
19. लाख-2
20. जहर, विष-3
21. आनंदित, मनमौजी-2
22. मुनि, साधू-2
23. अच्छाई, सदाशयता-3
25. सुरक्षा-2
26. कीड़ा, कीट-2

शब्द पहेली -8841 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

12 हजार बोरी अमानक सुपरफास्फेट खाद वितरित

किसानों का आरोप–खाद में पोषक तत्व नहीं, धान की पत्तियां पीली और फसल कमजोर; खरीदी की राशि लौटाने व क्षतिपूर्ति की मांग

पद्मेश न्यूज। लांजी। खरीफ सीजन में किसानों को राहत देने के लिए उपलब्ध कराया गया सुपरफास्फेट खाद अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। म.प्र. राज्य विपणन संस्था द्वारा सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किए गए सुपरफास्फेट के एक लॉट को प्रयोगशाला जांच के बाद अमानक घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि अमानक खाद का उपयोग किसान धान की फसल में पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद कई खेतों में धान की पत्तियां पीली पड़ने और फसल कमजोर होने की स्थिति दिखाई दे रही है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश एवं जिले में ब्लू फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, माऊली (उदयपुर) से म.प्र. राज्य विपणन संस्था द्वारा प्राप्त सुपरफास्फेट को प्रयोगशाला जांच के बाद अमानक घोषित किया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक खाद की गुणवत्ता पर सवाल सामने आए, तब तक बड़ी मात्रा में इसका उपयोग खेतों में हो चुका था। इससे किसानों के सामने खाद पर खर्च की गई राशि के साथ-साथ फसल प्रभावित होने का दोहरा संकट खड़ा हो गया है।

17 समितियों के माध्यम से करीब 12 हजार बोरियों का वितरण

जनपद पंचायत लांजी के सभापति दिनेश लाड़े एवं किसान कांग्रेस लांजी अध्यक्ष मानिक पांचे ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लांजी क्षेत्र की करीब 17 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 12 हजार बोरी सुपरफास्फेट खाद किसानों को वितरित की गई है। उनका आरोप है कि अमानक खाद का उपयोग किसानों के लिए गंभीर आर्थिक नुकसान का कारण बन रहा है।

उन्होंने मांग की है कि अमानक खाद से जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है, उन्हें फसल क्षति की भरपाई के रूप में क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। साथ ही किसानों द्वारा इस खाद को खरीदने में खर्च की गई पूरी राशि वापस कराई जाए।

डबल लॉक गोदाम से भी 700 बोरी वितरण

मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार लांजी स्थित डबल लॉक खाद गोदाम से भी करीब 700 बोरी अमानक सुपरफास्फेट वितरित किया गया है। कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा वितरित खाद की संख्यात्मक जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। इससे अमानक खाद के वितरण का दायरा और किसानों पर संभावित प्रभाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एसडीएम ने कृषि विभाग से कराई पुष्टि

मामले को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से चर्चा की गई। उन्होंने कृषि विस्तार अधिकारी से जानकारी लेकर मामले की पुष्टि कराई। चर्चा के दौरान यह माना गया कि क्षेत्र में किसानों को अमानक खाद का वितरण हुआ है। एसडीएम ने बताया कि मामले में उच्च अधिकारियों से संवाद कर किसानों को राहत एवं भरपाई दिलाने का प्रयास किया जाएगा। फसल क्षति के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रयास जारी रहने की बात कही गई है।

पहले समर्थन मूल्य, अब अमानक खाद ने बढ़ाई चिंता

किसानों का कहना है कि वे पहले से ही समर्थन मूल्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। महंगे उर्वरक, मौसम की बेरुखी और कीट-व्याधि ने खेती की लागत और जोखिम दोनों बढ़ा दिए हैं। ऐसे समय में यदि खेत में डाली गई खाद ही अमानक निकल जाए तो किसान की पूरी मेहनत और लागत पर संकट खड़ा होना स्वाभाविक है। किसानों का कहना है कि अमानक खाद से फसल को हुए नुकसान का आकलन कर जिम्मेदारी तय की जाए और किसानों को तत्काल राहत दी जाए। उनका कहना है कि किसान ने जिस खाद को फसल की ताकत बढ़ाने के लिए खेत में डाला, वही यदि फसल को कमजोर करने का कारण बन जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। किसान नेताओं ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि अमानक खाद की बिक्री एवं वितरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, किसानों से वसूली गई खाद की राशि वापस कराई जाए तथा प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर उचित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।

धान की फसल पर तना छेदक और भूरा माहू का प्रकोप, किसान चिंतित

लगातार बारिश और नमी से बढ़ी कीटों की सक्रियता, समय पर कृषि सलाह की मांग

पद्मेश न्यूज। लांजी। क्षेत्र में लगातार बारिश और मौसम में बनी नमी के बीच धान की फसल पर तना छेदक, भूरा माहू सहित अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ने लगा है। कई खेतों में धान के पौधों की बढ़वार प्रभावित होने और पौधों के सूखने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे किसान फसल को लेकर चिंतित हैं और खेतों में लगातार निगरानी कर रहे हैं। किसानों के अनुसार खरीफ सीजन की शुरुआत में मौसम धान की फसल के लिए अनुकूल रहा, लेकिन लगातार बारिश और खेतों में नमी के कारण कुछ क्षेत्रों में कीट एवं रोगों की सक्रियता बढ़ी है। तना छेदक के प्रकोप से धान की बालियां सफेद व पोची निकलने लगती हैं। ऐसी बालियों को खींचने पर वे आसानी से बाहर आ जाती हैं। वहीं तने की निचली सतह पर कीट की इल्ली द्वारा छोड़ा गया मल भी दिखाई दे सकता है।

भूरा माहू से भी बढ़ी परेशानी

अत्यधिक जलभराव और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण धान में भूरा माहू यानी ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप भी बढ़ सकता है। ये कीट सामान्यतः पानी की सतह से ऊपर पौधे के तने के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पौधे कमजोर होकर सूखने लगते हैं।

कृषि विभाग से मैदानी निरीक्षण की मांग

किसानों ने कृषि विभाग से प्रभावित क्षेत्रों का मैदानी निरीक्षण कर फसल की स्थिति का जायजा लेने तथा तना छेदक, भूरा माहू एवं अन्य कीटों की पहचान और नियंत्रण के संबंध में किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि समय रहते विशेषज्ञों की सलाह मिलने से फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है।

किसानों को सावधानी बरतने की सलाह

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कीट या रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसान बिना सलाह के किसी भी कीटनाशक का प्रयोग न करें। फसल की स्थिति और कीट की पहचान के आधार पर कृषि विभाग अथवा कृषि विशेषज्ञों से अनुशंसित दवा और उसकी मात्रा की जानकारी लेकर ही छिड़काव करें। विशेष रूप से भूरा माहू की स्थिति में खेत में अत्यधिक पानी जमा न रहने दें तथा आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का उपयोग करने से बचें। तना छेदक की पहचान- रोपाई के करीब 20-25 दिन बाद तथा 60-65 दिन की अवस्था में प्रकोप देखा जा सकता है। प्रभावित पौधों में बालियां सफेद होकर आसानी से निकल सकती हैं। भूरा माहू की पहचान- पौधे के निचले तने पर पानी की सतह के ऊपर कीट दिखाई देते हैं। अधिक प्रकोप की स्थिति में पौधों में कमजोरी और सूखने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जरूरी सावधानी- तना छेदक या भूरा माहू के नियंत्रण के लिए किसी भी कीटनाशक का चयन फसल की अवस्था, कीट की संख्या और स्थानीय कृषि विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अलग-अलग कीटों पर सभी दवाएं समान रूप से प्रभावी नहीं होतीं और कुछ दवाओं के अनावश्यक उपयोग से लाभकारी कीटों को नुकसान पहुंच सकता है।

निर्माण इंस्टीट्यूट में राज्य आनंद संस्थान का एक दिवसीय अल्पविराम परिचय कार्यक्रम आयोजित

पद्मेश न्यूज। लांजी। निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी में मध्यप्रदेश शासन के राज्य आनंद संस्थान के तत्वावधान में एक दिवसीय अल्पविराम परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में संस्थान से जुड़े करीब 60 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूतपूर्व वायुसैनिक राजेन्द्र रामटेककर ने की, जबकि सेवानिवृत्त प्राचार्य

सी.एल. विजयवंशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। संस्था की छात्राओं महक ठाकरे, शीतल कालबेले एवं उषा खेरे ने मां सरस्वती की प्रार्थना प्रस्तुत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेन्द्र रामटेककर ने कहा कि आधुनिक मानव भौतिकवाद के कुचक्र में फंसकर जीवन के प्राकृतिक आनंद से दूर होता जा रहा है। ऐसे में अल्पविराम व्यक्ति को कुछ समय स्वयं के साथ जुड़ने और अपनी मानसिक स्थिति को समझने का अवसर देता है। इसके माध्यम से मानसिक उलझनों से बाहर निकलकर जीवन की विभिन्न समस्याओं का सहजता से सामना किया जा सकता है तथा आनंदपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। मुख्य अतिथि सी.एल. विजयवंशी ने विद्यार्थियों को अल्पविराम विधा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि इसे सही ढंग से आत्मसात करने से व्यक्ति तनाव और चिंता से मुक्त रहकर अपने कैरियर पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। आनंदित एवं संतुलित जीवन जीते हुए देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। राज्य आनंद संस्थान की मास्टर ट्रेनर श्रीमती हेमलता विजयवंशी ने विद्यार्थियों को आनंदित एवं सकारात्मक रहने के विभिन्न टूल्स की जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर एवं जिला संपर्क व्यक्ति कमलकांत बिठले ने विद्यार्थियों को जीवन की बैलेंस शीट तैयार करने की प्रक्रिया समझाई। साथ ही विभिन्न खेलों एवं गतिविधियों के माध्यम से अल्पविराम के महत्व को व्यवहारिक रूप से समझाया। आनंदम सहयोगी विनय गोयल ने विद्यार्थियों को राज्य आनंद संस्थान से जुड़ने की प्रक्रिया एवं संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में तोषण मस्करे एवं अजेन्द्र कुमार श्रीरामे ने भी सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक सहभागिता की और अल्पविराम के माध्यम से स्वयं को समझने, मानसिक संतुलन बनाए रखने तथा जीवन में आनंद को महत्व देने के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संचालक कैलाश ब्रम्हपुरे ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।

24 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ का समापन

सद्भावना यात्रा में गूंजा नशामुक्ति का संदेश

पद्मेश न्यूज। लांजी। धर्म सम्राट चेतन पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज के आशीर्वाद से भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वावधान में भारती लॉन परिसर में आयोजित 24 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ 5 एवं 6 सितंबर को आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक जागरूकता का अनूठा संगम देखने को मिला। समापन से पूर्व सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिसमें संगठन से जुड़े शिष्य-भक्तों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरे नगर का भ्रमण कर नशामुक्ति, सामाजिक समरसता और मानव कल्याण के संदेश से जुड़े नारे लगाए गए। यात्रा के बाद सभी श्रद्धालु मुख्य आयोजन स्थल पहुंचे और अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ में शामिल हुए। कार्यक्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी (अनूप भैया) का शंखनाद के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा परिसर मां की भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। समापन अवसर पर बरखा बिल्होरे एवं आरुषि बिसेन ने गुरु एवं मां के जयकारे लगाए।

धर्म और मानवता की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य - सौरभ द्विवेदी

समापन बेला पर केंद्रीय महासचिव सौरभ द्विवेदी ने कहा कि श्री दुर्गा चालीसा का पाठ साधना और शक्ति जागरण का माध्यम है। उन्होंने हिंदू धर्मग्रंथों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य जीवन में गुरु का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र और धर्म की रक्षा के साथ मानवता की सेवा के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़कर प्राप्त हुआ मार्ग दुर्लभ है। वर्तमान समय में समाज को अपने धर्म के प्रति सजग होकर संगठित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने नशामुक्त और संस्कारवान समाज निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन आकाश भारद्वाज ने किया। समापन पर सभी श्रद्धालुओं ने शक्तिजल एवं प्रसाद ग्रहण किया तथा महाप्रसाद का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष जगदीश बिल्होरे ने मां भक्तों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में तहसील संगठन अध्यक्ष पवन पटले सहित मोतीलाल बिसेन, पुरुषोत्तम डहरे, संजय भंडारकर, योगेश माहेश्वरी, गणेश समरिते, खेमेन्द्र गिरी गोस्वामी, पूरनलाल जाम्बूरकर, हुलास राम हेनोते, वीर सिंह धामने, चैनलाल मानकर, डॉनिक राम डोये, हीरामन डोये, मानिक लाल उपराडे, नंदकिशोर लिल्हारे, प्रियंका भंडारकर, देवलता बनोटे एवं योगेश्वरी ठाकरे सहित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला पदाधिकारियों में दिलीप चौधरी, राजेंद्र पंचेश्वर, अभिषेक बिल्होरे, मदनलाल चौधरी, मोहनलाल नगपुरे, राजू चौहान, तुपेश ठाकरे, लोकेश चित्रिव, कैलाश सोनी, किशोर बानेवार, बजरंग सिंह राजपूत, उपेंद्र कटरे, नीमा ठाकरे, रेखा श्रीवास एवं सीता जमारे सहित अन्य कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के गोंदिया, आमगांव एवं सालेकसा क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से भी बड़ी संख्या में शिष्य पहुंचे। आयोजन में उनकी सक्रिय सहभागिता रही। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपने विचार व्यक्त किए।

कौटिल्य एजुकेशन एकेडमी में सम्मान के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस

पद्मेश न्यूज। लांजी। कौटिल्य एजुकेशन एकेडमी स्कूल भानेगांव में 7 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन सम्मान, उत्साह और आत्मीयता के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शिक्षकों एवं संस्था के स्टाफ का तिलक-वंदन कर सम्मान किया। गुरुजनों के प्रति विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त किए गए सम्मान और कृतज्ञता से समारोह भावपूर्ण हो उठा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके मार्गदर्शन और शिक्षा को जीवन में महत्वपूर्ण बताया। विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि अनुशासन, संस्कार, नैतिक मूल्यों और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए संस्था के संचालक महेंद्र कुथे ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव और संस्कारों

के माध्यम से विद्यार्थियों को सही दिशा प्रदान करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन का पालन करने, शिक्षकों का सम्मान करने तथा अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने भी अपने विचार साझा करते हुए विद्यार्थियों को मेहनत, लगन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता ही शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। समारोह के अंत में शिक्षक दिवस के आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ का योगदान सराहनीय रहा।

लांजी में "पद्मेश"
इंटरनेट (ब्राडबैंड)
कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

आखिर शराब में मौत का कौन सा रसायन मिलाया जा रहा

जहरीली शराब की मौतों पर हर बार कार्रवाई, पर जहर का राज अब भी बरकरार

भोपाल। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार और इससे होने वाली मौतें कोई नई समस्या नहीं हैं। सागर में शनिवार को हुई दर्दनाक घटना ने एक बार फिर इस पुराने सवाल को सामने ला दिया है कि आखिर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला मौतों के बाद ही क्यों शुरू होता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि होने के बावजूद कई मामलों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर शराब में कौन सा रसायन मिला था। उज्जैन, मुरैना, मंदसौर और इंदौर में पिछले वर्षों में जहरीली शराब से सामूहिक मौतों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। घटनाओं के बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई, आरोपी पकड़े गए, कहीं अधिकारियों को निलंबित किया गया तो कहीं आरोपियों की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। बावजूद इसके अवैध शराब की सप्लाई का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। अब सागर की घटना के बाद एक बार फिर अवैध शराब के नेटवर्क के साथ-साथ आबकारी और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

जहरीली शराब से मौत की घटनाओं में सबसे अहम सवाल यह होता है कि शराब में ऐसा क्या मिला था, जिससे लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में सामने आए कई पुराने मामलों में शुरुआती जांच में डिनैचर्ड या मेथिलेटेड स्पिरिट जैसे पदार्थों का उल्लेख हुआ, लेकिन संबंधित रसायन की अंतिम और स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक स्तर पर सामने आने को लेकर स्थिति हमेशा साफ नहीं रही। उज्जैन की 2020 की घटना इसका बड़ा उदाहरण रही। शुरुआती रिपोर्टों में मौतों की संख्या

12 से 14 बताई गई थी, जबकि बाद के न्यायिक रिकॉर्ड में 16 मौतों का उल्लेख मिलता है। जांच में डिनैचर्ड/मेथिलेटेड स्पिरिट से संबंध की बात सामने आई और बाद में इथाइल व मिथाइल अल्कोहल के संकेतों का भी उल्लेख हुआ। मुरैना में जनवरी 2021 में छैरा और मनपुर गांवों में अवैध शराब पीने से 24 लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस मामले में आरोपियों को सजा भी हुई, लेकिन घटना के बाद भी यह सवाल बना रहा कि इस्तेमाल किए गए जहरीले मिश्रण की आधिकारिक पहचान और जानकारी आम लोगों तक कितनी स्पष्टता से पहुंची। मंदसौर और इंदौर में भी 2021 में जहरीली शराब से मौतों के बाद जांच और कार्रवाई हुई। मंदसौर के खखराई गांव में मौतों के बाद जांच समिति गठित की गई और आबकारी उपनिरीक्षक को निलंबित किया गया। आरोपी के मकान पर कार्रवाई भी हुई। इंदौर में भी सात लोगों की मौत की घटना सामने आई थी।

मौत के बाद खुलता है नेटवर्क

सागर की घटना में अब जांच जिस दिशा में बढ़ रही है, उसने अवैध शराब के नेटवर्क की सीमा भी सामने ला दी है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक शराब की सप्लाई उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सागर तक पहुंची थी। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को बोतलों में भरकर उस पर नकली रैपर और फर्जी क्यूआर कोड लगाए जाते थे, जिससे वह देखने में असली शराब जैसी लगे। इसके बाद इसे कम कीमत पर मध्य प्रदेश भेजा जाता और स्थानीय स्तर पर महंगे दामों में बेचा जाता था। घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने ललितपुर पुलिस की मदद से छापेमारी कर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए जाने की भी बात सामने आई है।

मई में पकड़ा गया था गिरोह, फिर भी सागर तक पहुंची सप्लाई

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि अवैध शराब का नेटवर्क पहले से पुलिस की नजर में था। मई 2026 में ललितपुर पुलिस ने अवैध शराब बनाने और तस्करी से जुड़े गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सागर और आसपास के इलाकों में नकली शराब खपाने की जानकारी सामने आने का दावा किया गया था। इसके बावजूद कुछ महीने बाद यही नेटवर्क सागर के गांवों तक शराब पहुंचाने में सफल रहा। इससे निगरानी और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बताया गया है कि बांदरी, बढ़ोदिया, गूगरा खुर्द, नौराज और बैराज सहित कई गांवों तक अवैध शराब पहुंचाई जाती थी। नकली रैपर और क्यूआर कोड के जरिए शराब को असली दिखाने की कोशिश की जाती थी।

अब कार्रवाई से आगे जवाबदेही की जरूरत

सागर की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन सक्रिय है, संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं और तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि सिर्फ घटना के बाद गिरफ्तारी और छापेमारी से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। जरूरत इस बात की है कि अवैध शराब के नेटवर्क की सप्लाई चेन, स्थानीय वितरण और उसकी निगरानी में चूक की भी जांच हो। साथ ही जहरीली शराब से हुई मौतों में किस रसायन की मौजूदगी पाई गई, इसकी स्पष्ट वैज्ञानिक और आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक हो, ताकि हर घटना के बाद वही सवाल दोबारा न उठे। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि सागर में शराब कहां से आई; सवाल यह भी है कि जिन इलाकों में पहले से अवैध शराब का नेटवर्क सक्रिय होने की जानकारी थी, वहां उसे समय रहते रोका क्यों नहीं गया।

मप्र के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों में ही होगी दिल की जांच

अब मासूमों जन्मजात बीमारी जल्दी पकड़ने की तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहे नवजात बच्चों की बीमारी पकड़ने में होने वाली देरी कम करने की तैयारी है। अब गंभीर हालत में भर्ती शिशुओं को केवल हृदय की जांच के लिए दूसरे अस्पताल या मेडिकल कॉलेज भेजने की जरूरत कम होगी। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों (एसएनसीयू) में ईको मशीनें लगाने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल छह मशीनें खरीदी गई हैं। इन्हें छह जिला अस्पतालों के एसएनसीयू में स्थापित किया जाएगा। खरगोन, बड़वानी और विदिशा में मशीन लगाने का निर्णय हो चुका है, जबकि अन्य तीन अस्पतालों का चयन जल्द किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बाकी एसएनसीयू को भी ईको मशीनों से लैस किया जाएगा।

जन्मजात हृदय रोग की पहचान में सबसे बड़ी चुनौती गंभीर हालत में भर्ती नवजात को जांच के लिए दूसरी जगह ले जाना है। यदि एसएनसीयू में भर्ती बच्चे में दिल की बीमारी के संकेत मिलते हैं तो सामान्य स्थिति में उसे ईकोकार्डियोग्राफी के लिए मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ सकता है। लेकिन कई बार नवजात की हालत ऐसी होती है कि उसे दूसरी जगह ले जाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में जांच में देरी हो सकती है और बीमारी की पहचान भी देर से होती है। नई व्यवस्था में जांच की सुविधा उसी एसएनसीयू में उपलब्ध कराने पर जोर है। इसका सीधा फायदा उन बच्चों को मिलेगा जिन्हें जन्म के तुरंत बाद विशेष निगरानी और उपचार की जरूरत होती है।

दिल में छेद का पता देर से चलना बड़ी चुनौती

बच्चों में जन्मजात हृदय रोग के कई प्रकार हो सकते हैं। इनमें दिल में छेद जैसी समस्या भी शामिल है। कई मामलों में जन्म के समय स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते और बीमारी का पता तब चलता है जब बच्चा बड़ा होने लगता है। सांस फूलना, वजन बढ़ने में परेशानी या शरीर का नीला पड़ना जैसे लक्षण सामने आने के बाद जांच कराई जाती है। ऐसे मामलों में बीमारी की पहचान जन्म के काफी समय बाद हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग अब कोशिश कर रहा है कि जिन बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की आशंका हो, उनकी शुरुआती अवस्था में ही जांच हो सके।

मशीन से ज्यादा जरूरी होगा प्रशिक्षित स्टाफ

सिर्फ ईको मशीनें खरीदना इस व्यवस्था की पूरी सफलता की गारंटी नहीं है। इसलिए मेडिकल कॉलेजों के हृदय रोग विशेषज्ञ एसएनसीयू में तैनात शिशु रोग विशेषज्ञों को ईकोकार्डियोग्राफी का प्रशिक्षण देंगे। इससे जिला स्तर पर ही शुरुआती जांच और बीमारी की पहचान संभव हो सकेगी। जरूरत पड़ने पर गंभीर मामलों को आगे के उपचार के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान भेजा जा सकेगा। यानी सरकार का मॉडल केवल मशीन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मशीन + प्रशिक्षित डॉक्टर + समय पर रेफरल की व्यवस्था बनाने की कोशिश है।

जल्दी पहचान से इलाज का रास्ता भी जल्दी खुलेगा

जन्मजात हृदय रोग की समय पर पहचान होने से परिवार को लंबे समय तक बच्चे की बीमारी का कारण पता लगाने के लिए अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जांच के बाद बच्चे को उपचार के लिए उचित केंद्र तक जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दिल में छेद सहित कई जन्मजात बीमारियों का उपचार निशुल्क कराया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दो से तीन वर्ष की उम्र में दिल में छेद जैसी समस्या का उपचार कराया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए एसएनसीयू स्तर पर शुरुआती पहचान की व्यवस्था को केवल जांच सुविधा के तौर पर नहीं, बल्कि बच्चे को समय पर इलाज तक पहुंचाने वाली पहली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

महापौर का वाहन जलने से बाल-बाल बचा

भोपाल। राजधानी भोपाल नगर निगम कार्यालय परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब अपनी मांगो का निराकरण नहीं होने से नाराज एक कर्मचारी ने हंगामा करते हुए कुछ कागजो में आग लगाकर उन जलते हुए कागजो को महापौर मालती राय की गाड़ी की छत पर रख दिया। यह देख वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों की सांसे ऊपर नीचे हो गई और उन्होनें बिना पल गवांये ही जलते हुए कागजों को वाहन से तुरंत हटा दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया है की जलते हुए कागज हटाने के प्रयास में एक कर्मचारी के हाथ मामूली रुप से झुलस गए है। जानकारी के मुताबिक वाहन की छत पर जलते हुए कागज रखने वाला आक्रोशित कर्मचारी कुछ समय से बीमार चल रहा है, और अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज भी करा रहा था। सोमवार को वह अस्पताल से सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचा था। कार्यालय पहुंचने पर उसने अपनी मांगों के निराकरण नहीं होने और अन्य समस्याओं को लेकर गुस्से में आकर हाथ में पर्चे लहराते हुए नारेबाजी करते हुए महापौर मालती राय की गाड़ी के पास पहुंच गया। यहां उसने कुछ कागजों में आग लगाई और उन्हें गाड़ी की छत पर रख दिया। गाड़ी में आग लगने की आशंका को देखते हुए वहां मौजूद कर्मचारियों ने फौरन ही जलते हुए कागजों को हटा दिया जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। घटना के बाद नगर निगम कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल कर्मचारी के हंगामे और महापौर की गाड़ी के ऊपर जलते हुए कागज रखने की घटना को लेकर निगम प्रशासन द्वारा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई किये जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

- प्याज-लहसुन की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर सरकार का नया दांव, खेत से बाजार तक बनेगी पूरी चेन

- शहरों की मांग के हिसाब से फसल उत्पादन, क्लस्टर में किसानों को जोड़ा जाएगा; 2030 तक 30 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी का लक्ष्य

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्याज-लहसुन समेत फल और सब्जियों के बाजार भाव में आने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए सरकार अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर निर्भर नहीं रहेगी। फसल के उत्पादन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, परिवहन और बड़े बाजार तक पहुंच बनाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत प्याज और लहसुन के विशेष क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज रियायती दर पर उपलब्ध कराने की योजना है। उद्यानिकी संचालनालय ने प्याज-लहसुन क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके साथ ही अलग-अलग जिलों को फल और फूलों के क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य भी दिया जाएगा। मंदिरों के आसपास फूल उत्पादन के विशेष क्लस्टर बनाए जाने की योजना है।

सरकार की योजना का सबसे अहम हिस्सा फसल को खेत से सीधे मंडी तक भेजने के बजाय उसका वैल्यू एडिशन करना है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे प्याज और लहसुन जैसी फसलों को लंबे समय तक उपयोग योग्य उत्पादों में बदला जा सकेगा। फल-सब्जियों से पल्प, पाउडर और फ्लेक्स जैसे उत्पाद तैयार कर उन्हें बड़े बाजारों और निर्यात बाजार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस मॉडल का उद्देश्य यह है कि उत्पादन बढ़ने के बाद यदि मंडी में कीमतें गिरती हैं तो किसानों के पास उपज को प्रोसेस कर दूसरे बाजार में बेचने का विकल्प मौजूद रहे।

शहरों के आसपास बनेगा उत्पादन का नेटवर्क

सरकार शहरी इलाकों में ताजी सब्जियों की लगातार मांग को देखते हुए शहरों के आसपास विशेष सब्जी क्लस्टर विकसित कर रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत क्लस्टर आधारित खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सब्जी उत्पादक किसानों को निर्धारित इकाई लागत के आधार पर प्रति हेक्टेयर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 24 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बताई गई है। इस व्यवस्था में स्थानीय बाजार की जरूरत के हिसाब से किसानों को फसल चयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी जिस इलाके में जिस फल, सब्जी या मसाले की ज्यादा मांग है, वहां उसी के उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश होगी।

इंदौर से छिंदवाड़ा तक उत्पादन क्लस्टर पर फोकस

इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और छिंदवाड़ा जैसे इलाकों में क्षेत्र की क्षमता और बाजार की मांग के अनुसार उच्च मूल्य वाली सब्जियों, फलों और मसालों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों को परंपरागत फसल के बजाय ज्यादा बाजार मूल्य देने वाली उद्यानिकी फसलों की ओर ले जाने की कोशिश है। क्लस्टर मॉडल में किसानों को उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण और परिवहन से जोड़ने की योजना है।

विभागीय जांच में लापरवाही पर प्रभारी संयुक्त संचालक अमरसत्य गुप्ता निलंबित

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने विभागीय जांच में लापरवाही और समय पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर प्रभारी संयुक्त संचालक अमरसत्य गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गुप्ता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के ग्वालियर-चंबल संभाग में प्रभारी संयुक्त संचालक के पद पर कार्यरत थे।

गुप्ता को नगर पालिका परिषद भिंड में निर्माण कार्यों में अनियमित भुगतान से निकाय को हुई आर्थिक क्षति की शिकायत की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। उन्हें तीन माह में जांच पूरी कर प्रतिवेदन संचालनालय को प्रस्तुत करना था, लेकिन निर्धारित अवधि से पांच माह से अधिक समय बीतने के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। बार-बार स्मरण कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।

विभाग ने 31 अगस्त को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा था, लेकिन निर्धारित अवधि में जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में छह अन्य विभागीय जांच प्रकरणों और 15 लोकायुक्त प्रकरणों में भी प्रतिवेदन लंबित पाए गए। इसके अलावा उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में चल रहे विभिन्न अवमानना प्रकरणों में समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में भी लापरवाही सामने आई।

इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबन अवधि में गुप्ता का मुख्यालय संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

फर्जी आईएएस तृप्ति सिंह के रिश्ते के भाई और ड्रायवर गिरफ्तार

भोपाल। प्रदेश में एमपीटी की एडिशनल डायरेक्टर बताकर ठगी की आरोपी तृप्ति सिंह राजपूत के ममेरे भाई को भोपाल पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उसका ड्राइवर भोपाल से पकड़ा गया है। फर्जी आईएएस तृप्ति और सुधांशु की रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। पुलिस के मुताबिक, तृप्ति कभी ट्रेनी आईएएस और प्रशासन अकादमी से जुड़ी अधिकारी तो कभी एमपीटी में एडिशनल डायरेक्टर बताती थी। इसी आधार पर होटल रिसॉर्ट की लीज और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम ली। भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ रकम वापस भी करती थी। फर्जी सरकारी पहचान के दस्तावेज तृप्ति का ममेरा भाई प्रखर सिंह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करता था। पुलिस पता लगा रही है कि ऐसे कितने दस्तावेज बनाए गए। सूत्रो के मुताबिक तृप्ति ने पूछताछ में बताया की ठगी की अधिकांश रकम घूमने फिरने और महंगे शौक पूरे करने में खर्च की है। उसके खातों में अब ज्यादा रकम नहीं है। पुलिस बैंक स्टेटमेंट से रकम का ट्रेल और मोबाइल की कॉल डिटेल की जॉच कर रही है। जानकारी के अनुसार भोपाल पुलिस की टीम ने फर्जी आईएएस के भाई प्रखर को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके भाई ड्राइवर भूपेंद्र को भी भोपाल से पकड़ लिया है।

45 हजार बिजली कर्मचारी करेंगे काम बंद

भोपाल। प्रदेश में बिजली आउटसोर्स व्यवस्था खत्म कर पंजाब की तर्ज पर नई आउटसोर्स सुधार संविदा नीति लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों के करीब 45 हजार बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मचारी 7 और 8 नवंबर 2026 को काम बंद आंदोलन करेंगे। इसका ऐलान मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने किया है।

भार्गव ने कहा कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के वचन-पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें केंद्र के आउटसोर्स कर्मियों के समान न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी बनाने के लिए विधानसभा से विधेयक पारित हो चुका है, जबकि मप्र में इस दिशा में पहल नहीं हुई है।

पद समाप्त करने और बोनस नुकसान का आरोप

वहीं, बिजली कंपनियों के नए संगठनात्मक ढांचे में करीब 23 हजार पद खत्म किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में छंटनी और बेरोजगारी का डर है। संगठन का आरोप है कि बोनस की दर बढ़ाने के आदेश के बावजूद 69 महीने से पुरानी दर से भुगतान हो रहा है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को करीब 80 से 90 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर धनतेरस की रात से दीपावली की मध्यरात्रि तक सामूहिक अवकाश लेने की चेतावनी दी है।

17 सितंबर को भोपाल सहित प्रदेशभर की मंडियों में रहेगी हड़ताल

भोपाल। पिछले दिनों कृषि उपज मंडी टैक्स में की गई बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर व्यापारियों ने विरोध किया था। मगर शासन ने टैक्स में कमी नहीं की। सकल अनाज दलहन-तिलहन महासंघ का जो प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया कि 17 सितम्बर को भोपाल सहित प्रदेशभर की मंडियां बंद रहेंगी और व्यापारी भोपाल पहुंचकर कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। मंडी नियमों में प्रस्तावित संशोधन, नामांतरण, नामांकरण शुल्क में वृद्धि, पेनल्टी सहित ऑनलाइन पोर्टल की जटील प्रक्रिया सहित जो मांगें रखी गई थी उन पर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। व्यापारी महासम्मेलन में प्रदेशभर के व्यापारी, मंडी प्रतिनिधि व अन्य अनाज दलहन-तिलहन कारोबार से जुड़े व्यापारी शामिल हुए और इस महासम्मेलन में मंडी से जुड़ी समस्याओं-व्यवस्थाओं, नियमों पर अपनी बात कही और अतिरिक्त टैक्स वृद्धि वापस लेने और भविष्य में कोई भी नियम बनाने से पहले व्यापारियों से पर्याप्त सहमति और चर्चा करने की बात भी कही। अध्यक्ष के मुताबिक 17 सितम्बर को देशभर में मंडियों को बंद रखा जाएगा।

विनोद / 07 सितम्बर 26

स्टाइपेंड की मांग को लेकर सीएम हाऊस घेरने जा रहे इंटर्न डॉक्टर्स की पुलिस से झड़प

भोपाल। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर्स ने अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम हाउस की ओर पैदल मार्च निकालने का प्रयास किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही महिला पुलिस और किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये पुलिस की अन्य टीमें भी तैनात थी। बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टर्स हमीदिया अस्पताल से पैदल निकले जिन्हें पुलिस बल द्वारा हमीदिया के गेट पर ही बैरिकेटिंग कर रोक दिया गया। इस डॉक्टरो और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बन गई, हालत को काबू में करने के लिये पुलिस ने वाटर कैनन चलाया। इस दौरान पुलिस और इंटर्न डॉक्टर्स के बीच मामूली झड़प हुई। वाटर कैनन की चपेट में आने से एक छात्र को चोट लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी हंगामें के बीच इंटर्न डॉक्टर अपनी मांगो को लेकर हमीदिया अस्पताल के गेट के सामने सड़क पर ही धरने पर बैठ गये। मोके पर पुलिस अफसरो के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरो का कहना है की वर्तमान में उन्हें हर महीने 14,337 का स्टाइपेंड मिल रहा है, इसे बढ़ाकर कम से कम 30 हजार प्रतिमाह किया जाए। पूर्व में सरकार ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं आया। इसके बाद अपनी मांग रखने के लिये उन्होनें मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च निकालने का फैसला लिया। इंटर्न डॉक्टरो का आरोप है की वे सीएम मुख्यमंत्री निवास जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनके सामने पूरी तैयारी के साथ भारी पुलिस बल खड़ा कर दिया। हमारा आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन पैदल मार्च रोकने के लिए पुलिस ने अस्पताल परिसर की घेराबंदी कर दी थी। इसी दौरान कुछ इंटर्न डॉक्टर्स ने हमीदिया अस्पताल का गेट और बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद वे बाहर निकलकर फतेहगढ़ की मुख्य सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ छात्र गेट तोड़कर बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए। विरोध पर उतरे इंटर्न डॉक्टरों का कहना है, कि वे लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि स्टाइपेंड बढ़ाने का आधिकारिक लिखित आदेश चाहिए। जब तक मुख्यमंत्री स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश नहीं देते, तब तक इंटर्न डॉक्टर हमीदिया अस्पताल परिसर में ही बैठे रहेंगे। वहीं डॉक्टरो के प्रदर्शन के कारण पुलिस ने हमीदिया अस्पताल की और आने वाले सभी रास्तो को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया, जिससे पीर गेट, इमामी गेट, रॉयल मार्केट, मोतिया तालाब वाली सड़क, चौकी इमाम बाड़ा, सिंधी मार्केट, बीआईपी रोड पर वाहनो का जाम लग गया और इन रास्तो के साथ ही आसपास की गलियों से गुजरने वाले छोटे रास्तो पर भी वाहन चालको को परेशानियो का सामना करना पड़ा।

नगर परिषद जेरोन खालसा के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने मतदान 29 सितम्बर को

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद जेरोन खालसा जिला निवाड़ी के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। इस संबंध में मतदान 29 सितम्बर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दिनेश श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं प्रतीक का आवंटन 8 सितम्बर को किया जायेगा। मतदान 29 सितम्बर को होगा। मतगणना 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से होगी। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर परिषद जेरोन खालसा जिला निवाड़ी के नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।

भोपाल भाजपा की जिला टीम में 90 नए चेहरे

- सुरेश पचौरी समेत 23 दिग्गज स्थायी आमंत्रित सदस्य

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में जिला संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया है। रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे जिला कार्यसमिति की सूची जारी की गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद जिलाध्यक्ष रविंद्र यती ने सदस्यों के नामों की घोषणा की। नई कार्यसमिति में कुल 90 कार्यकर्ताओं को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इनमें मनोज राठौर, मनोज राजू अनेजा, राजेश खटीक, महेश जोशी, दिनेश पांडे, अनुपा सिंह रघुवंशी, पूजा भारद्वाज, विकास शर्मा (बंटी), सुमत कुमार जैन और सुनील व्यास समेत कई नेताओं को जगह मिली है। नई सूची में सबसे चर्चित नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का है। कांग्रेस छोडकर भाजपा में शामिल हुए पचौरी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इस श्रेणी में कुल 23 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें रघुनंदन शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, ध्रुवनारायण सिंह, महापौर मालती राय, राहुल कोठारी और सुमित पचौरी समेत वरिष्ठ नेता शामिल हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सरकार और संगठन से जुड़े प्रमुख चेहरों को जगह दी गई है।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज 13 सितंबर से होगी

भारतीय टीम अब तब रही है अजेय

नई दिल्ली। इसी माह 13 सितंबर से भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की एक टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान बोर्ड कर रहा है। सीरीज का आयोजन यहां के अरुणे जेटली स्टेडियम में होगा क्योंकि अफगान टीम के पास अपना कोई स्टेडियम नहीं है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी। पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान ने जिस तरह से टी20 प्रारुप में खेला है उससे ये मुकाबला आसान नहीं रहेगा।

टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक बेहद अच्छा रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं, और इनमें से 8 में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबले का परिणाम नहीं निकला है। अफगानिस्तान को अभी तक टी20 प्रारुप में भारतीय टीम के खिलाफ जीत नहीं मिली है। जिससे पता चलता है कि भारतीय टीम अभी तक अजेय रही है।

आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और वापसी देखने को मिली है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम की गेंदबाजी बेहतर होगी।, हालांकि उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही खेलने की अनुमति मिलेगी। 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिली है, और अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहता है इसपर सबकी नजरें रहेंगी। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और ईशान किशन संभालेंगे, जो टीम को गहराई प्रदान करेंगे। नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी भी फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही अंतिम एकादश का हिस्सा बन पाएंगे, जो टीम की बेंच स्ट्रेंथ को दिखाता है।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के रोमांचक मुकाबले में 1 रन से जीती शुभमन की टीम

मोहाली। शुभमन गिल की आक्रामक पारी से शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में फजिल्का फाल्कन्स ने एक रोमांचक मुकाबले में एक रन से लुधियाना लायंस को हरा दिय। अंतिम ओवर में लुधियाना को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे पर वह केवल 5 रन बी बना पायी और एक रन से मुकाबला हार गयी।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी फजिल्का फाल्कन्स के कप्तान शुभमन ने सिर्फ 21 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की सहायत से 40 रन बनाकर , जिससे फजिल्का को एक धमाकेदार शुरुआत मिली। हालांकि, लुधियाना के युवा गेंदबाज कार्तिक चड्ढा ने 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें शुभमन का बहुमूल्य विकेट भी शामिल था। शुभमन के आउट होने के बाद प्रेरित दत्ता ने 36 रन और जयवीर भिंडर ने 18 गेंदों में 21 रन बनाकर फजिल्का फाल्कन्स को 20 ओवरों में 9 विकेट पर 170 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जीत के लिए मिले 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लुधियाना लायंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लगातार अंतराल पर विकेट गिरने से लुधियाना पर दबाव बढ़ता गया। सलामी बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 32 रन बनाकर एक छोर संभालने की कोशिश पर उन्हें सहयोग नहीं मिला।

इसके बाद माधव पठानिया और कृष भगत ने बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम की मैच में वापसी करायी। दोनों बल्लेबाजों ने केवल 29 गेंदों में 61 रनों की एक विस्फोटक और अटूट साझेदारी करके लुधियाना के खेमे में जीत की उम्मीदें फिर से जगा दीं। माधव पठानिया ने 16 गेंदों पर तेजी से 37 रन बनाए, वहीं कृष भगत ने 23 गेंदों में 28 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ दिया।

अंतिम ओवर में लुधियाना को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे, और पठानिया-भगत की जोड़ी ने शुरुआती गेंदों पर तेजी से रन बटोरकर मैच को आखिरी गेंद तक खींच दिया। अंतिम गेंद पर लुधियाना लायंस को जीत के लिए 6 रन की दरकार थी और क्रीज पर विस्फोटक माधव पठानिया मौजूद थे पर फजिल्का के गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए कोई रन नहीं दिया। लुधियाना की टीम 1 रन से पीछे रह गई। इस तरह फजिल्का फाल्कन्स ने ये मुकाबला जीता लिया।

भारत-पाकिस्तान ट्राई सीरीज शुरु करने पर विचार कर रहा आईसीसी

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसमें प्रशंसकों को दोनो के बीच अधिक मुकाबले देखने को मिलेंगे। अभी दोनो ही टीमें केवल आईसीसी टूर्नामेंटों में ही आमने-सामने होती हैं। पिछले एक दशक से अधिक समय से दोनो के ही बीच बढ़ते तनाव के कारण कोई भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है। दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय भिड़ंत 2012-13 के सत्र में हुई थी, जब पाकिस्तान टीम ने भारत का दौरा किया था।

अब आईसीसी एक ऐसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट या सीरीज की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें शामिल होंगी। यह प्रस्ताव एक ट्राई सीरीज के रूप में हो सकता है, जिसमें तीन टीमें हिस्सा लेंगी, या फिर चार टीमों का एक बड़ा टूर्नामेंट भी आयोजित किया जा सकता है।आईसीसी को पता है कि इन दोनो के बीच मैच से भारी राजस्व भी मिलता है।

गौरतब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) भारतीय टीम के साथ तटस्थ स्थल पर मैच खेलने की मांग करता रहा है पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड इससे इंकार करता रहा है। आगामी 22 और 23 सितंबर को आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन होना है, जिसमें सभी पूर्ण सदस्य देशों और आठ सहयोगी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी सेमिनार से पहले इस मल्टी-नेशन सीरीज पर भी विचार होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस सेमिनार में भारत-पाकिस्तान को शामिल करने वाली इस ट्राई सीरीज या चार-टीमों के टूर्नामेंट का विचार औपचारिक रूप से पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे का प्रमुख तर्क यह है कि ऐसे टूर्नामेंट से जबरदस्त राजस्व (रेवेन्यू) उत्पन्न किया जा सकता है। यह न केवल प्रसारकों के लिए, बल्कि आयोजकों के लिए भी एक बड़ा आर्थिक अवसर प्रदान करेगा, जिससे क्रिकेट के वैश्विक विकास में भी मदद मिल सकती है। यदि इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी मिल जाती है, तो इसे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसे किसी तटस्थ और सुरक्षित स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। गौरतलब है कि पूर्व में, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत के साथ ट्राई सीरीज खेलने की अपनी इच्छा जता चुके हैं। उस समय आईसीसी ने स्पष्ट किया था कि ऐसी सीरीज पर निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह संबंधित देशों के क्रिकेट बोर्ड का व्यक्तिगत फैसला होता है। हालांकि, मौजूदा प्रस्ताव में आईसीसी स्वयं सक्रिय रूप से शामिल होकर इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

ईशान ने दूसरा शतक लगाकर बनाया रिकार्ड

चेन्नई । ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दिलीप ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन शानदार दोहरा शतक लगाकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। ईशान ने पहले दिन शतक लगाय था। वहीं दूसरे दिन भी उनकी बल्लेबाजी जारी रही।अब ईशान टूर्नामेंट के फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले दिलीप ट्रॉफी के फाइनल में रमन लांबा, अंशुमन गायकवाड़, चेतेश्वर पुजारा और यशस्वी जायसवाल ने ही दोहरे शतक लगाये हैं। शुरूआत से ही ईशान ने ईस्ट जोन की कमान अच्छे से संभाली। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर ईस्ट जोन ने 4 विकेट पर 385 रन था जिसमें ईशान 111 और कुमार कुशाग्र 63 रन बनाकर नाबाद थे। इस दोनो ने सिर्फ 26.4 ओवर में 144 रनों की अटूट साझेदारी करके ईस्ट जोन को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरे दिन कुशाग्र भी आउट होने से पहले शतक तक पहुंचे। हालांकि उनके आउट होने से ईशान पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया।

धोनी का आईपीएल 2027 सत्र में खेलना संभव नहीं - बद्रीनाथ

चेन्नई । चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने कहा है कि दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 सत्र में खेलना संभव नजर नहीं आता है। इसका कारण है कि धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। बद्रीनाथ का मनाना था कि धोनी इम्पैक्ट प्लेयर नियम के तौर पर उतरकर अपने आईपीएल करियर को लंबा कर सकते थे पर वह इसके लिए तैयार नहीं दिखते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि वह खेलना जारी रखते हैं, तो वह एक पूर्णकालिक विकेटकीपर के रूप में ही मैदान पर उतरना चाहेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्हें पूरे 20 ओवर तक विकेटकीपिंग और क्षेत्ररक्षण की जिम्मेदारी निभानी होगी जो उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए संभव नहीं दिखता।

बद्रीनाथ का मानना है कि धोनी के लिए उनके करियर के इस चरण में इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका अधिक उपयुक्त हो सकती थी। 44 साल की उम्र को देखते हुए, पूरे 20 ओवर तक विकेटकीपिंग करना उनके लिए शारीरिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। यह नियम उन्हें केवल बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने

और दबाव कम करने का अवसर प्रदान कर सकता था, जिससे वे फिनिशर के रूप में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा पाते।

बद्रीनाथ ने बताया, "धोनी ने मुझसे कहा कि वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलेंगे। वह खुद को एक पूर्णकालिक विकेटकीपर मानते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पूरे 20 ओवर तक मैदान पर रहना होगा। इसलिए वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं तो इससे सीएसके को रणनीतिक फायदा होगा।"

गौरतलब है कि धोनी पिछले कुछ आईपीएल सत्रों में फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं, और उनके आईपीएल भविष्य को लेकर अटकलें लगातार बनी रहती हैं। बद्रीनाथ का मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम निश्चित रूप से धोनी पर काम का बोझ कम कर सकता था, जिससे सीएसके उनके अमूल्य अनुभव और फिनिशर के रूप में उनकी अद्वितीय भूमिका का लाभ उठा पाता। सीएसके को पांच आईपीएल खिताब दिलाने वाले धोनी ने 2024 के सत्र से पहले कप्तानी छोड़ दी थी, और तब से बल्लेबाज के रूप में भी उनकी भूमिका काफी सीमित हो गई है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम आठ साल बाद दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी, लाबुशेन की वापसी

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई टीम आठ साल के बाद दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने इस सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी है। इस टीम में बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की भी वापसी हुई है। लाबुशेन खराब फार्म के कारण पिछले काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे। सीए ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जो 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है उसमें लाबुशेन को देखकर उनके प्रशंसकों में उत्साह छा गया। यह दौरा अक्टूबर में होगा और कंगारू टीम साल 2018 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसकी धरती पर टेस्ट क्रिकेट खेलेगी। गौरतलब है कि पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद, मेजबान ऑस्ट्रेलिया किसी प्रकार सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाने में सफल रही।

रिंकू की मेरठ मावरिक्स ने यूपी टी20 लीग खिताब जीता

नई दिल्ली। रिंकू सिंह की कप्तानी वाली मेरठ मावरिक्स ने भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कंस को 94 रनों से हराकर यूपी टी20 लीग का खिताब जीता है।इस रोमांचक मुकाबले में मेरठ मावरिक्स के कप्तान रिंकू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरु की। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। पारी की शुरुआत करने उतरे स्वास्तिक चिकारा और दिव्यांश जोशी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाय। । दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए तेजी से 53 रनों की साझेदारी कर टीम को एक अच्छा आधार दिया।

स्वास्तिक चिकारा के आउट होने के बाद क्रीज पर दिव्यांश ने और तेजी दिखायी। दिव्यांश ने लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बेकार कर दिया। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी दिव्यांश पर अंकुश नहीं लगा पाये। दिव्यांश जोशी ने लीग इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक खेलते हुए केवल 40 गेंदों में 105 रन बना दिये। इस अविश्वसनीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 7 करारे छक्के लगाये। दिव्यांश की इस आतिशी पारी के बल पर मेरठ मावरिक्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 203 रन बनाये।

इसके बाद जीत के लिए मिले 204 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मेरठ के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को कोई अवसर नहीं दिया दबाव में लखनऊ की टीम बिखर गई। टीम की ओर से अकेले अजीत वर्मा ने 24 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके रन आउट होते ही टीम की उम्मीदें समाप्त हो गयीं।

अमेरिकी ओपन में सेरूंडोलो ने फ्रिट्ज को हराकर सनसनी फैलाई

अब अलेक्जेंडर ब्लॉकक्स से होगा मुकाबला

न्यूयॉर्क। यहां जारी अमेरिकी ओपन टेनिस में नौवीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज उलटफेर का शिकार हो गये। फ्रिट्ज को अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरूंडोलो ने हराकर सनसनी फैला दी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही सेरूंडोलो के पहली बार अमेरिकी ओपन के अंतिम-16 में जगह मिली है। यह रोमांचक मुकाबला आर्थर ऐश स्टेडियम में खेला गया। मैच में फ्रिट्ज ने शुरु से ही आक्रामक रुख अपनाया और पहले दो सेट 6-3 और 6-4 से आसानी से आसानी से जीत लिए पर इसके बाद अर्जेंटीनी खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए अगले तीन सेट 6-3, 6-4 और 6-4 से जीत लिए। इस जीत से सेरूंडोलो अपने दृढ़ संकल्प और जुझारूपन को दिखाय। यह उनके करियर में दूसरी बार है जब वे दो सेट से पिछड़ने के बाद कोई मैच जीतने में कामयाब रहे हैं, जो उनकी मानसिक दृढ़ता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। इस पांच-सेट के मैराथन मुकाबले में को भी आनंद आया। मुकाबला और कुल तीन घंटे 39 मिनट तक चला। टेलर फ्रिट्ज के लिए यह हार बेहद निराशाजनक रही, खासकर तब जब वे पहले दो सेट जीतकर मजबूत स्थिति में थे और उनकी खिताबी जीत की उम्मीदें थीं उनका टूर्नामेंट से इतनी जल्दी बाहर होना प्रशंसकों और विशेषज्ञों दोनों के लिए हैरान करने वाला अनुभव रहा। सेरूंडोलो ने इस जीत के साथ न केवल अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, बल्कि टूर्नामेंट में एक नए और अप्रत्याशित दावेदार के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। अब अंतिम-16 में फ्रांसिस्को सेरूंडोलो का मुकाबला बेल्जियम के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ब्लॉकक्स से होगा। ब्लॉकक्स ने भी अपने तीसरे दौर के मुकाबले में फ्रांस के फ्लेवियो कोबोली को हराकर टूर्नामेंट में यहां तक का सफर तय किया है।

टेवेज के विदाई मैच में एक साथ खेल सकते है मेसी ओर रोनाल्डो

बार्सिलोना। हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने वाले अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ओर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब एक विदायी मैच में एक साफ खेलते नजर आ सकते हैं। रोनाल्डो और मेसी के बीच पिछले एक दशक में कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है पर आने वाले एक मैच में ये दोनो दिग्गज एक साथ दिख सकते हैं। ये दोनो ही इस साल के अंत में अर्जेंटीना के पूर्व स्टार फुटबॉलर कार्लोस टेवेज के विदाई मैच में खेल सकते हैं। इससे दोनो के प्रशंसक भी हैरान होने के साथ ही उत्साहित हैं।

इसका कारण ये है कि पिछले लगभग 15 वर्षों से, रोनाल्डो और मेसी की प्रतिद्वंद्विता फुटबॉल जगत में हावी रही है। ला लीगा में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए और मेसी ने बार्सिलोना के लिए खेलते हुए कई यादगार मुकाबले जीते हैं। राष्ट्रीय टीमों की ओर से खेलने के दौरान और क्लब स्तर पर ये दोनो ही 37 बार एक-दूसरे के खिलाफ खेल हैं पर कभी भी एक टीम में नहीं रहे हैं। इन दोनों महान खिलाड़ियों ने मिलकर रिकॉर्ड 13 बैलन डी खिताब जीते हैं। दोनो के ही प्रशंसक अपने-अपने स्टार खिलाड़ी के बेहतर होने के दावे करते रहे हैं। वहीं कार्लोस टेवेज ने इन दोनो के साथ ही खेला है और वह विदाये मैच में इन्हें साथ ला रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसर टेवेज ने अपने पूर्व क्लब बोका जूनियर्स के अध्यक्ष जुआन रोमन रिकेल्मे से ला बॉम्बोनेरा स्टेडियम में इस मैच को आयोजित करने पर बात की है। रिकेल्मे ने इस खास आयोजन के लिए अपनी सहमति दे दी है। गौरतलब है कि बोका जूनियर्स से अपना पेशेवर करियर शुरू करने वाले टेवेज ने 2021 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। अब पांच साल बाद, वे अपने करियर को एक भव्य विदाई देने की तैयारी में हैं। ये मैच दिसंबर महीने में होना तय है। जिससे बोका जूनियर्स के कार्यक्रम पर इसका कोई असर न पड़े।

गौरतलब है कि रोनाल्डो और मेसी जैसे दिग्गजों को एक साथ खेलने के लिए मनाना किसी और के लिए शायद असंभव होता, लेकिन टेवेज के लिए यह संभव है। दरअसल, टेवेज अर्जेंटीना की नेशनल टीम में मेसी के साथ और मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं। आज भी उनके दोनों दिग्गजों के साथ अच्छे संबंध हैं। टेवेज का मानना है कि वह इन दोनो को एकसाथ लाने में सफल रहेंगे। अगर टेवेज इसमें कामयाब होते हैं, तो यह केवल एक विदाई मैच नहीं, बल्कि फुटबॉल इतिहास में एक स्वर्णिम पल होगा, जो हमेशा याद रखा जाएगा। यह दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा।

अगले पांच साल तक रियल मैड्रिड से खेलेंगे स्ट्राइकर कार्लोस एस्पी

मैड्रिड। स्पेन के शीर्ष फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने लेवांते के युवा स्ट्राइकर कार्लोस एस्पी को अपने साथ जोड़ा है। रियल मैड्रिड ने एस्पी को करीब 25 मिलियन यूरो की मोटी रकम देकर खरीदा है। ऐसे में अब अगल सत्र से कार्लोस रियल की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। रियल ने कहा कि कि कार्लोस अगले पांच साल तक उसके पास ही रहेंगे। इसके तहत ये फुटबॉलर जून, 2031 तक रियल की ओर से खेलेगा।

गौरतलब है कि रियल मैड्रिड में आने से पहले कार्लोस ने लेवांते की ओर से तीन सत्र खेले हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 66 मैचों में 20 गोल दागे हैं। उनका पिछला सीजन विशेष रूप से अच्छा रहा। इस दौरान उन्होंने 27 मैचों में 13 गोल किये। उन्हें पिछले सीजन में लीग का सर्वश्रेष्ठ अंडर-23 खिलाड़ी भी चुना गया था। कार्लोस के इन गोलों के कारण ही लेवांते को निचली लीग में जाने से बचा था। सत्र सीजन के आखिरी हफ्तों में उनके प्रदर्शन ने टीम को मजबूती मिली थी। इस स्ट्राइकर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए स्पेनिश ला लीगा के क्लब विल्लारियल और इंग्लैंड की प्रीमियर लीग के साथ् ही कई बड़े क्लबों ने भी रुचि दिखायी थी। रियल मैड्रिड ने हालांकि इस दौड़ में बाजी मार ली। लेवांते ने संभावित चोट के खतरे को कम करने के लिए प्री-सत्र फ्रेंडली मैचों से बाहर रखा था, जो आमतौर पर बड़े ट्रांसफर से पहले किया जाता है।

कार्लोस का रियल मैड्रिड में ऐसे समय में आये जब क्लब अपने स्ट्राइकर गोंजालो गार्सिया को इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब फुलहम को बेचने के करीब पहुंच गया है। गोंजालो की यह डील लगभग 40 मिलियन यूरो में फाइनल होने वाली है, जिससे मैड्रिड को काफी रकम मिलेगी। इससे टीम में नए स्ट्राइकर को भी जगह मिलेगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कार्लोस को अगले सत्र में सीधे मैड्रिड की फर्स्ट-टीम स्क्वाड में शामिल किया जाएगा या उन्हें शीर्ष स्तर का अनुभव हासिल करने के लिए किसी अन्य क्लब में लोन पर भेजा जाएगा।

ग्रीम स्मिथ सहित इन खिलाड़ियों के नाम है सबसे लंबे समय तक कप्तानी का रिकार्ड

जोहांसबर्ग । आजकल टी20 क्रिकेट का जोर है और दुनिया भर में टी20 लीग चल रही हैं। इसके बाद भी टेस्ट क्रिकेट का महत्व बना हुआ है। इसका कारण ये है कि इसी प्रारुप में किसी खिलाड़ी की प्रतिभा और कौशल की असली परीक्षा होती है और खेल का असली रोमांच मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में इस दौरान कई अनोखे रिकार्ड भी बने हैं। ऐसा ही एक रिकार्ड दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ के नाम है। स्मिथ ने 2003 से 2014 के बीच रिकॉर्ड 109 टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी की थी। सबसे लंबे समय तक कप्तानी का रिकार्ड है। पिछले 12 साल मे कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया है। इस दौरान स्मिथ की टीम को 29 टेस्ट मैचों में हार का भी सामना करना पड़ा उन्होंने जिस प्रकार से एक युवा और बिखरी हुई टीम को विश्व की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में से एक बनाया , उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। कप्तान के तौर पर भले ही उन्होंने शतक न जमाया हो, लेकिन उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने नई उपलब्धियां हासिल की।

स्मिथ के बाद सबसे अधिक समय तक कप्तानी करने वलो बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग इस दूसरे स्थान पर हैं। कीवी टीम के सबसे सफल कप्तान फ्लेमिंग ने साल 1997 से 2006 के बीच कप्तानी संभाली और इस दौरान उनकी टीम 27 टेस्ट मैच ही हारी। फ्लेमिंग ने अपनी कप्तानी में न्यूजीलैंड को आगे बढ़ाया। उन्होंने कप्तान के रूप में 117 रनों की एक शतकीय पारी सहित 1589 रन बनाए।

वहीं इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान जो रूट ने साल 2017 से 2022 तक टेस्ट कप्तानी की थी। वह सबसे अधिक समय तक कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान हैं।जब इंग्लैंड की टीम बदलाव के दौर से गुजर रही थी, तब रूट ने अकेले दम पर बल्लेबाजी का भार संभाला। कप्तानी के दौर में रूट ने भी 27 टेस्ट मैचों में हार का सामना किया। कप्तान के रूप में रूट का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा; उन्होंने 1793 रन बनाए, जिसमें नाबाद 180 रनों का एक यादगार शतक शामिल था। उनका कप्तानी कार्यकाल यह दर्शाता है कि एक खिलाड़ी कितने भी रन बनाये, टेस्ट मैच जीतने के लिए पूरी टीम के सामूहिक योगदान की जरूरत होती है। रुट को इस साल एक बार फिर कप्तानी सौंपी गयी थी

क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में गिने जाने वाले वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा का नाम भी इस सूच में है। 1998 से 2006 के बीच लारा ने वेस्टइंडीज की कप्तानी तब संभाली जब कैरेबियाई क्रिकेट का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया था। लारा के नेतृत्व में वेस्टइंडीज ने 26 टेस्ट मैच गंवाए। हालांकि, हारने वाले मैचों में भी लारा का बल्ला जमकर बोला; उन्होंने 40.50 की बेहतरीन औसत से 2106 रन बनाए, जिसमें 202 रनों के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक शामिल थे।

वहीं साल 1980 और 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को निखारने का श्रेय एलन बॉर्डर को जाता है। साल 1984 से 1994 के बीच बॉर्डर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभाली। उनके कप्तानी दौर में ऑस्ट्रेलिया को 22 टेस्ट मैचों में हार मिली। कप्तानी के दौरान दबाव के क्षणों में बॉर्डर ने 27.14 की औसत से 1140 रन बनाए, जिसमें नाबाद 152 रनों की शतकीय पारी शामिल थी।

ये आंकड़े दिखाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी एक दोधारी तलवार है, जहां लंबे कार्यकाल अक्सर जीत के साथ-साथ हार का भी बोझ लेकर आते हैं।

अरुणाचल सीमा पर पहली बार भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक

-वाचा-दमाई सीमा बैठक स्थल पर हुई सैन्य वार्ता, एलएसी से जुड़े मुद्दों और शांति-स्थिरता पर हुई चर्चा

ईटानगर। भारत और चीन की सेनाओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े मुद्दों को लेकर रविवार को महत्वपूर्ण सैन्य वार्ता हुई। 6 सितंबर को वाचा-दमाई सीमा बैठक स्थल पर दोनों देशों के बीच पहली बार कोर कमांडर स्तर की बैठक आयोजित की गई। पूर्वी सैन्य सेक्टर में इस स्तर की यह पहली बैठक मानी जा रही है।

बैठक भारतीय क्षेत्र में स्थित वाचा सीमा बैठक स्थल पर हुई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व तीसरी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया ने किया। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से जुड़े मौजूदा मुद्दों और उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की।

दो भारतीय कोर संभालती हैं सीमा की जिम्मेदारी

अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी एलएसी की सुरक्षा और सैन्य जिम्मेदारियां भारतीय सेना की चौथी कोर, तेजपुर और तीसरी कोर, रंगापाहर संभालती हैं। संवेदनशील सीमा क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत रखा है। एलएसी पर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाओं के कारण कई बार गश्त, सैनिकों की आवाजाही और किसी क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर तनाव की स्थिति बनती रही है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर सीधे सैन्य संवाद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गलवान के बाद बदला सीमा पर सैन्य रुख

भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठकें अब तक मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख के चुशुल-मोल्डो सीमा बैठक स्थल पर होती रही हैं। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों और सीमा पर सैन्य स्थिति में बड़ा बदलाव आया था। गलवान घटना के बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ पर्वतीय युद्ध क्षमता और बुनियादी सैन्य ढांचे को मजबूत किया। भारत लगातार यह रुख रखता आया है कि एलएसी पर यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने की किसी भी कोशिश का जवाब दिया जाएगा।

डोभाल की चीन यात्रा के बाद बढ़ा संवाद

अरुणाचल में यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद आगे बढ़ा है। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर जारी बातचीत का उद्देश्य सीमा पर तनाव कम करना और टकराव की स्थिति से बचना है। इसी व्यापक प्रक्रिया के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोर कमांडर स्तर की बैठक को महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इससे पूर्वी सेक्टर में स्थानीय स्तर के विवादों और एलएसी की अलग-अलग धारणाओं से पैदा होने वाली समस्याओं को सीधे सैन्य संवाद के जरिए नियंत्रित करने का रास्ता खुल सकता है।

सेना प्रमुख ने भी तीसरी कोर का किया था दौरा

बैठक से कुछ दिन पहले ही थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रंगापाहर स्थित तीसरी कोर मुख्यालय का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की सैन्य तैयारियों, ऑपरेशनल स्थिति और युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की थी। तीसरी कोर अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के संवेदनशील हिस्सों की निगरानी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में कोर कमांडर स्तर की बैठक और सेना प्रमुख के हालिया निरीक्षण को क्षेत्र की सुरक्षा एवं ऑपरेशनल तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अरुणाचल में हुई यह पहली उच्चस्तरीय सैन्य बैठक दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन के लिए सीधे और स्थानीय सैन्य संवाद के नए चैनल की शुरुआत का संकेत देती है। हालांकि, वास्तविक प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि बातचीत के जरिए एलएसी से जुड़े मतभेदों और जमीनी स्तर की समस्याओं को किस हद तक सुलझाया जा सकता है।

स्मृति ईरानी बोलीं- फडणवीस को देखकर गौरान्वित होती हूं

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र किया और उनके साथ पार्टी में अपने शुरुआती अनुभवों को साझा किया। स्मृति ईरानी ने व्यक्त किया कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस को देखकर गर्व होता है। उल्लेखनीय है कि साल 2024 में उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद ईरानी कुछ समय से सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर चल रही थीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी ऐसा लगा कि राज्यसभा के माध्यम से पार्टी उन्हें वापस ला सकती है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में पद का अर्थ पहचान नहीं, बल्कि एक अवसर होता है।

ईरानी ने अपने राजनीतिक जीवन के 24 वर्षों का अनुभव साझा करते हुए कहा कि बहुत से लोग इस बात को पूरी तरह नहीं समझते कि उनके लिए संगठन में पद का मतलब व्यक्तिगत पहचान बनाना नहीं, बल्कि सेवा करने का एक मौका होता है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि वह पहली बार 2003 में भाजपा की युवा मोर्चा में पदाधिकारी बनी थीं। यह महाराष्ट्र की बात है, और उस समय उनके साथ जो उपाध्यक्ष थे, उनका नाम देवेंद्र फडणवीस था। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए बताया कि वे दोनों तब 24-25 साल के युवा थे, जो पार्टी के बड़े नेताओं जैसे प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी को देखकर प्रेरणा लेते थे। स्मृति ईरानी आज भी जब देवेंद्र फडणवीस से मिलती हैं, तो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करके मुस्कुराते हैं। उन्हें कभी जीवन में यह अनुमान भी नहीं था कि वे राजनीतिक यात्रा में इतनी दूर तक पहुंचेंगे।

एक छोटा सा उदाहरण देते हुए उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, जब उन्होंने चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय एक समर्पित कार्यकर्ता, जो आज भी संगठन में महत्वपूर्ण पद पर हैं और सांसद भी हैं, प्रवीण खंडेलवाल, की टिकट कट गई थी और वह टिकट उन्हें मिल गई थी। प्रवीण खंडेलवाल उनके डमी कैंडिडेट बने थे, जो नामांकन पत्र भरते समय आवश्यक होता है। प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने वर्षों से चांदनी चौक में पार्टी के लिए अथक परिश्रम किया था, उनका मुंह उतरा हुआ था। ईरानी ने बताया कि उन्होंने प्रवीण जी से विनम्रतापूर्वक माफी मांगी और कहा कि उन्हें तो पार्टी ने अचानक टिकट दे दिया था, उस वक्त वेंकैया नायडू पार्टी अध्यक्ष थे और उन्होंने सीधे चुनाव लड़ने का फरमान सुनाया था। ईरानी ने प्रवीण जी को भरोसा दिलाया कि उन्हें भी एक दिन संगठन अवश्य मौका देगा, और आज वे सांसद हैं। आज जब स्मृति ईरानी देवेंद्र फडणवीस को देखती हैं, तो उन्हें सचमुच गर्व महसूस होता है।

मैप बना लें पर कश्मीर और लद्दाख भारत का दिखना चाहिए

नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर प्रस्तावित विश्व मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को देश के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही दिखाया जाना चाहिए। भारत ने यूएन को हिंदी समझाते हुए यह भी साफ कर दिया कि इन क्षेत्रों का कोई भी गलत या भ्रामक चित्रण किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों द्वारा शुक्रवार को एक प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किए जाने के दो दिन बाद आया है। इस प्रस्ताव का शीर्षक मानचित्र में सुधार- वैश्विक मानचित्रण प्रतिनिधित्व में संतुलन कायम करना और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। भारत ने महाद्वीपों के भूभाग को अधिक सटीकता से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विश्व मानचित्र में सुधार से जुड़े इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत ने अपने मतदान पर स्पष्टीकरण देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि यह प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र, मानचित्रण पद्धति या राष्ट्रीय सीमाओं के किसी खास चित्रण का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने इक्वल एरिया मानचित्रण पद्धतियों को बढ़ावा देने के मूल सिद्धांत पर बल दिया। जायसवाल ने दृढ़ता से कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत भारत के संप्रभु क्षेत्र को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही दिखाया जाना चाहिए। कोई भी गलत या भ्रामक चित्रण स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमारा रुख स्पष्ट और अडिग है तथा इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत ने इस बयान से अपनी एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिससे यह संदेश गया है कि अपनी क्षेत्रीय अखंडता के मामले में भारत किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा।

प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का अर्थ समझाते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ऐसी इक्वल एरिया मानचित्रण पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिनमें महाद्वीपों के भूभागों के आपसी क्षेत्रफल का वास्तविक अनुपात बना रहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव न तो किसी विशेष विश्व मानचित्र को अपनाता है और न ही उसे प्रमाणित करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नाम समेत राजनीतिक मानचित्रण से भी संबंधित नहीं है। यानी, यह भौगोलिक प्रस्तुति पर केंद्रित है, न कि राजनीतिक दावों पर। टोगो द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 164 देशों ने मतदान किया। एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन ने मतदान में भाग नहीं लिया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके खिलाफ एकमात्र मत दिया। भारत का यह रुख उसके संप्रभु हितों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जम्मू-कश्मीर : स्टाइपेंड बढ़ोतरी के लिए एसकेआईएमएस इंटर्न की भूख हड़ताल

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बेमिना स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) कॉलेज के मेडिकल इंटर्न ने अपनी इंटर्नशिप स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एमबीबीएस 2021 बैच के ये इंटर्न अपने विरोध प्रदर्शन को तेज कर स्टाइपेंड वृद्धि संबंधी प्रशासन के एक औपचारिक लिखित आदेश पर अड़े हुए हैं। इंटर्नों ने कहा कि बार-बार की बातचीत और मौखिक आश्वासनों के बावजूद स्टाइपेंड बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक लिखित आदेश नहीं मिलने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। उनका रुख साफ है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा करने वाला औपचारिक लिखित आदेश जारी नहीं होता और प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई जाती, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन और भरोसे के आधार पर वे अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लेने वाले हैं। विरोध कर रहे इंटर्न ने बताया कि उनकी मांग न्याय, सम्मान और इंटर्न डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले काम एवं जिम्मेदारियों के बदले उचित मुआवजे से जुड़ी है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर तुरंत ध्यान देने और लिखित व आधिकारिक आदेश के जरिए गतिरोध को दूर करने की अपील की। यह भूख हड़ताल जम्मू-कश्मीर में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के उस व्यापक आंदोलन का अगला चरण है, जिसमें वे अपनी मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड 12,300 रुपये है। इंटर्न का कहना है कि 2019 के बाद से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। एसकेआईएमएस बेमिना के इंटर्न ने दोहराया है कि भूख हड़ताल का मकसद बातचीत की प्रक्रिया को खत्म करना नहीं, बल्कि मामले का जल्द समाधान निकालना है।

8 सितंबर को 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि मानसून अब धीरे-धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, लेकिन पूर्वी और मध्य भारत के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश का दौर बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 8 सितंबर के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में 8 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे पीछे मुड़कर देखने भारत नहीं भेजा, मुझे यहां काम पूरा करना है- गोर

बेंगलुरु। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के सीएम डीके शिवकुमार के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। बेंगलुरु में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने कहा कि 250 साल यह जश्न मनाने लायक है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए भारत नहीं भेजा है। उन्होंने मुझे यहां काम पूरा करने और आगे देखने के लिए भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजदूत गोर ने कहा कि हमारा ध्यान इसी पर है कि अमेरिका और भारत में असली लोगों के लिए असली नतीजे निकलें और दोनों देशों को फायदा मिले। गोर ने कहा कि इस बारे में बात करने के लिए बेंगलुरु सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यह शहर निर्माण करता है। यह काम पूरा करता है। यह इंतजार भी नहीं करता और यहां का प्रशासन भी ऐसा ही है। गोर ने आगे कहा कि यही भावना ट्रंप अमेरिका-भारत संबंधों में लेकर आए थे। गोर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक राजदूत के तौर पर मैंने भी हर दिन इसी भावना को लाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आज रात मुझे ट्रस्ट फेलोशिप शुरू करने में मदद करने पर गर्व है। अमेरिकी राजदूत ने बताया कि यह एक नई साझेदारी है जो शीर्ष अमेरिकी और भारतीय शोधकर्ताओं को उन तकनीकों पर काम करने के लिए एक साथ लाती है, जो इस सदी को परिभाषित करेंगी वो हैं एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक।

सीएम विजय की डीएमके को चेतावनी : महिलाओं के अपमान और भ्रष्टाचार पर नहीं होगी नरमी

चेन्नई,। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विपक्षी पार्टी डीएमके पर कड़ा प्रहार कर चेतावनी दी कि महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस विभाग के लिए अनुदान की मांग पर विधानसभा में हुई बहस के जवाब में, मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया, साथ ही पार्टी के उन पदाधिकारियों की आलोचना की जिन्होंने कथित तौर पर उन लोगों के खिलाफ बयान दिए थे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। सीएम विजय ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन महिलाओं के प्रति अभद्र या अपमानजनक टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर विस्तार से बात कर मुख्यमंत्री विजय ने दावा किया कि उनके पास आधिकारिक रिकॉर्ड और विधानसभा लाइब्रेरी में मौजूद दस्तावेजों और नतीजों के प्रमाण हैं। उन्होंने डीएमके को सबूत मांगने के बजाय आरोपों का जवाब देने की चुनौती दी। उन्होंने 1977 की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का जिक्र कर वीरनम पाइपलाइन परियोजना में कथित गड़बड़ी और ठेके देने में कमीशन मांगने का आरोप लगाया। सीएम विजय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) का इस्तेमाल एक विशिष्ट कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों का हवाला देकर उन्होंने पार्टी फंड के नाम पर पैसे जुटाने और कुछ लेन-देन में 7.5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन लेने की बात कही। उन्होंने पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी पर भी अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने डीएमके अध्यक्ष और पूर्व सीएम एम.के. स्टालिन और पार्टी नेता उदयनिधि स्टालिन का नाम लिया, आरोप लगाया कि वे और पूर्व मंत्री से जुड़े अन्य अधिकारी इन कथित लेनदेन में शामिल थे। हालांकि, मुख्यमंत्री विजय द्वारा लगाए गए ये सभी आरोप अभी भी अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं और केवल आरोप ही बने हुए हैं। अपनी बात समाप्त कर सीएम विजय ने कहा कि वे राजनीति में पद या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने सी.एन. अन्नादुरई, एम.जी. रामचंद्रन और एन.टी. रामाराव जैसी हस्तियों की विरासत का उल्लेख कर विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक विरोध के बावजूद अंततः जनता का प्यार ही विजयी होगा।

शौर्य चक्र विजेता की माँ 22 साल बाद सम्मान लौटाने को मजबूर

नई दिल्ली। 22 सालों तक सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने और वादों के अधूरा रहने से आहत 80 वर्षीय सावित्री देवी ने बड़ा और भावुक निर्णय लिया है। मणिपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए अपने शौर्य चक्र विजेता बेटे, पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट विवेक सक्सेना को मिले सम्मान को वे अब उत्तरप्रदेश सरकार को लौटाने को मजबूर हैं। नई दिल्ली में उनकी यह घोषणा सरकारी संवेदनहीनता और नौकरशाही की उदासीनता को दिखाती है।

दरअसल विवेक सक्सेना 8 जनवरी 2003 को शहादत को प्राप्त हुए थे, जिसके बाद उन्हें शौर्य चक्र और राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। उनकी शहादत के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने परिवार को एक मेमोरियल पार्क और ग्रामीण कोटे के तहत ज़मीन देने का वादा किया था। दो दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए। सावित्री देवी ने अपने बड़े बेटे रंजीत के साथ लखनऊ में आयोजित शिकायत निवारण कार्यक्रम में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

रंजीत के अनुसार, 2016 में तत्कालीन ज़िला मजिस्ट्रेट राज शेखर के हस्तक्षेप के बाद ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बाद में परिवार से उत्तर प्रदेश में मूल निवासी होने का सबूत मांगा गया। रंजीत ने बताया कि परिवार यहीं पला-बढ़ा, यहीं शिक्षा मिली और उनके भाई की यादगार चीज़ें भी एयर फ़ोर्स स्टेशन मेमोरा में हैं, फिर भी उनसे एक हलफ़नामा मांगा गया।

फिर सक्रिय हुए चंपत राय, बोले- कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद चौतरफा आलोचनाओं का सामना करने वाले और महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय एक बार फिर सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। चोरी मामले के बाद पहली बार उन्होंने तीर्थ यात्री सेवा केंद्र का दौरा किया और कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, यहां तक कहा कि कोई परेशानी हो तो उन्हें बताएं। इस दौरान उनके साथ पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। एक घंटे तक सेवा केंद्र में रहकर उन्होंने कर्मचारियों का हालचाल जाना। चंपत राय की सक्रियता ऐसे समय में देखने को मिली है जब श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को नया पूर्णकालिक महासचिव और पहला सीईओ मिल गया है।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब जून में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठाया था। शुरुआत में चंपत राय ने इन आरोपों को गलत बताया था, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव और एसआईटी जांच में चोरी की पुष्टि होने के बाद यह साफ हो गया कि उन्हें अखिलेश के आरोपों से पहले ही चोरी का पता था। लाखों रुपयों की बरामदगी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने तो इस पूरी घटना को डाका तक करार दिया था। इन गंभीर आरोपों के चलते चंपत राय चौतरफा घिर गए थे और उन्होंने अंततः महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच, अलग-अलग शिकायतों और आरोपों के चलते राम मंदिर की व्यवस्थाओं से हटाए गए तीन कर्मचारियों, शहीद कारसेवक वासुदेव गुप्ता के बेटे संदीप गुप्ता, केडी तिवारी और बजरंग पाठक की भी वापसी हो गई है। संदीप गुप्ता को एक विदेशी महिला की शिकायत के बाद तीर्थ यात्री सेवा केंद्र की लॉकर व्यवस्था से हटा दिया गया था। विदेशी महिला ने लॉकर में सामान रखने को लेकर हुई कहासुनी के बाद ट्रस्ट को शिकायत पत्र सौंपा था। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने संदीप को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें काम से हटा दिया गया था। शहीद कारसेवक के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए संदीप को मंदिर में काम दिया गया था।

जनता के लिए आधार अनिवार्य, लेकिन खुद के लिए छूट चाह रहे केंद्रीय कर्मचारी

नई दिल्ली। एक ओर केंद्र सरकार 3,100 से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं और 360 से ज्यादा सार्वजनिक सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारी अपने स्वयं के सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड को आधार से जोड़ने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। यह स्थिति उन अधिकारियों के दोहरे मापदंड को दिखाती हैं, जो देश के सबसे गरीब नागरिकों से हर योजना के लिए आधार की मांग करते हैं।

सीजीएचएस के दायरे में केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, मौजूदा और पूर्व सांसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और दिल्ली में मान्यता प्राप्त पत्रकार शामिल हैं। केंद्र सरकार स्वयं यह स्पष्ट कर चुकी है कि आधार से योजनाओं को जोड़ने से लक्षित, पारदर्शी और लीक-प्रूफ वितरण सुनिश्चित होता है, जिससे डुप्लिकेट और अयोग्य लाभार्थियों की पहचान आसान होती है। इसके बावजूद, सीजीएचएस के तहत मृत पेंशनभोगियों या अपात्र हो चुके आश्रितों को हटाने के लिए कोई वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया नहीं होती, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है। गौरतलब है कि पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) और रेलवे की स्वास्थ्य सेवा में आधार लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार ने जून 2015 से सीजीएचएस के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाने के कई प्रयास किए, लेकिन कर्मचारियों के तीखे विरोध के कारण हर बार अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी कड़ी में, जुलाई 2024 में भी सीजीएचएस लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी (आभा आईडी) से जोड़ने के आदेश को अगले आदेश तक स्थगित करना पड़ा।परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था पूरी तरह स्वैच्छिक बनी हुई है, जबकि रोजगार गारंटी योजना के तहत 300 रुपये की न्यूनतम दिहाड़ी पाने वाली गरीब महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि सीजीएचएस एक अंशदायी योजना है, न कि कोई मुफ्त कल्याणकारी योजना, जिसमें वे स्वयं योगदान करते हैं। हालांकि, हकीकत यह है कि सीजीएचएस के कुल खर्च का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा भारत की संचित निधि से आता है, और कर्मचारियों का योगदान एक मामूली हिस्सा होता है। यदि अन्य योजनाओं से तुलना करें, सीजीएचएस का प्रति व्यक्ति खर्च सबसे अधिक है, जो इस दोहरे मापदंड पर और भी सवाल उठाता है।

गहरी खुदाई और बारिश के चलते 700 साल पुराना महाकाल द्वार गिरा

उज्जैन। महाकाल मंदिर से रामघाट जाने वाले प्राचीन मार्ग पर स्थित करीब 700 साल पुराना ऐतिहासिक महाकाल द्वार शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय द्वार के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा और जनहानि टल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह के समय स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महाकाल द्वार के ठीक आसपास निर्माण कार्य के लिए गहरी खुदाई (डीप एक्सकेवेशन) की जा रही थी। पिछले दो-तीन दिनों से उज्जैन में लगातार बारिश होने के कारण जमीन में नमी बढ़ गई थी।

पद्मेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव
बालाघाट एक्सप्रेस

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

थाने की चारदीवारी में इंसानियत हुई शर्मसार!

चोरी की पूछताछ के नाम पर पुलिसकर्मियों ने की कथित गर्भवती की पिटाई, पति को भी पीटा, महिला के गर्भवती होने की बात सामने आने से मामला और गंभीर, एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, डीएसपी के नेतृत्व में बिठाई एसआईटी जांच

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। किरनापुर थाने में चोरी के मामले की पूछताछ के दौरान एक दंपती के साथ कथित रूप से अमानवीय मारपीट किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर पति-पत्नी को थाने लाकर प्रताड़ित करने, कपड़े उतारकर मारपीट करने और चोरी कबूल करवाने के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए किरनापुर थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक दामेन्द्र तुरकर, प्रधान आरक्षक आशीष बघेल, आरक्षक कपिल बघेल और महिला आरक्षक मेघा टेकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र भेज दिया है।

अब एसआईटी कर रही मामले की जांच

उधर प्रकरण सामने आते ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर के नेतृत्व में चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। टीम को पूरे घटनाक्रम की जांच कर दो सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।फिलहाल पुलिस ने चार कर्मचारियों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। अब एसआईटी की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह तय होगा कि थाने में लगाए गए गंभीर आरोपों की वास्तविकता क्या है और आगे किन लोगों पर कार्रवाई होती है।

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला 21 अगस्त को सामने आई चोरी की घटना से जुड़ा है। बताया गया कि किरनापुर थाना क्षेत्र के पालडोंगरी के ग्राम नागुटोला निवासी शीला कारमेगे, अलका गिरिया के साथ किरनापुर स्थित पोस्ट ऑफिस गई थी। यहां बैंक खाते से एक लाख रुपये निकालने के बाद वह रकम गिन रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने नोटों के बंडल से रबर निकालकर रुपये गिनने की बात कही। इसी बीच अलका गिरिया के बैग से कथित तौर पर 50 हजार रुपये गायब हो गए।घटना की शिकायत शीला कारमेगे ने किरनापुर थाने में दर्ज कराई थी। इसी मामले में पुलिस ने कैलाश चौधरी और उसकी पत्नी सावित्री चौधरी को पूछताछ के लिए 2 सितंबर को थाने बुलाया था।

पूछताछ से शुरू हुआ मामला, मारपीट के आरोप तक पहुंचा

परिजनों का आरोप है कि दंपती को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया, लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि चोरी कबूल करवाने के लिए पति-पत्नी पर दबाव बनाया गया और महिला के साथ भी कथित तौर पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया।उधर सोमवार को रिटायर्ड फौजी तोषण राहंगडाले और कैलाश चौधरी के भाई रवि चौधरी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम शिकायत सौंपी। शिकायत में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई।

2 माह की गर्भवती बताई जा रही महिला

पीड़िता सावित्री चौधरी के करीब दो माह की गर्भवती होने की बात परिजनों ने कही है। देवर रवि चौधरी का आरोप है कि गर्भवती होने के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। उन्होंने महिला के शरीर और पैरों पर चोट के निशान होने का दावा करते हुए पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।परिजनों का कहना है कि महिला गर्भावस्था की स्थिति में है तो पूछताछ के दौरान उसके साथ किया गया कथित व्यवहार बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की मेडिकल जांच कराने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बिना पुष्टि के पति-पत्नी को आरोपी बनाने का आरोप

परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कैलाश चौधरी घटना के समय मवेशी चराने गया था, जबकि सावित्री घर पर कपड़े सिल रही थी। उनका दावा है कि दोनों के संबंध में पुलिस को पर्याप्त जांच-पड़ताल करनी चाहिए थी, लेकिन किसी के कथित बयान के आधार पर उन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान दोनों पर चोरी का आरोप स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस की एसआईटी जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि थाने में वास्तविक घटनाक्रम क्या था और आरोपों में कितनी सच्चाई है।

शिकायत मिलते ही एसपी का एक्शन

मामले की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इसे गंभीरता से लेते हुए चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। उपनिरीक्षक दामेन्द्र तुरकर, प्रधान आरक्षक आशीष बघेल, आरक्षक कपिल बघेल और महिला आरक्षक मेघा टेकाम को निलंबन के बाद रक्षित केंद्र भेजा गया है।

2 सप्ताह में जांच कर एसआईटी देगी रिपोर्ट

उधर पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के बाद एसपी ने मामले की जांच के लिए डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर के नेतृत्व में चार सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। जांच टीम को पूरे मामले की परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई, पूछताछ के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और लगाए गए मारपीट के आरोपों की जांच कर दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

अब जांच में सामने आएगा सच

इस पूरे मामले में अब एसआईटी की जांच अहम मानी जा रही है। पुलिस हिरासत अथवा थाने में पूछताछ के दौरान क्या हुआ, दंपती को किस आधार पर थाने लाया गया, पूछताछ की प्रक्रिया क्या थी, मारपीट के आरोपों में कितनी सच्चाई है और चोरी के मामले से दोनों का कोई संबंध है या नहीं— इन तमाम बिंदुओं की जांच की जाएगी।

परिजनों ने राष्ट्रपति तक से लगाई इंसाफ की गुहार

उधर परिजनों ने मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग तथा पूर्व विधायक हीना कावरे को भी शिकायत भेजकर हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है।

तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर, अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए,एसपी ले जिम्मेदारी- अनुभा

इस पूरे मामले में विधायक अनुभा मुंजारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि अत्यन्त अमानवीयता का व्यवहार किरनापुर थाने की पुलिस ने इनके साथ की है जो अत्यन्त निंदनीय है । इन पुलिस कर्मियों को जो बेशर्म और राक्षसी प्रवृति के हो चुके हैं इनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करके इन पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।वही पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस पूरे शर्मनाक प्रकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए। मुझे इस घटना को जानकर अत्यन्त दुख हुआ।बेगुनाह गरीब जनता पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

खेत में मोटर पाइप कसते समय करंट की चपेट में आया युवक की मौत

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। खैरलांजी थानाक्षेत्र के ग्राम कुम्हली में सोमवार को कृषि कार्य के दौरान विद्युत करंट की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब युवक अपनी मां के साथ खेत में लगी मोटर के पास ट्यूब-पट्टी पाइप कस रहा था। खैरलांजी पुलिस में मृतक शैलेश पिता राधेश्याम बावने 28 वर्ष का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कुम्हली निवासी राधेश्याम बावने अपने परिवार के साथ खेती-किसानी करते हैं। परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं तथा सभी की शादी हो चुकी है। करीब एक वर्ष पूर्व राधेश्याम लकवे से पीडित हो गए थे और वर्तमान में लकड़ी के सहारे चलते-फिरते हैं।बताया गया कि 7 सितंबर की सुबह राधेश्याम बावने अपने बेटे शैलेश बावने और पत्नी सुशीला के साथ खेत में निंदाई करने तथा मोटर पंप के माध्यम से खेत में पानी चलाने पहुंचे थे। खेत में मोटर पंप के लिए स्थायी विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। करीब 11 से 11:30 बजे के बीच शैलेश अपनी मां के साथ मोटर के पास ट्यूब-पट्टी पाइप कस रहा था। इसी दौरान वह विद्युत करंट की चपेट में आ गया और जमीन पर गिर पड़ा।शैलेश को करंट लगते देख उसकी मां सुशीला ने शोर मचाकर आसपास मौजूद लोगों को सूचना दी। खेत में निंदाई कर रही चार महिलाएं तत्काल मौके पर पहुंचीं और विद्युत तार को हटाया। इसके बाद शैलेश को उठाकर खेत की मेड़ पर लाया गया। उस समय उसकी सांसें चल रही थीं। लेकिन कुछ देर बाद उसकी सांसें थम गईं।घटना की सूचना मृतक के पिता राधेश्याम बावने ने खैरलांजी थाने में दी। सूचना मिलने पर पुलिस ग्राम कुम्हली पहुंची और शैलेश के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद खैरलांजी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया।खैरलांजी पुलिस ने इस मामले में धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

कृषि कार्य के दौरान विद्युत सुरक्षा जरूरी

खेतों में मोटर पंप और विद्युत उपकरणों के उपयोग के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। बिजली के तार, मोटर पंप या पाइप को छूने से पहले विद्युत कनेक्शन बंद करना जरूरी है। विशेषकर खेतों में नमी होने के कारण करंट फैलने का खतरा अधिक रहता है। किसानों को कृषि कार्य के दौरान विद्युत सुरक्षा संबंधी सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

वाणिज्य विषय में उत्कृष्ट शिक्षण के लिए डॉ. पूनम मिश्रा राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। इसी क्रम में वाणिज्य विषय में उल्लेखनीय शैक्षणिक योगदान के लिए डॉ. पूनम मिश्रा, उच्च माध्यमिक शिक्षक को राज्यपाल पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि उनके शिक्षण के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। मध्यप्रदेश में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में प्रदेश के 33 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी सम्मान समारोह में डॉ. पूनम मिश्रा को वाणिज्य विषय में उत्कृष्ट शिक्षण एवं शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉ. पूनम मिश्रा ने विद्यार्थियों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि विकसित करने के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और नवाचारपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया। उनके प्रयासों से विद्यार्थियों को विषय को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय उसे व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर मिला। शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान को इसी कारण महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि विद्यार्थियों की सफलता और उनके भविष्य को बेहतर दिशा देना है। राज्य स्तरीय सम्मान मिलने से उनके शैक्षणिक कार्यों को नई पहचान मिली है। यह सम्मान उन्हें आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। डॉ. पूनम मिश्रा की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, सहकर्मियों, विद्यार्थियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षकों का कहना है कि उनका यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर प्रयासों की भी पहचान है। यह सम्मान अन्य शिक्षकों को भी समर्पण, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए प्रेरित करेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट